दैनिक जागरण
अभाव की स्थिति भी बहुत कुछ सिखाती है

प्रधानमंत्री की चिंतन बैठक

प्रधानमंत्री की ओर से अपनी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ दो दिवसीय चिंतन बैठक यह रेखांकित कर रही है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श होने जा रहा है। इनमें से एक विकसित भारत के लिए आवश्यक कदमों पर अमल करना और सुधारों को आगे बढ़ाना है। इस बैठक में योजनाओं की प्रगति, नीतियों के क्रियान्वयन और मंत्रालयों के बीच तालमेल जैसे विषयों पर भी चर्चा संभावित है। जो भी हो, सरकार के कामकाज को और प्रभावी बनाना समय की मांग है। इसके लिए नौकरशाही को अपना रुख-रवैया बदलना होगा। इससे इन्कार नहीं कि मोदी सरकार की ओर से विकास और जनकल्याण संबंधी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन कार्यों की गति और गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करके ही 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस लक्ष्य को आसान बनाने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर गंभीरता से ध्यान दे। इनमें एक मोर्चा है शहरों की सूरत संवारने का। चूंकि शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, इसलिए उनके ढांचे में सुधार के साथ नागरिक सुविधाओं में बेहतरी समय की मांग है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि समृद्धि बढ़ने के साथ एक ऐसा वर्ग उभर आया है, जिसे सब कुछ गुणवत्तापूर्ण चाहिए। इनमें नागरिक सुविधाओं से लेकर उपभोक्ता सामग्री एवं आमोद-प्रमोद के साधन भी शामिल हैं। ध्यान रहे कि देशों का वैभव उनके शहरों से भी प्रकट होता है। शहरों को साधन संपन्न बनाने का काम प्रमुखता से होना चाहिए, ताकि वे तनाव मुक्त जीवन का जरिया बन सकें।

शहरों की सूरत संवारने के साथ ही सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यह ठीक नहीं कि तमाम प्रयासों के बाद भी कृषि की उत्पादकता बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। एक अन्य मोर्चा शिक्षा का है। यह ठीक है कि नई शिक्षा नीति पर अमल हो रहा है, लेकिन सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। ऐसी ही चुनौती युवाओं को उपयुक्त कौशल से लैस करने की भी है। हमारे युवा डिग्री तो हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन वे किसी कौशल से लैस नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि इससे ही रोजगार की चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। किसी भी सरकार का लक्ष्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना और जीवन को आसान बनाना होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तब आसानी से होती है, जब नियम-कानूनों का सही से पालन होता है।

सख्ती आवश्यक

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से कक्षा दो की छात्रा की मौत के कथित मामले में तत्काल किसी निष्कर्ष पर सीधे पहुंचना कठिन है। यह तो जांच का विषय है और उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। परिवार के लोगों ने चूंकि बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए मौत के कारण को लेकर संदेह बना रहेगा। वैसे स्कूल अवधि में जिस समय बच्ची की तबीयत बिगड़ी, वहां से म्यूजिक सिस्टम के गुजरने के साक्ष्य मिले हैं। विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों ने तेज आवाज महसूस की। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि अत्यधिक तेज ध्वनि से हार्मोन का स्तर बढ़ने से हार्ट अटैक की आशंका बनती है। अस्पताल, स्कूल, न्यायालय जैसे शांत क्षेत्र में विशेष प्रतिबंध लागू होते हैं। असुविधा तब होती है, जब ध्वनि मानक के ऐसे नियम कागजों पर रह जाते हैं। पुलिस-प्रशासन को इनका पालन सुनिश्चित कराने के साथ उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। समझना होगा कि आस्था की अभिव्यक्ति किसी दूसरे के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा न बने। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतनी तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बलरामपुर में जहां विद्यालय संचालित है, वहां इसका अनुपालन विसर्जन करने वाला समूह कर रहा था या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक आयोजनों में तेज ध्वनि का प्रसारण चिंता का विषय है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ताजा घटना प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है।

> नियम का जमीन पर दिखना भी आवश्यक है। ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो

अमेरिकी दबदबा बढ़ाने की कोशिश में ट्रंप

हर्ष वी. पंत

संयुक्त राष्ट्र के मंच से ट्रंप के संबोधन ने यही दर्शाया कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों एवं प्रतिद्वंद्वियों पर रणनीतिक दबाव और बढ़ा सकता हैं

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन एक अहम पड़ाव होता है कि यह महाशक्ति शेष विश्व को किस दृष्टि से देखती है। चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अपारंपरिक एवं अप्रत्याशित पहलुओं से भरा रहा है, इसलिए उनके संबोधन को लेकर उत्सुकता स्वाभाविक थी। ट्रंप का संबोधन उनके दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति के आधारभूत तर्कों की एक स्पष्ट और सटीक अभिव्यक्ति साबित हुआ। इसमें ट्रंप ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि अमेरिका केवल 'अपनी महानता की वापसी' की ओर ही नहीं लौट रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपनी शर्तों के अनुसार नया स्वरूप देने के प्रति संकल्पित भी है। उनका मूल संदेश उनकी चिरपरिचित शैली के अनुरूप ही था कि किसी संस्थागत आम सहमति के बजाय अमेरिकी सैन्य एवं आर्थिक सामर्थ्य ही वैश्विक शांति की प्रमुख संरक्षक होगी। ट्रंप ने जिस तरह दुनिया को खतरों, कमजोर संस्थाओं और रणनीतिक होड़ से घिरे परिदृश्य के रूप में चित्रित किया, उसमें 'शक्ति के जरिये शांति' महज एक नारा नहीं, बल्कि वाशिंगटन के वैश्विक दृष्टिकोण को समझने का एक व्यावहारिक ढांचा बनकर उभरा।

ट्रंप के भाषण में ईरान का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। उन्होंने तेहरान को दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक करार दिया और दोहराया कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। हालांकि उनकी आक्रामक बयानबाजी ने कूटनीति और टकराव दोनों ही विकल्पों को खुला रखा। जहां उन्होंने दो-टूक कहा कि ईरान के सामने विकल्प एकदम स्पष्ट हैं कि या तो वह वाशिंगटन की स्वीकार्य शर्तों पर समझौता करे या फिर अप्रत्याशित सैन्य बल के प्रहार का सामना करने को तैयार रहे। इस तीखी बयानबाजी के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों से इतर अमेरिकी और ईरानी राजनयिकों में संवाद भी जारी रहा। यह ट्रंप की सौदेबाजी पर केंद्रित कूटनीति को ही उजागर करता है। उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध को लेकर भी कड़ा रवैया दिखाया। वेनेजुएला, निकोलस मादुरो और तेल संसाधनों के आलोक में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' सरीखे नजरिये से उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन इस क्षेत्र को ऐसे दायरे के रूप में देख रहा है, जहां अमेरिकी वर्चस्व न केवल स्थापित होना चाहिए, बल्कि उसे सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए। उन्होंने क्यूबा को एक विफल कम्युनिस्ट देश के रूप में चित्रित किया।

अवधेश राजपूत

कुछ समय से ट्रंप की छवि ऐसे व्यक्ति की बन गई है, जो अपनी पीठ स्वयं थपथपाने को लेकर कोई संकोच नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उन्होंने यही दोहराया कि एक के बाद एक युद्ध, टकराव और तनाव दूर करने में उनकी कितनी अहम भूमिका रही। इस कड़ी में उन्होंने कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, रवांडा-कांगो, भारत-पाकिस्तान, आर्मेनिया-अजरबैजान और गाजा के विवादों को ऐसे उदाहरणों के रूप में गिनाया, जिनका उनके शासनकाल में स्थायी समाधान हुआ या युद्धविराम संभव हो सका। आर्कटिक और ग्रीनलैंड ट्रंप की नई नीति में अंतर्निहित भू-राजनीतिक दृष्टिकोण के सबसे मुखर उदाहरण के रूप में सामने आए। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और डेनमार्क एवं ग्रीनलैंड के साथ नए सुरक्षा समझौतों पर ट्रंप का आग्रह आर्कटिक की बढ़ती सामरिक अहमियत का परिचायक रहा। स्पष्ट है कि अमेरिका के लिए यह क्षेत्र अब एक सीमांत परिधि से परे बृहद-शक्ति प्रतिस्पर्धा, समुद्री आवाजाही, संवेदनशील अवसंरचना और उत्तरी अमेरिका की संप्रभु रक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

ट्रंप का संबोधन शीतयुद्ध के बाद आकार लेने वाली वैश्विक व्यवस्था की स्थापित मान्यताओं पर एक तीखा प्रहार भी था। वे संयुक्त राष्ट्र को ऐसी संस्था मानते हैं, जो कट्टर वामपंथी एजेंडे के चंगुल में फंसी हुई है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कराधान और साझा नियामक ढांचे थोपने से जुड़ी कोशिशों को भी आड़े हाथों लिया। वैश्विक कार्बन टैक्स का विरोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों को सिरे से खारिज करना उनकी उसी नीति को ही दर्शाता है कि ऐसे सभी मामलों में निर्णयन को लेकर वाशिंगटन की पूर्ण स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, जिन्हें अमेरिका अपनी राष्ट्रीय शक्ति की धुरी मानता है। मानवाधिकार परिषद और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर ट्रंप के तीखे हमलों ने भी यह साफ कर दिया कि वे ऐसी संस्थाओं के प्रभाव एवं अधिकार को किस हद तक अस्वीकार करते हैं। उनके संबोधन में तेल संसाधनों, विवादों के समाधान और ड्रग कार्टेल्स पर नकेल कसने संबंधी कई दावे संदेहास्पद भी रहे। आखिर किसी संघर्ष के 'समाप्त' होने का एलान करने और एक स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ऊर्जा क्षेत्र में वर्चस्व के दावों को भी राजनीतिक बयानबाजी के बजाय वास्तविक वैश्विक भंडारों और उत्पादन के धरातल पर परखे जाने की जरूरत है।

कुल मिलाकर, इस संबोधन की अहमियत किसी एक दावे में नहीं, बल्कि उस समग्र दृष्टिकोण में निहित है, जिसने इसे आकार दिया। इसमें ट्रंप ने एक ऐसे अमेरिका की तस्वीर पेश की, जो अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति सशंकित भी। साथ ही किसी बाहरी बंदिश को स्वीकार करने को तैयार नहीं और अपने रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पहले से कहीं अधिक तत्पर है। इस पूरे भाषण का मर्म अमेरिकी वर्चस्व की नए सिरे से पुनर्स्थापना पर केंद्रित रहा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसके दूरगामी और गहरे निहितार्थ हैं। अमेरिका रणनीतिक दबाव को ही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का प्राथमिक आधार समझता है। संभव है कि वह अपने मित्र राष्ट्रों, बहुपक्षीय मंचों और प्रतिद्वंद्वियों पर ऐसा दबाव और बढ़ाए। सवाल यह नहीं है कि क्या अमेरिका आज भी एक महाशक्ति है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह अपनी शक्ति का एक सुदृढ़ एवं दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में कैसे उपयोग करेगा।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

यूपीआइ तंत्र के हित में है एमडीआर

अशोक चंद

यूपीआइ भुगतान पर कुछ शुल्क लगने के बाद भी नकदी की तरफ लौटने का कोई खतरा नहीं दिख रहा हैं

यूपीआइ यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वह सिस्टम है, जिसकी वजह से हम मोबाइल से तुरंत किसी को भी पैसे भेज या मंगवा सकते हैं। इसे 2016 में एनपीसीआइ (नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया) ने शुरू किया था और तब सिर्फ 44 बैंक इससे जुड़े थे। आज 750 से अधिक बैंक इससे जुड़े हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल बहुत कम था, लेकिन आज हर महीने 2,400 करोड़ से भी ज्यादा लेनदेन इसी के जरिये हो रहे हैं। यानी हर दिन करीब 80 करोड़ से अधिक बार लोग यूपीआइ से पैसे भेज या ले रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं। गांव की छोटी दुकान, ठेले वाला, आटो चालक आदि सब यूपीआइ क्यूआर कोड से जुड़ चुके हैं। इसने नकदी पर निर्भरता को कम किया है और बैंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया है, जिनके पास पहले कभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं था। इसने छोटे व्यापारियों को बिना किसी भारी उपकरण या शुल्क के डिजिटल भुगतान अपनाने का मौका दिया। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यूपीआइ ने भुगतान की लागत को शून्य कर दिया, जिससे औपचारिक आर्थिकी का दायरा बढ़ा और वित्तीय समावेशन को नई गति मिली। यूपीआइ सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आर्थिकी की रीढ़ है।

यूपीआइ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहा गया है। आइएमएफ ने जून 2025 में यूपीआइ को दुनिया का सबसे बड़ा रीयल-टाइम भुगतान तंत्र बताया था, जो विश्व का करीब 49 प्रतिशत रीयल-टाइम डिजिटल लेनदेन संभालता है-ब्राजील, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी अधिक। आज भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मारीशस और मालदीव समेत करीब एक दर्जन देश यूपीआइ को अपना चुके हैं और कई देश अपने डिजिटल भुगतान ढांचे को इसी माडल पर बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब इसी मुफ्त सिस्टम में 15 अक्टूबर से मामूली शुल्क लगने जा रहा है, जिसे एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। एनपीसीआइ के इस फैसले ने हलचल पैदा की है, लेकिन असली तस्वीर समझने के लिए इसे आंकड़ों और अर्थशास्त्र की नजर से देखना जरूरी है। 2,000 रुपये तक के यूपीआइ भुगतान पूरी तरह मुफ्त ही रहेंगे और यही रकम कुल भुगतान (यानी जब किसी दुकानदार को यूपीआइ से पैसे दिए जाते हैं) का 95 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा है। मतलब सौ में से 95 से ज्यादा बार जब आप यूपीआइ से पैसे देंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा।

यूपीआइ से वित्तीय समावेशन को मिली तेज गति। फाइल

यूपीआइ भुगतान पर शुल्क सिर्फ उन पांच प्रतिशत से भी कम लेनदेन पर लगेगा जो 2,000 से अधिक के होंगे और वह भी सिर्फ बड़े दुकानदारों-कारोबारियों पर। जो छोटे दुकानदार महीने में एक लाख रुपये तक यूपीआइ क्यूआर कोड से कमाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए सब कुछ पहले जैसा मुफ्त ही रहेगा। दर भी बहुत मामूली रखी गई है-सिर्फ 0.4 प्रतिशत और वह भी 75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 तक। यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि दुकानदार से लिया जाएगा यानी 3,000 की खरीदारी पर दुकानदार को सिर्फ 12 रुपये का एमडीआर देना होगा। 1,00,000 की खरीदारी पर 0.4% के हिसाब से 400 बनते हैं, लेकिन दुकानदार से अधिकतम 300 ही लिया जाएगा। रेलवे टिकट, बीमा प्रीमियम, बिजली-पानी बिल, पेट्रोल पंप और स्कूल-कालेज की फीस आदि पर तो और भी राहत है।

भारत में क्रेडिट कार्ड पर दुकानदारों को आमतौर पर 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता है, जबकि डेबिट कार्ड पर यह करीब 0.9 प्रतिशत तक जा सकता है। इस हिसाब से यूपीआइ की 0.4 प्रतिशत दर अब भी सबसे सस्ती रहेगी-क्रेडिट कार्ड से चार-छह गुना कम और डेबिट कार्ड से भी काफी कम। इसका मतलब है कि दुकानदारों के पास डिजिटल भुगतान अपनाते रहने की वजह बनी रहेगी और नकदी की तरफ लौटने का खतरा नहीं बढ़ेगा। बाकी बड़े देशों से तुलना करें तो भारत की यह दर वाकई कम ठहरती है। चीन में अलीपे जैसे मोबाइल-वालेट दुकानदारों से 0.6 प्रतिशत तक शुल्क लेते हैं यानी यूपीआइ से भी ज्यादा, जबकि वहां भी लेनदेन की संख्या भारत जैसी ही बहुत बड़ी है। ब्राजील में डेबिट कार्ड पर एक प्रतिशत शुल्क है। अमेरिका में कोई सीमा तय नहीं है और क्रेडिट कार्ड की फीस अक्सर 2 से 3 प्रतिशत तक चली जाती है, जिसकी शिकायत वहां के छोटे दुकानदार बरसों से करते आए हैं। इन सबकी तुलना में भारत की 0.4 प्रतिशत दर बहुत ही कम बैठती है।

असली सवाल शुल्क की दर से ज्यादा उसकी वजह का है। यूपीआइ पर हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च सिर्फ सर्वर, साइबर सुरक्षा और तकनीकी ढांचे पर आता है। कोई भी सुविधा हमेशा मुफ्त नहीं चल सकती। जब कोई सुविधा बिल्कुल मुफ्त होती है तो अक्सर सिर्फ बड़ी कंपनियां ही लंबे समय तक घाटा झेल पाती हैं और नई-छोटी कंपनियों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल हो जाता है। एक मामूली शुल्क इस बाजार में और प्रतिस्पर्धा ला सकता है और नई तकनीक में निवेश को बढ़ावा दे सकता है।

(लेखक पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मन के बोझ से मुक्ति

हर मनुष्य के भीतर एक अदम्य आकांक्षा सदैव विद्यमान रहती है कि अपनी वर्तमान अवस्था से उन्नत एवं श्रेष्ठ स्थिति की ओर अग्रसर होना है। यह आकांक्षा मनुष्यता का मूल स्वभाव है। विडंबना यही है कि यह ऊर्जा बाल्यावस्था में तो उन्मुक्त प्रवाह के साथ प्रवाहित होती है, परंतु आयु में वृद्धि के साथ-साथ क्षीण होती चली जाती है। जहां इसे समय के साथ प्रगाढ़ होना चाहिए था, वहां यह निस्तेज पड़ जाती है। इसका मूल कारण है-मन की चंचलता और उसका निरंतर भटकाव।

मनुष्य का मन एक अनियंत्रित अश्व के समान है, जो क्षण-प्रतिक्षण नवीन दिशाओं में दौड़ लगाता रहता है। यह कभी अतीत की स्मृतियों में उलझता है, तो कभी आशंकाओं में डूब जाता है। इस निरंतर भटकाव से मन पर एक अदृश्य भार संचित होता चला जाता है-चिंताओं का भार, असफलताओं की छाया का भार। यह भार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें इसका आभास भी नहीं होता, किंतु यह हमारी संकल्प-शक्ति को कुंठित करता रहता है और जब यह भार असहनीय हो जाता है, तब हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व ही नकारात्मक विचारों के सघन कुहासे में विलीन हो जाते हैं। यहां एक शाश्वत सत्य उद्घाटित होता है कि हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति केवल उन्मुक्त मन से ही कर सकते हैं। जिस प्रकार आकाश में उड़ान भरने के लिए पक्षी को अपने पंखों को किसी बंधन से मुक्त रखना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन के किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को पूर्वाग्रहों, भय और नकारात्मकता से मुक्त रखना होगा। जीवन की सार्थकता इसी में निहित है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को क्षीण न होने दें। उसे निरंतर प्रज्वलित रखें, ताकि हम उन्मुक्त भाव से सशक्त हुए मन के माध्यम से अपने प्रत्येक स्वप्न की पूर्ति में प्रयासरत हो सकें।

ममता कुशवाहा

रोजगार में बदले ग्रामीण महिलाओं का हुनर

सीता

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना जरूरी हैं, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके

देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनके श्रम की कोई कीमत नहीं है। दिन की शुरुआत घर के काम से होती है और एक बड़ा हिस्सा खेत, पशुओं और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच गुजर जाता है। सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद उनके हाथ में अपनी कमाई नहीं होती है। वह परिवार की अर्थव्यवस्था को संभालने में लगातार योगदान देती हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों में उसकी भूमिका लगभग शून्य होती है। राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति भी इस तस्वीर को समझने में मदद करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 58.75 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की ग्रामीण साक्षरता दर 78.57 प्रतिशत थी। पिछले वर्षों में शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण समाज के कई हिस्सों में लड़कियों की पढ़ाई आज भी परिवार की प्राथमिकताओं में पीछे रह जाती है। जब किसी महिला के पास अपनी आमदनी नहीं होती, तो रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए भी उसे परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता केवल पैसे की कमी नहीं है। कई बार यह उसके अपने फैसले लेने की क्षमता को भी सीमित करती है। ऐसी स्थिति में अगर घर में उसके साथ हिंसा या किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो आर्थिक मजबूरी उसके सामने विकल्पों को और कम कर देती है। इसलिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना केवल परिवार की आय बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णयों में अधिक भागीदारी देने और कठिन परिस्थितियों में अपने लिए आवाज उठाने की क्षमता देने का भी सवाल है।

विडंबना यह है कि गांवों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान उन कामों में है, जिन्हें अक्सर काम ही नहीं माना जाता। महिलाएं खेतों में बीज बोने से लेकर निराई-गुड़ाई और फसल से जुड़े कई काम करती हैं। पशुपालन में चारा लाना, पशुओं की देखभाल, दूध निकालना और उससे जुड़े घरेलू कामों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हालिया जेंडर रणनीति में भी ग्रामीण महिलाओं की कृषि और विशेष रूप से पशुपालन में बड़ी भागीदारी दर्ज की गई है। फिर भी इन कार्यों से होने वाली आय पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। गांवों में महिलाओं के पास हुनर की कमी नहीं है और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता भी कम नहीं है। कमी है तो ऐसे अवसरों की, जो उनके काम को पहचान दे और उसे बाजार से जोड़ सके। यदि गांव की महिला को उसके घर और गांव के आसपास ही सम्मानजनक रोजगार मिल सके, तो उसके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह खुल सकती है।

(राजस्थान से जुड़ी लेखिका ग्रामीण आर्थिकी की जानकार हैं)

मेलबाक्स

नेता प्रतिपक्ष का अमर्यादित व्यवहार

'फूहड़ और विषाक्त होती राजनीति' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने देश की वर्तमान राजनीति के गिरते स्तर और भाषाई मर्यादा के उल्लंघन पर जो चिंता व्यक्त की है, वह पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए विचारणीय होनी चाहिए। इंदौर में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में आचरण न तो उनकी पदेन गरिमा के अनुरूप था और न ही राष्ट्रीय दल कांग्रेस की मर्यादा के अनुकूल। राहुल गांधी ने न केवल संवैधानिक पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाया, अपितु उस मानवीय संवेदना पर भी कुठाराघात किया जो एक कार्यक्रम में मां जैसी बुजुर्ग महिला के प्रति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने संस्कारवश सहज रूप से व्यक्त की गई थी। राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मर्यादा की सीमा रेखा लांघ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कभी भी राहुल गांधी के अमर्यादित व्यवहार को लेकर टीका-टिप्पणी नहीं की। इससे राहुल गांधी का मनोबल बढ़ता गया और उन्होंने अपने फूहड़पन और अमर्यादित व्यवहार को ही कांग्रेस की राजनीति का पर्याय बना दिया। भारत के विपक्षी दल कांग्रेस के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी कि उसके नेता को लोग गंभीरता से न लें।

डा.वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

महिला सुरक्षा का ध्यान

महज एक सप्ताह के भीतर बिहार के जमुई में कुछ मनचले युवकों द्वारा एक नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और अगवा करने का प्रयास न केवल निंदनीय है, बल्कि चिंता का विषय भी। क्या हमारी सड़कें और सार्वजनिक स्थल इतने असुरक्षित हो गए हैं कि आवाजाही भी खतरे में है? मनचले, शरारती तत्वों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें कानून का भी कोई डर नहीं है? यह हमारी कानून, न्याय प्रणाली और सरकारी तंत्र की विफलता ही है जो आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी और हिंसा जैसे अपराध होते हैं। हाल ही में दिल्ली में नकली पुलिसकर्मी बन धमका कर कुछ युवकों ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया। ये घटनाएं बेटियों को निडर, निर्भर, बेबाक, चुस्त और सोच समझकर किसी पर विश्वास करने पर जोर देती हैं। पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती आवश्यक है। महिलाओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, हिंसा और दुष्कर्म जैसे मामलों में सख्त सजा का प्रविधान ऐसे कृत्यों में कमी ला सकता है।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

संवाद की मर्यादा का पतन

बुधवार को 'फूहड़ और विषाक्त होती राजनीति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने सही कहा कि राजनीति में संवाद की मर्यादा का पतन और विरोधियों के प्रति बढ़ रही फूहड़ता केवल नेताओं या दलों का आपसी विवाद नहीं है, बल्कि यह पूरे लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक गंभीर संकट है। आज भारतीय राजनीति वैचारिक बहसों और नीतिगत विमर्शों से कोसों दूर जा चुकी है। संवाद की जगह अमर्यादित टिप्पणियों, व्यक्तिगत हमलों और फूहड़ता ने ले ली है। कांग्रेस और राहुल गांधी के मंचों पर स्टैंड-अप कामेडी के बहाने प्रधानमंत्री, उनकी विदेश नीति और यहां तक कि उनकी दिवंगत मां का उपहास किया जाना इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक दलों में अब शालीनता की कोई सीमा नहीं बची है। यह प्रवृत्ति किसी एक दल तक सीमित नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी खबरें, मार्फ्ड वीडियो और अभद्र पोस्ट के जरिये विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की एक खतरनाक होड़ मची है। संसद से लेकर चुनावी रैलियों और डिजिटल मंचों तक भाषा का स्तर रसातल में जा रहा है। राजनीति में सामने वाले का चरित्र-हनन कर अंक अर्जित करना ही जैसे मुख्य हथियार बन गया है। यदि इस जहरीली संस्कृति पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह फूहड़पन हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीमक की तरह चाट जाएगा।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

1.23 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) फर्मों का जीईएम पर पंजीकरण हो चुका था 31 मार्च, 2026 तक उत्तर प्रदेश में, जबकि इस प्लेटफार्म पर पांच हजार से अधिक स्टार्टअप फर्म पंजीकृत थीं।

आजकल

छोटे उद्यमों के लिए बढ़ता नया बाजार

सरकार किसी देश की सबसे बड़े खरीदारों में से एक होती है। स्कूलों की किताबों से लेकर कार्यालयों के फर्नीचर तक-सरकारी जरूरतों का बाजार इतना बड़ा है कि यदि उसका एक हिस्सा भी छोटे कारोबारियों तक व्यवस्थित ढंग से पहुंच जाए तो वह लाखों उद्यमों के लिए कारोबार और रोजगार का आधार बन सकता है। इसमें समस्या यह थी कि इस विशाल बाजार तक छोटे उद्यमियों की पहुंच सीमित थी। इस जटिलता को आसान बना दिया गया है, जिसका लाभ अब लघु उद्यमियों को भी मिलने लगा है

अनंत अमित
लोकनीति विश्लेषक

प्रतीकात्मक

दस वर्ष पहले शुरू हुए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने देश के लघु उद्यमियों के लिए व्यापक बाजार और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक उपलब्धि हासिल की है। अपने संचालन का एक दशक पूरा कर चुका जीईएम अब महज सरकारी खरीद का आनलाइन मंच नहीं रहा। अगस्त 2026 तक इसके माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी कारोबार और 3.78 करोड़ से अधिक आर्डर दर्ज हो चुके थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस डिजिटल बाजार में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी लगातार बढ़ी है। ऐसे समय में जब रोजगार और उद्यमिता के लिए छोटे कारोबार को मजबूत करना आर्थिक नीति की प्राथमिकता है, जीईएम की दस वर्ष की यात्रा यह सवाल सामने रखती है कि क्या सरकारी खरीद वास्तव में छोटे उद्यमों के लिए बाजार और विकास का स्थायी आधार बन सकती है।

इस सवाल का जवाब केवल जीईएम पर दर्ज कारोबार के आकार में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि कितने छोटे उद्यम पहली बार बड़े संस्थागत खरीदारों तक पहुंचे, कितनों ने उत्पादन बढ़ाया और कितनों ने सरकारी मांग को स्थायी कारोबार में बदला। वस्तुतः सरकारी खरीद को अक्सर प्रशासनिक प्रक्रिया समझा जाता है, लेकिन इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। सरकार जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदती है, वह बाजार देश के उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मांग का बड़ा स्रोत बन सकता है। जीईएम ने इसी संभावना को डिजिटल मंच दिया है। अब किसी छोटे शहर का उद्यमी केवल अपने स्थानीय बाजार पर निर्भर रहने के बजाय सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच बना सकता है। य

उत्तर प्रदेश की उपलब्धि : जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो यहां सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) फर्मों का जीईएम पर पंजीकरण 31 मार्च, 2025 के 1,06,855 से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 1,23,075 हो गया। यानी एक साल में 16,220 फर्मों की वृद्धि हुई, जो लगभग 16 प्रतिशत है। यह वृद्धि बताती है कि उत्तर प्रदेश के छोटे उद्यम सरकारी संस्थानों की खरीद प्रक्रिया में उपलब्ध डिजिटल बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने और सरकारी खरीद में छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ाने वाली नीतियों के संदर्भ में यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। जीईएम पर महिला फर्मों के पंजीकरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2025 को जहां 19,418 महिला फर्में पंजीकृत थीं, वहीं 31 मार्च, 2026 तक यह संख्या बढ़कर 23,407 हो गई। यानी एक वर्ष में 3,989 महिला फर्में जीईएम से जुड़ीं और इस श्रेणी में करीब 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकारी खरीद में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सक्रियता भी जीईएम के आंकड़ों में दिखाई देती है। 31 मार्च, 2025 को जीईएम पर 4,404 स्टार्टअप फर्में पंजीकृत थीं। 31 मार्च, 2026 तक यह संख्या बढ़कर 5,350 हो गई। यानी एक साल में 946 स्टार्टअप फर्में जुड़ीं और इस श्रेणी में करीब 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे नए उद्यमों को सरकारी संस्थानों तक अपने नवाचार, तकनीकी समाधान और सेवाएं पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होने की तस्वीर सामने आती है।

छोटे कारोबारी के लिए बदलता बाजार : लघु उद्यम की सबसे बड़ी समस्या अक्सर उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि बाजार तक पहुंच होती है। बड़ी कंपनियों के पास विपणन, बिक्री नेटवर्क और ब्रांड निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, जबकि छोटे उद्यमी स्थानीय बाजार में ही सीमित रह जाते हैं। जीईएम इस दूरी को कम करने का माध्यम बन सकता है। डिजिटल मंच पर पंजीकरण और उत्पाद सूचीबद्ध करने के बाद उद्यमी सरकारी खरीदारों तक पहुंच सकता है। इससे बाजार की भौगोलिक सीमा घटती है। उदाहरण के लिए किसी जिले में फर्नीचर, स्टेशनरी, वर्दी, विद्युत उपकरण, कार्यालय सामग्री या विभिन्न सेवाओं से जुड़ा छोटा व्यवसाय सरकारी खरीद की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करके बड़े ग्राहक समूह तक पहुंच सकता है। यहां 'सरकारी बाजार' का अर्थ केवल सरकारी विभागों को सामान बेचना नहीं है। नियमित संस्थागत मांग छोटे उद्यम को उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और कारोबार को औपचारिक बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस तरह सरकारी खरीद रोजगार और उद्यमिता की श्रृंखला को भी प्रभावित करती है।

केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति ने छोटे उद्यमों के लिए इस बाजार को और महत्वपूर्ण बनाया है। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। मौजूदा व्यवस्था में कुल वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत एमएसई से करने का लक्ष्य है। इसमें महिला उद्यमियों के लिए तीन प्रतिशत और अनुसूचित जाति/ जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए चार प्रतिशत उप-लक्ष्य निर्धारित हैं।

इसका महत्व केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यदि सरकारी खरीद में छोटे उद्यमों की भागीदारी बढ़ती है तो सरकारी मांग का एक हिस्सा स्थानीय उत्पादन और उद्यमिता को सहारा दे सकता है। इससे सार्वजनिक खर्च का प्रभाव केवल वस्तु या सेवा खरीदने तक सीमित न रहकर उत्पादन और रोजगार तक पहुंच सकता है। सरकारी खरीद में समावेशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिला उद्यमिता है। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के आंकड़ों में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद 9,079 करोड़ दर्ज की गई और 31,307 उद्यम इससे लाभान्वित हुए। इसी अवधि में अनुसूचित जाति/ जनजाति के उद्यमों से खरीद 3,986 करोड़ रही और 12,479 उद्यम लाभान्वित हुए।

चुनौतियों का समाधान : जीईएम छोटे उद्यमियों को बाजार का दरवाजा तो खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से आगे बढ़ना आसान नहीं है। छोटे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी सीमित होती है। बड़ा सरकारी आदेश मिलने पर कच्चा माल खरीदने, श्रमिक रखने और समय पर आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है। भुगतान में देरी होने पर वही आदेश कारोबार के लिए समस्या बन सकता है। इगुणवत्ता मानक, प्रमाणन, उत्पाद सूचीकरण और प्रतिस्पर्धी कीमत तय करना छोटे उद्यमियों के लिए चुनौती हो सकते हैं। इसलिए जीईएम को केवल डिजिटल बाजार नहीं, बल्कि उसके साथ सहायता तंत्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की व्यवस्थाएं शुरू की हैं।

स्थानीय उद्यमिता का राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव

अब इस नीति का अगला चरण यह होना चाहिए कि जीईएम पर केवल विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने के बजाय उनके कारोबार की गुणवत्ता और स्थायित्व पर ध्यान दिया जाए। जिला उद्योग केंद्रों और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) सहायता संस्थानों को स्थानीय उद्यमियों को यह समझाने की जरूरत है कि कौन-से सरकारी उत्पादों और सेवाओं में मांग है, गुणवत्ता मानक क्या हैं और प्रतिस्पर्धी बोली कैसे तैयार की जाए। इसके साथ बैंकिंग और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था को भी सरकारी खरीद से जोड़ना उपयोगी होगा। समयबद्ध कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था उस उद्यम की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती है।

यहां एक और सावधानी जरूरी है। दरअसल सरकारी खरीद में केवल सबसे कम कीमत को प्राथमिकता देने से छोटे उद्यमों पर दबाव बढ़ सकता है। गुणवत्ता, आपूर्ति की क्षमता, नवाचार और कुल जीवन-चक्र लागत को भी पर्याप्त महत्व देना होगा। दूसरी ओर छोटे उद्यमियों को भी सरकारी संरक्षण के बजाय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सरकारी खरीद का विस्तार छोटे उद्योगों के लिए तभी स्थायी बाजार बनेगा जब पंजीकरण से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया छोटे उद्यमी के अनुकूल हो। आसान पंजीकरण, स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता, समय पर भुगतान, शिकायतों का त्वरित निपटारा और वित्त तक आसान पहुंच- ये सभी जीईएम की अगली सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। आज सार्वजनिक खरीद में एमएसई की बढ़ती भागीदारी यह बताती है कि डिजिटल माध्यम सरकारी मांग और छोटे उद्यम के बीच की दूरी कम कर सकता है। वर्ष 2025-26 के आंकड़ों में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की एमएसई खरीद 1.16 लाख करोड़ से अधिक पहुंचना इसी बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत है।

असल लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितने छोटे उद्यम जीईएम पर पंजीकृत हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि कितने उद्यम वहां से नियमित कारोबार प्राप्त कर रहे हैं, कितने नए रोजगार पैदा कर रहे हैं और कितने स्थानीय कारोबार राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। जीईएम ने छोटे उद्यमियों के सामने सरकारी बाजार का दरवाजा खोला है। अब जरूरत इस बात की है कि इस दरवाजे से गुजरने वाले उद्यमी केवल एक-दो सरकारी आदेश पाने तक सीमित न रहें, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और प्रतिस्पर्धा के बल पर स्थायी कारोबार खड़ा करें। सरकारी खरीद यदि छोटे उद्यम की उत्पादन क्षमता और बाजार पहुंच से जुड़ती है, तो जीईएम पोर्टल से आगे बढ़कर स्थानीय उद्यमिता को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने वाला आर्थिक सेतु बन सकता है।

(अनंत अमित)

खरी-खरी

फर्जी डिस्काउंट

निर्मल गुप्ता

फेस्टिव सीजन आ गया है। घाघ दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा त्याग का पर्व। दुकान के दरवाजे पर नीबू और मिर्ची वाले नजरिए के साथ बोर्ड झूल रहा है- ग्रैंड सेल, मेगा सेल, बंपर धमाका। ये ग्राहक को रिझाने के लिए जरूरी कीवर्ड हैं। 90 प्रतिशत तक की बेमिसाल छूट। ऐसा आफर जो न पहले कभी किसी ने सुना और न कभी पाया। मतलब साफ कि दुकानदार अपना घर-बार, बीवी के जेवर, बच्चों का टैब, फैंसी साइकिल आदि सब बेचने को तैयार है, बस कोई ग्राहक एक बार दुकान में आए तो। सेल वाले दुकानदार जितना बड़ा त्यागी तो ग्रंथों में वर्णित कोई मिथक पुरुष भी अभी तक नहीं हुआ।

त्योहार का मतलब ही यही है- शुभ और लाभ। शुभ ग्राहक के लिए, लाभ दुकानदार के लिए। शुभ फोटो के लिए, लाभ मिलावट के लिए। बड़े-बड़े ब्रांड कहते हैं- इस दिवाली दिलों को रोशन करो। मतलब जेब को खाली करो, दिल अपने आप रोशन हो जाएगा। ईएमआइ पर रोशनी बाजार में उपलब्ध है न। तमाम तरह की सुविधा और खुशियां आजकल एकमुश्त नहीं, बल्कि आसान किस्तों पर ही मिलती हैं।

और हमारे समय के महान डिजिटल इन्फ्लुएंसर आजकल ओवरटाइम कर रहे हैं। वो इस सीजन में सबसे ज्यादा व्यस्त प्राणी हैं। वो न शर्ट बेच रहा है, न मावा। वो सेल का वीडियो बना रहा है- मैंने इस दुकानदार की ईमानदारी देखी, 90 प्रतिशत डिस्काउंट में भी कैसे ये घर चला रहा है, सैल्यूट है। किसी की दुकान पर जाएगा तो कहेगा- देसी घी की खुशबू, बचपन की याद ताजा हो आई।

पहले त्योहार पर लोग घर लीपते-पोतते थे, अब दुकानदार दोनों हाथों से लाभ लपेटता है। पहले मिठाई में मावा होता था, अब मावे में मिठाई जैसी कोई चीज होती है। लगती है मिष्ठान जैसी पर सही सही किसी को नहीं पता कि वास्तव में ये होती क्या है। पहले डिस्काउंट दिल से दिया जाता था, अब कैलकुलेटर से दिया जाने लगा है। पर ग्राहक खुश है। उसे 90 प्रतिशत छूट मिल गई। उसे क्या पता, 90 प्रतिशत छूट के बाद भी वो 10 प्रतिशत लुट गया। इसी को कहते हैं- फेस्टिवल ब्लास्ट। ग्राहक के लिए धमाका, व्यापारी के लिए शुभ-लाभ।

X पोस्ट

पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विचारों को सुनकर यही लगता है कि वे मूलतः मजहबी उपदेशक हैं, जिन्होंने बस सेना की वर्दी पहनी हुई है।
वेद प्रकाश मलिक@Vedmalik1

चुनाव आयोग से जुड़ी खबर इसका संकेत है कि नौकरशाही एक बार फिर मीडिया से रिश्ते साधने लगी है और सरकार के भीतर की खबरें बाहर पहुंचाने लगी है। अतीत के हर सत्ता-संक्रमण के दौर में यही दिखा है।
कल्लोल भट्टाचार्जी@janusmyth

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है 'मतभेद व असहमति' में फर्क है। आयुक्तों ने फैसलों पर टिप्पणी की हो, पर आदेश जारी करते समय असहमति नहीं जताई थी।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

अगर आप नियुक्तियों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का क्रम देखें तो सीवीसी, सीबीआइ चीफ, ईडी निदेशक की नियुक्ति सरकार नहीं कर सकती, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पूरी तरह से न्यायपालिका ही करती है।
अखिलेश मिश्रा@amishra77

मध्य प्रदेश डायरी

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

21 वर्ष बाद सार्वजनिक परिवहन

मध्य प्रदेश के लिए 25 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। इस दिन राज्य के लोगों को 21 वर्ष बाद शासकीय परिवहन सेवा का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से 25 सितंबर से राज्य में सरकारी बसें संचालित की जाएंगी। सरकारी कंपनी के माध्यम से चलने वाली इन बसों को कई चरणों में शुरू किया जाएगा। यह बस सेवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर आधारित होगी, जिसमें नियंत्रण और मानिटरिंग सरकार के पास रहेगी, जबकि संचालन निजी आपरेटर करेंगे। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे और पहले दिन 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

वर्ष 2005 में तत्कालीन बाबूलाल गौर सरकार के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। तबसे लोग पूरी तरह से निजी बसों पर निर्भर थे। अब सरकार एक नए हाइब्रिड माडल के साथ इसकी वापसी कर रही है। इस सेवा को सुचारु रूप से चलाने और यात्रियों को सुरक्षित व आधुनिक सफर देने के लिए सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन से चार वर्षों में शुरुआती डेढ़ हजार बसों के नेटवर्क को बढ़ाकर 15 हजार बसों तक पहुंचाने का है। इस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निजी संचालकों की मनमानी और ओवरलोडिंग की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक परिवहन के अभाव में लाखों ग्रामीणों को न केवल रोजमर्रा के सफर में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बल्कि सुरक्षा से समझौता करने के कारण कई बेगुनाह लोगों को सड़क हादसों में अपनी जान भी गंवानी पड़ी है।

शासकीय परिवहन सेवा के आरंभ से दूर-दराज की यात्रा करने वालों को होगी सुविधा। प्रतीकात्मक

सरकारी बसें बंद होने के बाद ग्रामीण इलाकों में मैजिक, आटो, जीप और अवैध वाहन ही एकमात्र सहारा बन गए। मुनाफे के चक्कर में इन वाहनों में क्षमता से तीन से चार गुना अधिक सवारियां भरी जाती हैं, जो अकसर बड़े हादसों का कारण बनती हैं। निजी बस संचालक केवल उन्हीं रूट पर बसें चलाना पसंद करते हैं जहां उन्हें अधिक मुनाफा या ज्यादा यात्री मिलते हैं। इसके कारण दूरदराज के छोटे गांव मुख्य सड़कों और शहरों से पूरी तरह कट गए। स्थिति यह बन गई थी कि ग्रामीणों को अस्पताल जाने, कोर्ट-कचहरी के काम या पढ़ाई के लिए शहरों तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था।

परिवहन विभाग और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों पर होने वाले हादसों में एक बड़ी संख्या उन यात्रियों की होती है जो मजबूरन असुरक्षित, ओवरलोडेड या खटारा निजी वाहनों में सफर कर रहे होते हैं। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कम मुनाफे वाले रूट पर बसें चलाना अनिवार्य करेगी। इसके लिए निजी आपरेटरों को सरकार की तरफ से सब्सिडी या टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि वे गांवों तक बसें ले जाएं। ग्रामीण इलाकों में इस सेवा के बहाल होने से न केवल लोगों का पैसा और समय बचेगा, बल्कि हादसों और असमय मौतों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी।

मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने का मुख्य कारण भारी वित्तीय घाटा और ऋण का बढ़ता बोझ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने दो जनवरी, 2005 को इसके परिसमापन की आधिकारिक घोषणा की थी। उस दौर में इस बड़े फैसले के पीछे कई मुख्य कारण और परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। इनमें 756 करोड़ रुपये का भारी घाटा भी एक बड़ी वजह था। उस दौर में निगम को हर महीने करीब पांच करोड़ रुपये का रनिंग लास हो रहा था, जिसे उठा पाना राज्य के खजाने के लिए मुश्किल हो रहा था।

अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का यह निर्णय वास्तव में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक मील का पत्थर और अत्यंत संवेदनशील कदम माना जा रहा है। जहां पिछले दो दशकों से घाटे और कानूनी पेचीदगियों के डर से कोई भी सरकार इस क्षेत्र में हाथ डालने से कतरा रही थी, वहीं मुख्यमंत्री डा. यादव ने आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्ग की तकलीफों को प्राथमिकता दी।

डा. यादव ने साफ किया कि परिवहन सेवा केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोक-कल्याण का एक अनिवार्य माध्यम है। 21 साल के 'परिवहन वनवास' को खत्म कर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के रूप में राज्य को एक सुरक्षित और सुलभ तंत्र सौंपना निश्चित रूप से एक ऐसा फैसला है, जिसे प्रदेश की जनता लंबे समय तक याद रखेगी।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सरकार की चेतावनी के बाद विमान कंपनियां त्योहारी सीजन में टिकट के दाम में मनमानी से बाज आएंगी?

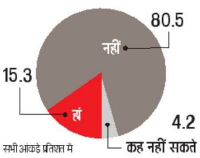

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या चुनाव आयोग में खींचतान इस संस्था की साख पर सवाल उठाने वाली है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

चीटिंग हो एजाम में ओढ़ जाति का खोल,
अगर कहीं पकड़े गए जमकर हल्ला बोल।
जमकर हल्ला बोल यही है बड़ा सहारा,
कहां ज्ञान की पूछ फिर रहा मारा-मारा!
ले 'बाबा' का नाम पा रहे हैं एवरी थिंग,
अब न 'बाबा' कोय आज तक करके चीटिंग!!
-ओम प्रकाश तिवारी

हिमाचल प्रदेश डायरी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

कब तक धीरज धरे धूलि धूसरित धरोहर

हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध कहावत 'बालुए जो रोंदी थी, नक्के ते भी गई' यानी नाक के लौंग या बाली के लिए रोती थी, लेकिन नाक से ही हाथ धोना पड़ा...। पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेलमार्ग ब्राडगेज करने की आवाजों के बीच जो नैरो गेज बचा था, वह भी रेलगाड़ियों से वंचित हो गया है। स्टेशन सुन्न हैं, पटरी पीड़ित है और राजनीति के दावे नित गूंजते हैं कि सर्वेक्षण अब हुआ कि तब हुआ।

यह बात शानन प्रोजेक्ट को बनाने वाले कर्नल बीसी बैट्टी, माल ढुलाई के लिए पठानकोट से जोगेंद्रनगर तक रेलमार्ग बिछाने वाले कार्य अधीक्षक ईबीएन टेलर और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के एक इंजीनियर नील की स्मृति को साक्षी रख कर कही जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश के इस 164 किलोमीटर (सबसे लंबे) रेलमार्ग को एक अश्विनी वैष्णव न सही, कुछ समय पहले तक रेल राज्य मंत्री रहे रवनीत सिंह बिट्टू की बड़ी जरूरत थी। बिट्टू होना क्या है... यह इससे जाना जा सकता है कि पठानकोट वालों को लगा कि हिमाचल जाने वाली गाड़ियों के कारण शहर के व्यस्त क्षेत्रों में फाटक बंद हो जाते हैं और शहर बार-बार ठिठकता है। सो अब रेल चलेगी तो हिमाचल की सवारियों के लिए पठानकोट का अर्थ हिमाचल का अंतिम बिंदु डलहौजी रोड होगा। यानी मूल पठानकोट स्टेशन से दस किलोमीटर पहले। आइए देखें कि 1926 से 1929 के बीच बने, 990 पुलों, दो सुरंगों और 500 मोड़ों वाले इस रेलमार्ग के इतिहास में अब ऐसा मोड़ क्यों आया है कि धरोहर बनने के बिंदु पर खड़े इस मार्ग पर डरावना सन्नाटा है।

इंजीनियर नील को इसलिए याद किया, क्योंकि 'नील्स बाल टोकन सिस्टम' ने इकहरी पटरी वाले इस पहाड़ी रेलखंड में आज तक कोई दुर्घटना नहीं होने दी। यह सुनिश्चित करता है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने-सामने या एक-दूसरे के पीछे न टकराएं। जब तक रेलगाड़ी चालक के पास उस विशिष्ट रेल खंड का धातु का 'टोकन' (लोहे की गेंद) नहीं होगा, तब तक वह ट्रेन को उस सिंगल लाइन पर आगे नहीं ले जा सकता।

हुआ यूं कि चार साल पहले पठानकोट के पास पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला चक्की पुल ध्वस्त हुआ। उपलब्ध फोटो और आम समझ के अनुसार इसके पीछे अवैध खनन था, पर आधिकारिक रूप से ऐसा जोर शोर से तो नहीं, 'नाम न छापने की शर्त पर' ही माना गया। खैर, चार वर्ष तक रेल परिचालन ठप रहा। पुल बना तो चार जून, 2026 को रेल सेवा प्रारंभ हुई। कई सांसदों-विधायकों ने इसे हरी झंडी दिखाई। यह झंडी ब्राडगेज के लिए या पूर्ववत सात गाड़ियां चलाने की प्रसन्नता में नहीं, इसलिए दिखाई गईं कि दो रेलगाड़ियां चलेंगी। फिर जुलाई की बरसात आई, कुछ स्थानों पर मलबे गिरे और ये दो रेलगाड़ियां भी बंद।

पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेलमार्ग के विकास की प्रतीक्षा में प्रदेशवासी। फाइल

इस मार्ग को ब्राडगेज करके मंदिरों से जोड़ा जा सकता है, पर्यटन स्थलों से जोड़ा जा सकता है, मंडी तक पहुंचा दें तो रणनीतिक लाभ भी होगा। मंदिर दर्शन के अलावा साहसिक पर्यटन के इच्छुक आते हैं, दलाईलामा का अलग आकर्षण है, चाय पर्यटन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हैं, वेलनेस के लिए लोग कांगड़ा घाटी का रुख कर रहे हैं... क्या रेलवे इन्हें संभावनाएं नहीं मानता? सब बिंदु कांगड़ा से लोकसभा सदस्य डा. राजीव भारद्वाज संसद में रख चुके हैं। यह रहस्य नहीं कि इस मार्ग पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां ट्रेन ही सुविधाजनक है। शानन परियोजना से आर्थिक लाभ कांगड़ा घाटी रेलवे को क्यों न मिले। शानन की लीज भी समाप्त है...। वर्ष 2025 में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी को रेलमंत्री ने बताया था कि गेज बदलने से संबंधित परियोजना रपट बन रही है, उसे राज्य सरकार को भी भेजेंगे। वर्ष 2026 में डा. राजीव भारद्वाज के प्रश्न संख्या 612 के लिखित उत्तर में बताया गया कि डीपीआर के लिए स्वीकृति दे दी गई है। और यदि गेज परिवर्तन पर्यावरण की कीमत पर होना हो तो इस मार्ग को अपना समझ कर इसी में प्राण फूंके जाने चाहिए। बैजनाथ पपरोला स्टेशन का सुंदरीकरण केंद्रीय योजना के अंतर्गत हुआ है, लेकिन ट्रेन ही न चले तो यह वैसा ही है, जैसे किसी खंडहर को आबाद कर दो, पहुंचना भूल जाओ। समझना होगा कि कांगड़ा घाटी रेलवे केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि हिमाचल की पहचान, धरोहर और गौरव भी है। इसे पूरे भाव के साथ विकसित किया जाना चाहिए। विश्व धरोहर के लिए यूनेस्को के संभावित स्थलों में इस रेलमार्ग के प्रविष्ट होने पर दृष्टि है तो भी धरोहर पर जमी धूल को तो झाड़ना ही पड़ेगा न।

कांगड़ा घाटी रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा कहते हैं कि डलहौजी रोड रेलवे स्टेशन पर 21 करोड़ रुपये खर्च करने से बेहतर है कि पठानकोट शहर में अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने पर खर्च किए जाएं, ताकि पठानकोट भी न ठिठके और हिमाचल की गाड़ी भी चलती रहे। वर्तमान में तो अग्रज शायर दुष्यंत कुमार से क्षमायाचना करते हुए यही कहा जा सकता है :

तुम कहां रेल सी गुजरती हो
मैं भी कब पुल सा थरथराता हूं।

एनटीपीसी ने 3,394 करोड़ रुपये का लाभांश दिया

नई दिल्ली: सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने शेयरधारकों को 3,393.83 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया है। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष के लिए कंपनी की ओर से दिया गया कुल लाभांश 8,727 करोड़ रुपये हो गया है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य वाले हर इक्विटी शेयर पर नौ रुपये के बराबर है। बिजली मंत्रालय के तहत एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। (प्रेट्र)

कंपनी को पिछले साल की तुलना में इस त्योहारी सत्र में बिक्री में दोहरे अंक में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसकी वजह ग्राहकों का बेहतर भरोसा, जीएसटी की वजह से किफायती दाम और त्योहारी सत्र का लंबा समय है।

– संजय चित्कारा, सह मुख्य बिक्री अधिकारी, एलजी इंडिया

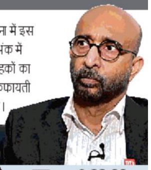

सेंसेक्स	74,828.25	▲ 299.17
निफ्टी	23,446.80	▲ 117.80
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,54,000	▼ ₹ 900
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,42,000	बदलाव नहीं
डालर	₹ 95.73	▲ ₹ 0.11
क्रूड प्रति बैरल	$ 99.60	

भारत की इकोनमी पर सभी रेटिंग एजेंसियों ने जताया भरोसा

मूडीज के बाद अब फिच रेटिंग, एसएंडपी ग्लोबल और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को देखते हुए तमाम वैश्विक रेटिंग एजेंसियां अब भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाने लगी हैं। मूडीज के बाद अब फिच रेटिंग, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास के अपने अनुमान को बढ़ाते हुए सात प्रतिशत कर दिया है। सिर्फ फिच रेटिंग ने पूर्व के अपने 6.4 प्रतिशत के अनुमान को 6.9 प्रतिशत रखा है। मूडीज ने अपने अनुमान को छह प्रतिशत से सात प्रतिशत, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने 6.6 प्रतिशत से सात प्रतिशत तो एडीबी ने भी अपने 6.6 प्रतिशत के अनुमान को सात प्रतिशत कर दिया है। आरबीआइ ने भी चालू वित्त वर्ष में विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

खास बात यह है कि विकास दर में बढ़ोतरी के साथ वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने महंगाई दर में भी इजाफे का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए इन रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि आरबीआइ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में बैंक दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है कि लोन लेना महंगा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई। दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भी आटो बिक्री, जीएसटी कलेक्शन, प्रत्यक्ष कर संग्रह, बिजली व पेट्रोल-डीजल की खपत, निर्यात के सकारात्मक सूचकांक को देखते हुए एसबीआइ ने सात प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे खर्च की बदौलत अर्थव्यवस्था बढ़ रही आगे: एडीबी के भारत स्थित निदेशक मियो ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई में बाधा और जिंसों की ऊंची कीमत के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर में हो रहे खर्च और विकास को समर्थन देने वाली नीतियों की बदौलत लगातार मजबूती दिखा रही हैं। हालांकि एडीबी के साथ एसएंडपी और फिच ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर को पांच प्रतिशत के स्तर को पार करने का अनुमान लगाया है। गत वित्त वर्ष 2025-26 में खुदरा महंगाई दर तीन प्रतिशत से कम थी। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 4.84 तक पहुंच गया है।

तेल कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव: कच्चे तेल की कीमत पिछले 15-20 दिनों से 100 डालर प्रति बैरल के पार चल रही है। इससे तेल कंपनियों पर फिर से पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम में बढ़ोतरी का दबाव बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई पर लगाम के लिए आरबीआइ अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 0.25 आधार अंक तक रेपो रेट बढ़ा सकती है।

- विकास दर में बढ़ोतरी के साथ वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने महंगाई दर में भी इजाफे का अनुमान लगाया
- रेटिंग एजेंसियों ने कहा-आरबीआइ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बैंक दरों में कर सकता है बढ़ोतरी

रेटिंग एजेंसियां क्यों बढ़ा रहीं जीडीपी वृद्धि का अनुमान

रेटिंग एजेंसी	वजह	जोखिम
एसएंडपी ग्लोबल 7% (पूर्व अनुमान 6.6%)	वित्त वर्ष 2028 में 7.2% और वित्त वर्ष 2029 में सात प्रतिशत की मजबूत मांग से इकोनमी को मिलेगी मदद।	सामान्य से कम बारिश होने, महंगाई के पांच प्रतिशत से ऊपर जाने और ब्याज दरें बढ़ने से जीडीपी की रफ्तार कमजोर पड़ सकती है।
फिच रेटिंग्स 6.9% (पूर्व अनुमान- 6.4%)	आत्मनिर्भरता और जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर जीडीपी की मजबूती की प्रमुख वजह।	अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने, पीएमआइ मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने और मानसून सामान्य से कम रहना अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख जोखिम।
मूडीज रेटिंग्स 7% (पूर्व अनुमान 6.0%)	वैश्विक झटकों को सहन करने के साथ ही निजी निवेश में तेजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च विकास दर के लिए संजीवनी।	अगर पश्चिम एशिया संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही अलनीनो का असर कायम रहा तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी।
आरबीआइ 6.7% (पूर्व अनुमान- 6.6%)	मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर की तेज मांग और निजी निवेश जीडीपी को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे।	अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की तुलना में देश के केंद्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद का सतर्क अनुमान लगाया है।

ओईसीडी ने भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने मजबूत घरेलू मांग और सरकारी नीतियों को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 0.80 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इसके पहले जून में ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। पेरिस स्थित ओईसीडी ने बुधवार को जारी अपने अंतरिम आर्थिक परिदृश्य में कहा कि जी20 में शामिल भारत जैसी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और सरकार की उन नीतियों से समर्थित रही, जिन्होंने ऊंची ऊर्जा कीमतों के असर से परिवारों और कंपनियों को राहत दी।

आरबीआइ को क्यों पड़ी बैंकों से नकदी निकालने की जरूरत

आरबीआइ द्वारा बैंकिंग सिस्टम से नकदी निकालने का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और देश की मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाए रखना होता है। जब देश के बैंकों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त नकदी जमा हो जाती है तो आरबीआइ विभिन्न वित्तीय साधनों के जरिये इस पैसे को अपने पास खींच लेता है।

ये हैं बड़ी वजह

महंगाई पर लगाम लगाना: यदि बैंकों के पास अत्यधिक नकदी होगी, तो वे बाजार में बहुत आसानी से और सस्ते ब्याज दरों पर लोन बांटना शुरू कर देंगे। बाजार में पैसे का बहाव तेज होने से लोगों के खरीदने की क्षमता (मांग) बढ़ेगी, जिससे चीजें महंगी हो सकती हैं।

मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाए रखना: आरबीआइ अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए 'रेपो रेट' तय करता है, लेकिन अगर बैंकों के पास पहले से ही बहुत पैसा होगा तो वे आपस में ही बहुत कम ब्याज दर पर लेन-देन करने लगेंगे। इससे आरबीआइ की नीतिगत दरों का असर बाजार पर कमजोर पड़ जाएगा। बाजार की ब्याज दरों को अपनी रेपो रेट के दायरे में रखने के लिए आरबीआइ दखल देता है।

वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाना: अत्यधिक नकदी के कारण वित्तीय बाज़ारों और एसेट प्राइसेज (जैसे शेयर बाजार या प्रापर्टी) में कृत्रिम तेजी आ सकती है, जो आर्थिक संकट का रूप ले सकती है। नकदी कम करके बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जाती है।

बैंकों से पैसे निकालने के लिए इन तरीकों का होता है इस्तेमाल

वीआरआर: परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआर) के तहत बैंक अतिरिक्त नकदी को एक निश्चित अवधि (जैसे सात दिन, 14 दिन या 30 दिन) के लिए आरबीआइ के पास जमा करते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं।

ओएमओ: खुले बाजार परिचालन के तहत आरबीआइ बैंकों को सरकारी बांड बेचता है। बैंक इन्हें खरीदते हैं और पैसा सीधे आरबीआइ के पास चला जाता है।

सीआरआर: इसमें बैंकों को कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआइ के पास जमा करना होता है। इसे बढ़ा भी नकदी होती है।

₹75,026 करोड़ आरबीआइ ने बुधवार को वीआरआर के जरिये बैंकों से निकाले

₹4.45 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी थी बैंकिंग प्रणाली में 22 सितंबर तक

विदेशी मुद्रा जमा योजना से बैंकों में आए 133 अरब डालर

बैंकों में अतिरिक्त नकदी की बड़ी मात्रा का एक कारण विदेशी मुद्रा जमा योजना (133 अरब डालर) में भारी वृद्धि है। जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण इस विंडो को तय समय से एक महीने पहले (31 अगस्त 2026) ही बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ओएफसीबी के जरिये 5.320 अरब डालर और वाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) से 5.296 अरब डालर आए। बाद में आरबीआइ के साथ किए गए अदला-बदली सौदों से बैंकों को रुपये की नकदी मिली। इसके अलावा महीने के अंत में सरकार की ओर से वेतन और पेंशन समेत विभिन्न मदों में किए गए खर्च से भी बैंकों में नकदी बढ़ी। *(इनपुट: जेएनएन)*

एक नजर में

अगस्त में घरेलू हवाई यात्री संख्या 6.34 प्रतिशत घटी

मुंबई: भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात अगस्त में सालाना आधार पर 6.34 प्रतिशत घटकर 121.26 लाख रह गया। सभी एयरलाइन कंपनियों ने अगस्त 2025 में कुल 129.47 लाख यात्रियों को हवाई यात्रा कराई थी। डीजीसीए ने कहा, 'जनवरी-अगस्त 2026 में कंपनियों ने 1,105.30 लाख यात्रियों को यात्रा कराई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1,107.26 लाख थी। इस तरह सालाना वृद्धि दर -0.18 प्रतिशत और मासिक (अगस्त 2026 की तुलना में अगस्त 2025) वृद्धि दर -6.34 प्रतिशत रही।' (प्रेट्र)

वित्त मंत्रालय 12 अक्टूबर से शुरू करेगा बजट-पूर्व बैठकें

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय 2027-28 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत 12 अक्टूबर से एक महीने तक बजट-पूर्व बैठकें शुरू करेगा। बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2027-28 का बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार दसवां बजट होगा। (प्रेट्र)

एमएसईआइ पर भी ट्रेड होंगे एनएसई के शेयर

नई दिल्ली: एनएसई के शेयरों में गुरुवार से बीएसई के साथ मेट्रोपालिटन स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया (एमएसईआइ) पर भी कारोबार होगा। एमएसईआइ ने बुधवार को कहा कि एनएसई के शेयर को गुरुवार से उसके पूंजी बाजार खंड में 'कारोबार के लिए मंजूर' श्रेणी के तहत कारोबार के लिए स्वीकार किया जाएगा। 'कारोबार के लिए मंजूर' श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों के लिए एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौता नहीं किया जाता है। (प्रेट्र)

जोहो ने पेश किया एकीकृत एआइ इंटरफेस 'जिया चैट'

चेन्नई, प्रेट्र: घरेलू साफ्टवेयर कंपनी जोहो ने बुधवार को कारोबारी क्षेत्रों के लिए एकीकृत एआइ इंटरफेस 'जिया चैट' पेश किया। यह एआइ इंटरफेस बिक्री, विपणन, ग्राहक सहायता, मानव संसाधन और वित्त जैसे कार्यों में उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। यह रिकार्ड और बातचीत का सारांश तैयार करने, कारोबारी आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा रिपोर्ट, चार्ट, स्प्रेडशीट और प्रस्तुति तैयार करने के साथ ईमेल का मसौदा बनाने में भी मदद कर सकता है। इसके साथ ही, जोहो ने सात क्षेत्रों के लिए उद्योग-विशेष उत्पाद पेश किए हैं। इनमें भौतिक खुदरा कारोबार के लिए जोहो रिटेलआइक्यू, वाहन डीलरशिप के लिए जोहो आटोडीएमएस और बैंकों, एनबीएफसी तथा बीमा कंपनियों के लिए ऋण प्रक्रिया से जुड़ा जोहो एलओएस शामिल है।

एआइ पर वैश्विक रोक अव्यावहारिक: वेम्बु

जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने कहा है कि एआइ के संभावित खतरों को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और एआइ विकास पर वैश्विक स्तर पर रोक लगने की संभावना नहीं है। उन्होंने भारत से रणनीतिक विकल्प खुले रखने और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान एवं विकास में बड़े पैमाने पर निवेश करने का आग्रह किया।

रूस से तेल खरीदते रहेंगे: सीतारमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की आशंका के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही भारत रूस से तेल नहीं खरीदने की घोषणा करेगा, तेल की कीमत बढ़ जाएगी। यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 1.4 अरब भारतीयों के हित का सवाल है और भारतीयों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत तेल विक्रेता सभी देशों से खरीदारी की संभावना तलाशता रहता है।

भारत अमेरिका और चीन के बाद पेट्रोल-डीजल की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए रूस से तेल खरीदारी बंद करने पर भारत को पश्चिम एशिया और अमेरिका पर तेल खरीद के लिए निर्भर होना पड़ेगा। इसे देखते हुए पश्चिम एशिया के देश तुरंत अपने तेल की कीमत बढ़ा देंगे। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी रूस से तेल खरीदारी नहीं करने की अपील की है। अमेरिका ने तो रूस के प्रमुख तेल खरीदार चीन, भारत, टर्की जैसे देशों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का कानून तक बना दिया है। अमेरिका अगर भारत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है तो अमेरिका के बाजार में भारत का निर्यात कठिन हो जाएगा।

- मित्र राष्ट्र से तेल नहीं खरीदने की घोषणा करते ही बढ़ जाएंगी कीमतें
- 1.40 अरब भारतीयों का हित सर्वोपरि, अन्य संभावनाएं भी तलाश रहे

'ट्रांसफर प्राइसिंग' विवादों से विकासशील देशों पर पड़ता बोझ

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ब्रिक्स देशों से अंतरराष्ट्रीय कराधान में संधि की व्याख्या और बहुपक्षीय वार्ताओं से जुड़े अपने अनुभव साझा करने का आग्रह करते हुए कहा कि 'ट्रांसफर प्राइसिंग' से जुड़े वैश्विक विवादों का विकासशील देशों पर असमान रूप से अधिक बोझ पड़ता है। 'ट्रांसफर प्राइसिंग' संबंधित कंपनियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के लेनदेन की कीमत तय करने से जुड़ी व्यवस्था है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में अलग-अलग देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले मुनाफे के उचित हिस्से पर कर लगाया जाए।

तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ का घाटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बाद भारत की सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल पर प्रति लीटर 8 रुपये तथा डीजल पर 9 रुपये का नुकसान उठा रही हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी करीब 300 रुपये है। इन कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है।

इक्रा का कहना है कि भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल की बास्केट कीमत 21 सितंबर 2026 को 117.4 डालर प्रति बैरल थी जबकि 2025-26 में औसतन आयात मूल्य 66 डालर प्रति बैरल था। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ मई, 2026 में खुदरा कीमतें बढ़ाई हैं। 19 से 23 मई, 2026 के बीच पेट्रोल की खुदरा कीमत में कुल चार बार (कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर) बढ़ोतरी की गई थी।

हालांकि उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड लगातार अस्थिर बना रहा है। हाल के हफ्तों में यह लगातार 100 डालर प्रति बैरल के आस पास है। रिपोर्ट के मुताबिक वैसे इन कंपनियों की रिफाइनिंग मार्जिन की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। सिंगापुर ग्रास रिफाइनिंग मार्जिन (एशिया में तेल रिफाइनरियों की लाभ मार्जिन निकालने का बेंचमार्क) पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद 10 डालर प्रति बैरल से ऊपर बने हुए हैं। फिर भी ऊंचे कच्चे तेल और उत्पादों को कम लागत से लगातार बेचने से कंपनियों की लाभप्रदता तथा नकदी प्रवाह पर असर पड़ने की संभावना है। कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार उन्हें कितना वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है।

ICRA

- पेट्रोल की बिक्री पर आठ तो डीजल बेचने पर हो रहा नौ रुपये प्रति लीटर का नुकसान
- घरेलू एलपीजी पर सितंबर में प्रति सिलेंडर करीब 300 रुपये का हो रही हानि

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अमीरों की सूची में गौतम अदाणी फिर शीर्ष पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: गौतम अदाणी और उनका परिवार मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत के अमीरों की सूची में फिर से एक बार शीर्ष स्थान पर आ गया है। अदाणी की संपत्ति 13 प्रतिशत बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डालर) हो गई, जबकि अंबानी की संपत्ति 10 प्रतिशत गिरकर 8.63 लाख करोड़ रुपये हो गई। इससे दोनों के बीच 59,400 करोड़ रुपये का अंतर रह गया। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में लक्ष्मी निवास मित्तल और उनका परिवार तीसरे स्थान पर पहुंच गया और उनकी संपत्ति दोगुनी होकर 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला और परिवार चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद एचसीएल की रोशनी नादर मल्होत्रा, कुमार मंगलम बिड़ला, सन फार्मास्युटिकल के दिलीप सांघवी और विप्रो के अजीम प्रेमजी रहे। अनिल अग्रवाल और उनका परिवार 2.08 लाख करोड़ रुपये के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए। जबकि समीर मेहता के नेतृत्व वाली टोरंट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जेबी केमिकल्स के अधिग्रहण के बाद वह और उनके परिवार की संपत्ति में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1.89 लाख करोड़ के साथ सूची में 10वें स्थान पर हैं।

सूची में शीर्ष स्थान के लिए अंबानी और अदाणी में हर साल कड़ा मुकाबला होता है। पहली बार गौतम अदाणी और उनके परिवार ने 2022 में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2023 में अदाणी एक स्थान नीचे खिसके गए। 2024 में फिर से बढ़त हासिल की और 2025 में फिर एक बार पीछे हो गए।

- मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, पिछले एक साल में अदाणी की संपत्ति 13 प्रतिशत बढ़ी
- एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या रिकार्ड 391 पर पहुंची

गौतम अदाणी

देश में 1,810 लोगों की संपत्ति एक हजार करोड़ से अधिक

1,000 करोड़ से अधिक जिन लोगों के पास संपत्ति है, ऐसे लोगों की देश में संख्या 1,810 है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 128 अधिक है। इन लोगों की संयुक्त संपत्ति 12.8 प्रतिशत बढ़कर 187.5 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो लगभग 1.96 ट्रिलियन डालर है और भारत की जीडीपी का लगभग आधा है।

मुंबई में रहते हैं सबसे ज्यादा धनी लोग

465 लोगों के साथ मुंबई भारत का सबसे बड़ा धनाढ्य केंद्र है। इसके बाद 236 सबसे धनी लोग दिल्ली में रहते हैं। 129 लोगों के बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा 2.79 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं। सूची में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें 156 देश के बाहर रहते हैं।

राष्ट्रीय फलक

त्योहार को देखते हुए सोया और पाम तेल पर शुल्क में कटौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: त्योहार को देखते हुए सरकार ने सोयाबीन और पाम तेल के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की है। पिछले कई महीनों से खाद्य तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। बुधवार को देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल के आयात पर 10 प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत का शुल्क लगेगा। कच्चे सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड पाम तेल पर अब 32.5 प्रतिशत की जगह 27.5 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। यह फैसला 24 सितंबर से मान्य होगा। इस फैसले से सरसों तेल की खपत पर दबाव कम होगा और उनकी कीमतों में भी नरमी आएगी।

बाबा रामदेव बोले- बृजभूषण से मुलाकात के बाद विवाद का पटाक्षेप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बाबा रामदेव और भाजपा नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। रामदेव ने बुधवार को खुद दोनों के बीच विवाद खत्म होने की बात कही। रामदेव के मुताबिक, उनकी बृजभूषण से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनी-सुनाई बातों पर उन्होंने यह आरोप लगाया था। ऐसे में इस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों बृजभूषण ने रामदेव के उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों के मुद्दे को उठाया था। इन बयानों के बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृजभूषण के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि दावा भी दायर किया था।

- पतंजलि के उत्पादें के बारे में कहा- कोई मिलावट मिले तो मुझे फांसी दे दें

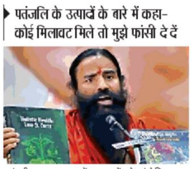

कांस्टीट्यूशन क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते बाबा रामदेव। चंद्र प्रकाश मिश्र

बाबा रामदेव ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पतंजलि के उत्पाद 100 प्रतिशत शुद्ध हैं, यदि इनमें मिलावट मिले तो उन्हें चौराहे पर फांसी पर लटका दें। पतंजलि के उत्पाद पूरी तरह प्रामाणिक हैं। मिलावट सामाजिक और धार्मिक पाप है। इसके विरुद्ध सख्त कानून बने।

सुभाष चंद्रा ने संपत्ति हस्तांतरण पर रोक के खिलाफ की अपील

नई दिल्ली, एएनआइ: जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की पांच सदस्यों वाली स्पेशल बेंच के एक सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था।

कार्यवाहक चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) योगेश खन्ना और टेक्निकल मेंबर बरुण मित्रा और अजय दास मेहरोत्रा की बेंच ने चंद्रा की अपील पर सुनवाई की और उन्हें निर्देश दिया कि वे याचिका की कापी क्रेडिटर्स को सौंपें। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। कई क्रेडिटर्स ने बताया कि उन्हें या तो अपील की कापी नहीं मिली थी या पक्षकार नहीं बनाया गया था।

घरेलू हवाई यात्री संख्या अगस्त में 6.34% घटकर 121.26 लाख रही

मुंबई, प्रेट्र: भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात अगस्त में सालाना आधार पर 6.34 प्रतिशत घटकर 121.26 लाख रह गया। सभी भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने अगस्त 2025 में कुल 129.47 लाख यात्रियों को हवाई यात्रा कराई थी।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, 'जनवरी-अगस्त 2026 अवधि के दौरान घरेलू एयरलाइन कंपनियों ने 1,105.30 लाख यात्रियों को यात्रा कराई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 1,107.26 लाख थी।'

समीक्षाधीन महीने में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी जुलाई के 67.4 प्रतिशत से घटकर 65 प्रतिशत रह गई। वहीं, संकटग्रस्त स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी भी जुलाई के 1.6 प्रतिशत से घटकर 1.2 प्रतिशत रह गई।

- जनवरी-अगस्त 2026 अवधि के दौरान घरेलू एयरलाइन कंपनियों ने 1,105.30 लाख यात्रियों को यात्रा कराई

इसके विपरीत, एयर इंडिया समूह की बाजार हिस्सेदारी अगस्त में बढ़कर 26.7 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई 2026 के मुकाबले 2.7 प्रतिशत अधिक है। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, अकासा एयर की बाजार हिस्सेदारी अगस्त में जुलाई के समान 5.5 प्रतिशत रही।

अगस्त 2026 में 10 प्रमुख हवाई अड्डों पर समय पर उड़ान संचालन (ओटीपी) के मामले में इंडिगो 91.5 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रही। इसके बाद अकासा एयर 90.5 प्रतिशत और एयर इंडिया समूह 83.9 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

इरडा का बीमा वेबसाइट पर 'डार्क पैटर्न' पर रोक लगाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को बीमा वेबसाइट पर 'डार्क पैटर्न' पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। इसमें ऐसी व्यवस्था भी शामिल है, जिसमें उत्पाद की विशेषताओं और कीमत की जानकारी देखने के लिए ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। 'डार्क पैटर्न' से आशय वेबसाइट या एप के ऐसे भ्रामक डिजाइन और तौर-तरीकों से है, जिनके जरिये यूजर को उनकी इच्छा के विरुद्ध बीमा खरीदने, अधिक प्रीमियम का भुगतान करने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए उकसाया जाता है।

इरडा ने व्यापक सुधारों के तहत 'बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव' पर एक परामर्श पत्र भी जारी किया है।

सरकार-जीवी स्वायत्त!

इतके दिवस निवडणूक आयोग सरकारची ‘शाखा’ असल्यासारखा वागतो, असा आरोप होत होता. आता तो सत्ताधारी पक्षाची ‘शाखा’ असल्यासारखे वागत असल्याची टीका होईल...

अलीकडे कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या नेकीविषयी नकारात्मक भाष्य करणे धोक्याचे वाटते. कारण ते खरे ठरतेच आणि या यंत्रणा वाटत होते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात अधिक वाईट निघतात. निवडणूक आयोग हा या विदारक सत्याचा ताजा नमुना. ‘लोकसत्ता’ने ताज्या संपादकीयात (२२ सप्टेंबर) निवडणूक आयोगाविषयी ‘कमिशन’ की ‘ओमिशन’? असा प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर दुसऱ्याच दिवशी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विशेष शोधवृत्तात मिळते. ‘‘निवडणूक आयोगात दुभंग’’ हे ते वृत्त. या तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या दोन सदस्यांनी गेल्या काही महिन्यात अनेक विषयांवर आपली मतभिन्नता नोंदवली आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून त्यास काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ या दोन सदस्यांवर आली. ही मतभिन्नता निवडणूक आयोगातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेसंदर्भात प्राधान्याने आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून मतदार याद्यांतील समावेशाविषयीच्या अर्जात या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीविना बदल कसे केले गेले असाही प्रश्न यातून उपस्थित होतो. निवडणूक आयोगाच्या बेपर्वा आणि मनमानी कार्यशैलीविषयी इतके दिवस फक्त बोललेच जात होते आणि त्या आयोगाच्या वर्तनातून त्यास पुष्टी मिळत होती. तथापि या वृत्ताने कथित स्वायत्त आयोगाच्या उरल्या-सुरल्या अब्रूची लक्तरे पूर्णपणे चव्हाट्यावर आणली असून त्यामुळे लज्जारक्षणापुरते काही शोधण्याची वेळ या घटनात्मक यंत्रणेवर आली आहे. देशाचा निवडणूक आयोग इतका बे-आबरू आतापर्यंत कधी झाला नव्हता. ते श्रेय निःसंशय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे. ते त्यांच्या पारड्यात पुरेपूर घालून आता या वृत्तानंतर जे झाले वा होत आहे त्याविषयी.

पहिला मुद्दा या वृत्तानंतरच्या घटनांत. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र, स्वायत्त घटनात्मक यंत्रणा. तिच्या बचावार्थ भाजपच्या वाक्वीरांनी मैदानात उतरण्याची काय गरज? निवडणूक आयुक्तांचे दौर्बल्य वैधानिक मुद्द्यांवर दिसले असेल/नसेल. पण आयोग मुखदुर्बल निश्चितच नाही. त्यांचा तो बचाव करण्यास सक्षम असेलच. तरी भाजपस तो करण्याची गरज का वाटते? केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागावर आरोप झाला? भाजप समर्थन करणार. सक्तवसुली संचालनालयावर (ईडी) टीका झाली? बचावार्थ आहेच भाजप. बाजारपेठ नियंत्रक ‘सेबी’च्या कार्यशैलीवर कोणी आक्षेप घेतले? उत्तर भाजप देणार. आताही तेच. हे काय सुरू आहे? निवडणूक आयोगातील दुभंग चव्हाट्यावर आणणाऱ्या या वृत्तांतात आयोगाविषयी, त्यातही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीविषयी, काही अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यास थेट उत्तर देण्याऐवजी निवडणूक आयोग स्वसमर्थनार्थ काहीतरी गोलमाल बचाव करतो आणि भाजप मात्र त्यांच्या वतीने हिरिरीने मैदानात उतरतो हे काय दर्शवते? या संपूर्ण वृत्तात भाजपवर काहीही आरोप नाही की त्या पक्षाचा उल्लेख नाही. तेव्हा ज्ञानेशकुमार यांच्या नावे जाळलेल्या मिरच्या भाजप नेतृत्वाच्या नाकास का झोंबाव्यात? भाजपची मदत ज्ञानेश कुमारांनी मागितली होती काय? मागितली असेल तर का, आणि नसेल तर मग भाजपची ही स्वयं-सेवा काय दर्शवते?

दुसरा प्रश्न ज्ञानेश कुमार यांच्या दोन सहकारी आयुक्तांच्या पत्रातील महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी हे अन्य दोन निवडणूक आयुक्त मतदार यादी नोंदणी प्रक्रियेच्या केंद्रीकरणास विरोध करतात; त्याबाबत. गोवा राज्यातील मतदार याद्यांबाबत ही बाब प्रथम इतकी स्पष्टपणे दिसून आली. निवडणूक आयोगाच्या तेथील अधिकाऱ्यांनी सर्व ती छाननी केल्यानंतर काही मतदारांची नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली. या मतदारांविषयीचे सर्व आक्षेप फेर पडताळणी प्रक्रियेत दूर झाले. त्यानंतर गोव्यातील स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही नावे यादीत पुन्हा समाविष्ट

...ती अस्थानी नसेल. अशा या तथाकथित स्वायत्त यंत्रणेविरोधात आता सर्व विरोधी पक्षीयांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरावे.

करण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाला. स्थानिक निवडणूक अधिकारी तसे का करू शकले नाहीत, यामागील कारण अत्यंत गंभीर आहे. ते असे की मतदार याद्यांत नाव समाविष्ट करण्याची संगणकीय प्रक्रिया संपूर्णपणे आयोगाच्या दिल्ली मुख्यालयात केंद्रीभूत करण्यात आल्याचे हे दोन निवडणूक आयुक्त म्हणतात. हे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याखेरीज अन्य कोणी करूच शकत नाही. तसे ते त्यांनी केले असेल तर त्यामुळे मतदार यादी प्रक्रियेत मूलगामी बदल होणार असून तो करण्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांस आहेत काय? ते देण्याबाबत आवश्यक घटनादुरुस्ती वा नियम-बदल केंद्र सरकारने केव्हा केले? या ‘बदलां’मुळे राज्य वा मतदारस्तरीय निवडणूक आयोग प्रमुख वा अधिकारी या पदाचे अवमूल्यन होऊन हा अधिकारी वर्ग केवळ सांगकाम्या कारकून ठरतो. राज्याराज्यांतील यंत्रणेस हे मान्य आहे काय? भाजप-शासित राज्ये या ‘बदलां’स नंदीबैलाप्रमाणे होकार देतीलही. पण इतका मोठा बदल करण्याचा अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांस मुदलात आहे काय?

तिसरा मुद्दा आयोगाच्या खुलाशाबाबत. ‘‘आमच्यात मतभेद नाहीत’’, ‘‘आम्ही तिघे एकत्र एकदिल’’ वगैरे भंपक खुलासा हा आयोग करतो. तो त्यांना करावाच लागेल. ते समजून घेता येईलही. पण ज्ञानेश कुमारेतर अन्य दोन आयुक्तांनी आयोगाच्या कामकाजाविरोधात थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांचा दरवाजा ठोठावला होता, त्याचे काय? मंत्रिमंडळ सचिव हे प्रशासनाचे प्रमुख असतात. निवडणूक आयोग हा शासकीय प्रशासनाचा भाग आहे काय? असेल तर तो तसा कधी झाला? नसेल तर मग मंत्रिमंडळ सचिवाकडे दाद मागण्याची गरज या दोन आयुक्तांस का वाटली? मंत्रिमंडळ सचिवांनी त्यास कसा प्रतिसाद दिला? आपले दोन सहकारी आपल्या विरोधात मंत्रिमंडळ सचिवाकडे औपचारिक तक्रार करत असतील तर त्यावर ज्ञानेश कुमार यांनी काही तरी मत व्यक्त केलेच असेल. ते काय? आयोगाच्या आजच्या ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ खुलाशात यावर काहीच कसे भाष्य नाही? खरे तर या मुद्द्यावरही आयोगाची बाजू स्पष्ट करण्याची जबाबदारी भाजपने घ्यायला हवी होती. पण या आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आयोग आणि त्याचा पाठीराखा भाजप दोघेही मौन बाळगत असतील तर त्यातून काय ध्वनित होते?

निवडणूक आयोग-नामे घटनात्मक यंत्रणेचे वस्त्रहरण करणारे हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर सरकारच्या ‘मांडीवरील माध्यमे’ खडबडून कामाला लागली. आयोगाच्या तीन सदस्यीय आयोगातील हे मतभेद हे कसे खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण आहे वगैरे पोपटपंची हे माध्यम-राघू करताना दिसतात. ते त्यांच्या वकुबाप्रमाणेच म्हणायचे. पण यातही मुद्दा असा: आयोगाच्या तीनपैकी दोन सदस्यांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा जर आपले आक्षेप/मतभेद लेखी नोंदले असतील तर त्या लेखी आक्षेपांस मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लेखी उत्तर दिले असेल. तसे ते देणे अपेक्षित आहे. त्या उत्तरांतून या आक्षेपांचे/मतभेदांचे निराकरण झाले असणार आणि त्यामुळे या दोघांचे समाधानही झाले असणार. कारण त्यानंतर हे सगळे निर्णय ‘बहुमता’ने घेतले गेले. तसे असेल तर मग आयोगाने या शंकांचे निरसन करणारा पत्रव्यवहार वा खुलाशाच्या नोंदी खुल्या कराव्यात. ज्ञानेश कुमार तसे करत नसतील तर आयोग-रक्षणकर्त्या भाजपने त्यांना ते तसे करण्यास भाग पाडावे. त्यामुळे सगळाच प्रश्न मिटेल. मात्र यात एक छोटीशी मेख आहे. ती अशी की आयोगासंदर्भातील २०२३ च्या कायद्यानुसार आयोगाचे सर्व निर्णय हे शक्य तितक्या एकमताने; एकमत न झाल्यास बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित आहे. पण दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा या आयोग सदस्यांनी विरोध नोंदवूनही त्याची दखलच घेतली न जाणे याला काय म्हणणार?

इतके दिवस निवडणूक आयोग सरकारची ‘शाखा’ असल्यासारखा वागतो, असा आरोप होत होता. आता तो सत्ताधारी पक्षाची ‘शाखा’ असल्यासारखे वागत असल्याची टीका होईल. ती अस्थानी नसेल. अशा या सरकार-जीवी स्वायत्त यंत्रणेविरोधात आता सर्व विरोधी पक्षीयांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरावे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली नाही तर तोच एक मार्ग उरतो.

वर्तमानाला प्रश्न विचारणे हेच खरे स्मरण!

लेख

अरुण वाघ
wagharun1963@gmail.com

२४ सप्टेंबर १८७३ हा सत्यशोधक समाजाचा स्थापना दिन. आज त्या काळातील आव्हाने जशीच्या तशी अस्तित्वात नाहीत. पण महात्मा फुले यांनी तत्कालीन आव्हानांना प्रश्न विचारण्याचे जे धैर्य दिले, ते आपण वर्तमानातही अबाधित ठेवले पाहिजे.

महात्मा जोतिराव फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी केलेली सत्यशोधक समाजाची स्थापना हा आधुनिक भारताच्या सामाजिक इतिहासातील एक निर्णायक टप्पा होता. कारण फुले यांनी केवळ काही सामाजिक रूढींना विरोध केला नाही; त्यांनी ज्या ज्ञानव्यवस्थेने त्या रूढींना पवित्रता, वैधता आणि नैतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले होते, त्या संपूर्ण ज्ञानसत्तेलाच प्रश्न विचारले. हेच सत्यशोधक चळवळीचे खरे क्रांतिकारकत्व आहे.

पर्यायी ज्ञानव्यवस्था उभारण्याची चळवळ

फुले यांच्या कार्याकडे केवळ ‘समाजसुधारक’ म्हणून पाहिले तर त्यांच्या विचारांची व्याप्ती कमी होईल. राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किंवा अन्य सुधारकांच्या परंपरेतील काही प्रश्नांशी फुले यांचे साधर्म्य असले तरी फुले यांची भूमिका अधिक मूलगामी होती. त्यांनी विचारले- समाजात विषमता का आहे? जन्मतः श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ कोणी ठरवते? ज्ञानावर काहींची मक्तेदारी का असावी? धार्मिक विधींच्या नावाखाली मध्यस्थांचे वर्चस्व का निर्माण झाले? शूद्र-अतिशूद्र आणि स्त्रियांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा अर्थ काय आहे? फुले यांनी परिणामांवर नव्हे, तर विषमतेच्या संरचनात्मक मुळांवर प्रहार केला. त्यामुळे सत्यशोधक समाज ही केवळ सामाजिक सुधारणा करणारी संस्था नव्हती. ती एक प्रकारची पर्यायी ज्ञानव्यवस्था उभारण्याची चळवळ होती.

ज्ञानाच्या ब्राह्मणी मक्तेदारीचे टीकाकार

‘सत्यशोधक’ या नावाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. भारतीय पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थेत सत्याचा अधिकार विशिष्ट धार्मिक-ज्ञानसत्तेकडे असल्याची कल्पना निर्माण झाली होती. फुले यांनी या अधिकारालाच आव्हान दिले. त्यांच्या विचाराचा गाभा असा होता की सत्य कोणाच्या जन्मजात मालकीचे नसते. ज्ञान मिळवण्यासाठी जन्माधारित पात्रता लागत नाही. ईश्वर, धर्मग्रंथ किंवा परंपरेच्या नावाने सांगितले गेले म्हणून एखादी गोष्ट सत्य ठरत नाही. तिची चिकित्सा करावी लागते. आजच्या भाषेत सांगायचे तर ही ज्ञानाची लोकशाही आहे. म्हणूनच फुले हे केवळ जातिव्यवस्थेचे टीकाकार नव्हते; ते ज्ञानाच्या ब्राह्मणी मक्तेदारीचे मूलगामी टीकाकार होते.

‘ब्राह्मण’ आणि ‘ब्राह्मण्य’ यातील फरक

फुले यांचा संघर्ष जन्माधारित श्रेष्ठत्वाच्या विचारसरणीविरुद्ध होता. म्हणजेच प्रश्न ‘ब्राह्मण व्यक्ती’चा नसून ब्राह्मण्यवादी सामाजिक रचनेचा आहे. जातीनुसार श्रेष्ठत्व, धार्मिक मध्यस्थी, ज्ञानावरील नियंत्रण आणि जन्माधारित सामाजिक अधिकार यांना वैधता देणारी मानसिकता म्हणजे ब्राह्मण्यवाद, असा व्यापक अर्थ फुले यांच्या सामाजिक संघर्षातून दिसतो.

जात आणि पितृसत्तेच्या परस्परसंबंधाला आव्हान

सत्यशोधक चळवळीचे विश्लेषण जोतिरावांपुरते मर्यादित ठेवणे ही मोठी ऐतिहासिक चूक ठरेल. सावित्रीबाई फुले या ह्या क्रांतीच्या सहनिर्मात्या होत्या. स्त्रीशिक्षण, मुलींच्या शाळा, विधवा स्त्रियांचे प्रश्न, बालहत्या प्रतिबंधाचे कार्य, स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा स्वीकार–या सर्व क्षेत्रांत फुले दाम्पत्याने जे कार्य केले, त्यातून एक मूलभूत तत्त्व पुढे आले की स्त्रीमुक्तीशिवाय सामाजिक मुक्ती पूर्ण होऊ शकत नाही. यामुळे फुले यांची चळवळ केवळ जातिविरोधी नव्हती; ती जात आणि पितृसत्ता यांच्या परस्परसंबंधालाही आव्हान देणारी होती.

शिक्षण हे मुक्तीचे साधन

म. फुले यांच्या विचारात शिक्षणाला असाधारण महत्त्व आहे. शिक्षण म्हणजे माणसाला स्वतःच्या गुलामगिरीची जाणीव करून देणारे साधन. म्हणूनच शूद्र-अतिशूद्र आणि स्त्रियांना शिक्षण देणे हे त्या काळात सामाजिक सत्तेच्या संरचनेवर केलेले आक्रमण होते. ज्याच्या हातात ज्ञान असते, त्याच्या हातात अर्थनिर्णयाची शक्ती असते. फुले यांनी ही बाब फार लवकर ओळखली. त्यामुळे शिक्षण हे मुक्तीचे साधन आहे, हा त्यांचा आग्रह होता.

पर्यायी सामा. संस्कृती निर्माण करण्याची चळवळ

जोतिबा फुले यांनी धर्माच्या नावावर सांगितल्या जाणाऱ्या नैतिक मूल्यांना नव्हे, तर धर्माच्या नावाने निर्माण झालेल्या सामाजिक वर्चस्वाला प्रश्न विचारले. माणूस आणि अंतिम सत्य यांच्यामध्ये जन्माधारित धार्मिक मध्यस्थ का असावा, या प्रश्नातून सत्यशोधक विवाहासारख्या पर्यायी सामाजिक पद्धती विकसित झाल्या. फुले केवळ ‘कर्मकांड वाईट आहे’ असे म्हणत थांबत नाहीत. ते कर्मकांडाला पर्यायी सामाजिक व्यवहार निर्माण करतात. म्हणून सत्यशोधक चळवळ ही केवळ नकाराची चळवळ नव्हती; ती पर्यायी सामाजिक संस्कृती निर्माण करण्याची चळवळ होती.

शेतकरी आणि आर्थिक शोषणाचा प्रश्न

‘शेतकऱ्याचा असूड’ हा फुले यांच्या सामाजिक अर्थशास्त्रीय विचारांचा महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. त्यांच्या मते शेतकरी केवळ जातीय व्यवस्थेच्याच नव्हे तर महसूलव्यवस्था, सावकारी, प्रशासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक सत्तासंबंध यांच्या गुंतागुंतीत अडकलेला होता. जात आणि वर्ग यांना पूर्णपणे वेगळे करून सामाजिक शोषण समजत नाही. भारतीय परिस्थितीत आर्थिक शोषणाला जातीय संरचना कशी आकार देते, हा प्रश्न फुले यांच्या विचारांत महत्त्वाचा आहे.

‘बहुजन’ या संकल्पनेची पायाभरणी

‘बहुजन’ ही केवळ लोकसंख्येची संज्ञा नाही. ती सत्तेच्या प्रश्नाशी जोडलेली आहे. ज्यांच्याकडे संख्या आहे पण ज्ञानसत्ता, सांस्कृतिक सत्ता आणि राजकीय सत्ता नाही, अशा समाजघटकांनी स्वतःची सामाजिक ओळख आणि राजकीय चेतना निर्माण करावी, हा फुले यांच्या विचारांचा एक महत्त्वाचा आशय आहे.

फुले ते आंबेडकर : विचाराच्या विस्ताराचा प्रवास

फुले आणि आंबेडकर दोघांचे ऐतिहासिक संदर्भ, राजकीय साधने आणि बौद्धिक विकास वेगळे आहेत. पण काही मूलभूत धागे स्पष्टपणे जोडलेले आहेत. शिक्षण-समता-जातिनिर्मूलन-सामाजिक प्रतिनिधित्व-मानवी प्रतिष्ठा-विवेक. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महात्मा फुले यांना आपल्या वैचारिक गुरूंमध्ये स्थान दिले, हे या वैचारिक संवादाचे महत्त्व दाखवते. मात्र आंबेडकरांनी फुले यांच्या वारशाला पुढे नेत संविधान, प्रतिनिधित्व, राजकीय सत्ता, कायदे, सामाजिक लोकशाही आणि जातिनिर्मूलनाचा अधिक संस्थात्मक कार्यक्रम उभा केला. म्हणून फुले ते आंबेडकर हा प्रवास ‘पुनरावृत्ती’चा नसून विचाराच्या विस्ताराचा आहे.

मर्यादांची चिकित्सा

म. फुले यांचे मोठेपण मान्य करताना त्यांना प्रश्न विचारणे हेच त्यांच्या सत्यशोधक परंपरेशी अधिक प्रामाणिक ठरेल. सत्यशोधक समाज व्यापक ग्रामीण आणि बहुजन समाजात किती खोलवर संघटित झाला? त्याचे संघटनात्मक सातत्य किती राहिले? फुले यांच्या निधनानंतर या चळवळीचे नेतृत्व आणि वैचारिक दिशा कशी बदलली? पुढे सत्यशोधक नावाचा वापर करणाऱ्या विविध प्रवाहांमध्ये फुले यांच्या मूलगामी विचारांचे किती जतन झाले, हे प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.

आजच्या काळात ‘सत्यशोधक’ म्हणजे काय?

आज जोतिबा फुलेंच्या काळातील आव्हाने जशीच्या तशी अस्तित्वात नाहीत. पण त्यांची रुपांतरे झाली आहेत. पूर्वी ज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोथी, पुरोहित आणि सामाजिक रूढी महत्त्वाची भूमिका बजावत होत्या. आज समाज माध्यमे, अल्गोरिदम, बनावट माहिती, इतिहासाचे विकृतीकरण, डिजिटल विषमता, ज्ञानाचे कॉर्पोरेट केंद्रीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील पूर्वग्रह ही नवी आव्हाने आहेत. म्हणून आजचा सत्यशोधक माणूस केवळ अंधश्रद्धेला प्रश्न विचारणारा नाही, तर माहितीची सत्यता तपासणारा नागरिक असला पाहिजे.

सार्वजनिक विवेक

फुले यांच्या वारशाचे आजच्या काळातील सर्वांत महत्त्वाचे रूप ‘सार्वजनिक विवेक’ या संकल्पनेत दिसते. सार्वजनिक विवेक म्हणजे प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, असहमतीचा स्वीकार, मानवी समानतेची जाणीव, विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन आणि कोणत्याही सत्तेच्या दाव्याची चिकित्साचालाही अपवाद करत नाही. याच अर्थाने सत्यशोधक परंपरा स्वतःलाही प्रश्न विचारते. त्यामुळे सत्यशोधक समाजाचा इतिहास हा एका संस्थेचा इतिहास नसून भारतीय समाजाने ‘कोणाला माणूस मानायचे, कोणाला ज्ञानाचा अधिकार द्यायचा आणि सामाजिक सत्य कोण ठरवणार?’ या तीन मूलभूत प्रश्नांवर केलेल्या संघर्षाचा इतिहास आहे.

महात्मा जोतिराव फुले यांची खरी क्रांती इथे आहे. त्यांनी वंचितांना केवळ सहानुभूती दिली नाही; त्यांना ज्ञानाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी स्त्रियांना केवळ संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला नाही; त्यांना शिक्षण आणि स्वायत्त व्यक्तिमत्त्वाचा अधिकार दिला. त्यांनी शूद्र-अतिशूद्रांना केवळ सामाजिक दयेचे पात्र मानले नाही; त्यांना इतिहासाचे आणि समाजपरिवर्तनाचे कर्ते मानले. धर्म, परंपरा व सामाजिक प्रतिष्ठा यांना अंतिम सत्य मानण्याऐवजी ‘सत्य शोधा’ असे सांगितले.

त्यामुळे सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनादिनी जोतिबा फुले यांच्या प्रतिमेला हार घालणे, त्यांच्या नावाने घोषणा देणे, त्यांच्या विचारांचे केवळ गौरवीकरण करणे ही त्यांना खरी आदरांजली नव्हे. तर, ज्या प्रश्नांमुळे जोतिबा अस्वस्थ झाले, ते प्रश्न आज कोणत्या नव्या रूपात आपल्यासमोर उभे आहेत, हे शोधणे, ही त्यांना खरी आदरांजली आहे.

जातीचे रूप बदलले आहे का? ज्ञानावरील मक्तेदारीचे स्वरूप बदलले आहे का? स्त्रीची गुलामी कोणत्या नव्या रूपात टिकून आहे? श्रमाला प्रतिष्ठा का मिळत नाही? बहुजनांचा ज्ञाननिर्मितीतील सहभाग किती आहे? शिक्षण मुक्तीचे साधन राहिले आहे की बाजाराचे? तंत्रज्ञान विषमता कमी करीत आहे की काही नव्या विषमता निर्माण करीत आहे? लोकशाहीत विवेक आणि असहमतीसाठी किती अवकाश आहे? हे प्रश्न विचारणे म्हणजेच सत्यशोधक होणे. जोतिबांचे खरे स्मरण हे वर्तमानाला प्रश्न विचारणारे असले पाहिजे.

फुले यांची परंपरा पुतळ्यात नाही, प्रश्न विचारण्याच्या धैर्यात आहे. ती घोषणेत नाही, विवेकात आहे. ती केवळ जातिविरोधात नाही, प्रत्येक प्रकारच्या मानवी अवमूल्यनाविरोधात आहे. आणि ती भूतकाळाची स्मृती नसून भविष्याच्या समताधिष्ठित समाजाची बौद्धिक पूर्वतयारी आहे.

याच अर्थाने २४ सप्टेंबर १८७३ हा केवळ सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा दिवस नाही; तो भारतीय समाजात ‘सत्य कोण ठरवणार?’ हा मूलभूत लोकशाही प्रश्न सार्वजनिकपणे विचारला जाऊ लागल्याचा दिवस आहे.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

जातीपेक्षा संघर्ष पाहावा

‘**जात सांगणेच** बरे...’ हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) वाचून एक प्रश्न पडला- आपण प्रत्येक दुःखामागे एखादी ओळख शोधण्याच्या इतके आहारी गेलो आहोत का? विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमागे अनेक कारणे असू शकतात. अभ्यासाचा प्रचंड दबाव, अपेक्षांचे ओझे, आर्थिक परिस्थिती, घरचे वातावरण, एकटेपणा, अपयशाची भीती, संस्थेतील वातावरण आणि अर्थातच जातीय किंवा सामाजिक भेदभाव यापैकी एखादे किंवा अनेक कारणे एकत्र असू शकतात. त्यामुळे एखादी घटना घडली की लगेच तिला जातीय रंग देणे जितके चुकीचे, तितकेच जातीय भेदभावाची शक्यता नाकारून मोकळे होणेही धोकादायक. जात हा आपल्या समाजाच्या वास्तवाचा भाग आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याकडे तो ‘कोणत्या जातीचा’ याऐवजी ‘त्याचा संघर्ष किती आहे,’ या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्याची जात त्याच्या मृत्यूनंतर चर्चेचा विषय होण्यापेक्षा, तो जिवंत असताना त्याच्याकडे माणूस म्हणून पाहिले जाते का, हा प्रश्न आपल्या शिक्षणव्यवस्थेने स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे.

■ **ऊर्जा भिंगे**, पुणे

मनातील श्रेष्ठ-कनिष्ठता संपवा

‘**जात सांगणेच** बरे’ हा अग्रलेख वाचला. आयआयटीतील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येला जातीय छळाची परिणती मानायचे की नाही, हा तपासाचा विषय असू शकतो. पण प्रत्येक घटनेला जातीय चष्म्यातून पाहणे आणि जातीय पूर्वग्रहांचे अस्तित्वच नाकारणे ही दोन्ही टोके आपल्याला मूळ प्रश्नापासून दूर नेतात. विद्यार्थ्यांमध्ये श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची भावना निर्माण होते तेव्हा गुणवत्ता ही ज्ञानाची कसोटी न राहता सामाजिक प्रतिष्ठेची खूण ठरते. प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या प्रत्येक अपयशामागे केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक किंमतही दिसत असते. अशा वेळी संस्थेने संकट येऊच नये यासाठी आधाराची व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. केवळ बाहेर दिसणारी जातीयता झटकून उपयोग नाही. आपण जातीअंताची भाषा करतो; पण जात आपली ओळख, अस्मिता, राजकारण आणि सामाजिक व्यवहार यांत नवनव्या रूपांनी परत येते. जात संपवायची तर केवळ जातीयतेच्या उघड अभिव्यक्तीला विरोध करून चालणार नाही. मनातील श्रेष्ठ-कनिष्ठता संपवावी लागेल.

■ **डॉ. राजेंद्र तांबिले**, सातारा

नागरिकांशी बांधिलकी हवी

‘**सरकारी कृपेने** रुग्णांची लूट!’ हा डॉ. अनंत फडके यांचा लेख (२३ सप्टेंबर) वाचला. औषधांचा उत्पादनखर्च आणि रुग्णांकडून वसूल केली जाणारी किंमत यांतील प्रचंड तफावत धक्कादायक आहे. सरकार केवळ मर्यादित औषधांवर किंमत-नियंत्रण ठेवत असल्यामुळे आजारपण हे औषध कंपन्या, वितरक आणि बाजारातील इतर घटकांसाठी नफ्याचे साधन झाले आहे. आपण लोककल्याणकारी राज्य आहोत. अशा राज्यात नागरिकांना परवडणारी आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. मग जनतेने निवडून दिलेले खासदार आणि आमदार औषधांच्या अवाजवी किमतींबाबत संसदेत व विधानसभेत आवाज का उठवत नाहीत? लोकप्रतिनिधी, औषधांच्या किमतीमुळे सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक कंबरडे मोडत असताना मौन का बाळगतात? राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी, औषध कंपन्यांचे लॉबिंग आणि धोरणनिर्मात्यांशी असलेले संबंध यांबाबत संपूर्ण पारदर्शकता आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी कंपन्यांच्या नफ्याशी नव्हे, तर नागरिकांच्या आरोग्याशी असली पाहिजे.

■ **फ्रान्सिस आल्मेडा**, निर्मळ (वसई)

जनऔषधीची जाहिरातबाजी

‘**सरकारी कृपेने** रुग्णांची लूट!’ हा डॉ. अनंत फडके यांचा लेख वाचला. २०१३ च्या धोरणानुसार आज औषध नियंत्रणाचा आवाका घटला असून आवश्यक औषधांच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. जन-औषधी दुकानांमधील औषधांच्या विक्रीचा वाटा एकूण औषध विक्रीच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. या योजनेचा वापर धोरणात्मक बदलांपेक्षा केवळ राजकीय प्रसिद्धी आणि जाहिरातबाजीसाठी अधिक केला जातो. औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवणे शक्य असतानाही, सामान्य रुग्णांची जी आर्थिक लूट होत आहे, ती ‘सरकारी कृपे’नेच सुरू आहे.

■ **चंद्रशेखर दाभोळकर**, भांडुप (मुंबई)

अन्वयार्थ

पश्चिम घाटाविरुद्ध मात्र एकमत...!

वातावरणातील बदलाचे चटके सर्वत्र जाणवू लागले आहेत. महाराष्ट्रसह निम्म्या देशात यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला. युरोपात उष्णतेच्या लाटेच्या प्रचंड झळा बसल्या. एवढे होऊनही राजकारणी काही त्यातून धडा घेण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीत. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कर्नाटक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल फेटाळण्याचा विशेष अधिवेशनात केलेला ठराव. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मांडलेल्या ठरावाला भाजपनेही साथ दिली. परिणामी एकमताने हा ठराव मंजूर झाला. पश्चिम घाट हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसर. कर्नाटकातील बेळगावीपासून म्हैसुरू, हसन, कुर्ग ते दक्षिण कन्नड असे किनारपट्टी भाग, दक्षिण कर्नाटकचा पट्टा, तमिळनाडू व केरळच्या सीमेला लागून असलेल्या १० जिल्ह्यांमधील २०,६६८ चौरस कि.मी. परिसर आणि १,४४९ गावे कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही गावे ३३ तालुक्यांमध्ये येतात. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागात व्यापारी किंवा कोणत्याही बांधकामास परवानगी नसते. या परिसरात कोणतेही कारखाने सुरू करता येत नाहीत. केंद्र सरकारच्या मसुद्यात समाविष्ट असलेल्या भागात पिकाखालील जमीन, घरे, खासगी जमीन तसेच सार्वजनिक वापराच्या जागेचा समावेश करण्यात आल्याचा कर्नाटक सरकारचा आक्षेप आहे. यामुळे कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाचा फेरविचार करण्याची शिफारस कर्नाटक विधिमंडळाने केली आहे. तसेच कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारचा मसुदा फेटाळण्यात येत असल्याचा ठरावही करण्यात आला. पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागात शेतजमीन, घरे, खासगी जमिनींचा समावेश करू नये, अशा मागण्याही कर्नाटक विधिमंडळाने केल्या आहेत.

केरळच्या धर्तीवर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागाचे फेरसर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट अहवालात समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचे योग्यपणे सर्वेक्षण करण्यात आले नव्हते. उपग्रहाच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसर निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळेच हा अहवाल अशास्त्रीय असल्याने या भागाचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याची कर्नाटक सरकारची भूमिका आहे.

पश्चिम घाट वाचविण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या अहवालाला काँग्रेसने विरोध केला. पण गेल्याच वर्षी काँग्रेसने दिल्लीपासून हरियाणा, राजस्थान, गुजरातपर्यंत पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगामध्ये पर्यावरणबाबत सुधारणा करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता. कर्नाटकात पर्यावरण संवेदनशील परिसराला विरोध करायचा आणि दिल्ली, राजस्थानात अरवली पर्वतरांगामधील खाणी, बांधकामांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, अशी भूमिका घ्यायची, हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा झाला. पश्चिम घाटातीलच केरळमधील वायनाडमध्ये दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या भूस्खलनात ४०० पेक्षा अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते, तर हजारो विस्थापित झाले होते. अजूनही तेथील लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. हिमाचल प्रदेशला अतिवृष्टी, पूर व त्यातून झालेल्या भूस्खलनाचा मोठा फटका बसला होता. नेपाळमध्ये गेल्याच महिन्यात हजारो लोक पुरात वाहून गेले. त्यांचा अजूनही ठावठिकाणा लागलेला नाही. वायनाडमधील दुर्घटनेत मानवी चुकाच कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. वायनाडमध्ये डोंगरावर बेसुमार वृक्षतोड तसेच मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे करण्यात आली होती. बोगद्याच्या कामाकरिता डोंगर उतरणीचा भाग वळविण्यात आला होता. यातून जमीन भुसभुशीत झाली. खरे तर वायनाडच्या दुर्घटनेचा पश्चिम घाटातील सर्व राज्यांनी धडा घेणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र सरकारनेही पश्चिम घाटातील शेकडो गावे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील पट्ट्यात समाविष्ट करू नये, अशीच भूमिका घेतली. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालांमुळे पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना बाधा येते, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारने केला होता. राज्य सरकारच्या भूमिकेवर पर्यावरणवाद्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र... कोणत्याही राज्यातील राज्यकर्त्यांना पर्यावरणाच्या संरक्षणापेक्षा बांधकामे, पायाभूत सुविधा यात अधिक रस असतो. पर्यावरणाच्या प्रश्नांमुळे सर्वसामान्य लोकांचे नुकसान होऊ नये, ही भूमिका काही प्रमाणात योग्य असली तरी सरसकट विरोधही भविष्याचा विचार करता चुकीचा आहे. एरवी भाजप व काँग्रेसचे नेते परस्परांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हितसंबंध जपण्यात मात्र सगळे एकाच माळेचे मणी!

मतभेदावर निवडणूक आयोगाची सारवासारव!

भिन्न निरीक्षणे निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अंतर्गत मतभेद आणि भिन्न निरीक्षणे ही कोणत्याही बहुसदस्यीय संस्थेतील नियमित निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी निवेदनाद्वारे दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर तीव्र आक्षेप घेतल्याचे सविस्तर वृत्त 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिले. या वृत्ताचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खंडन केलेले नाही. उलट, मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयप्रक्रियेला अन्य दोन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी लेखी विरोध केल्याची अप्रत्यक्षरित्या कबुली दिल्याचे आयोगाच्या निवेदनावरून स्पष्ट होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत नोंदी वा निरीक्षणांपैकी काही निवडक बाबी समोर आणल्याने संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही, असा दावाही आयोगाने निवेदनाद्वारे केला. मात्र, या निवेदनामध्ये 'द इंडियन एक्स्प्रेस'चा उल्लेख आयोगाने टाळला आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात बुधवारी टिकेची झोड उठवली. त्यावर सुरुवातीला, आयोगाच्या वतीने सूत्रांच्या आधारे, आयोगाचे निर्णय सहमतीने घेतले गेल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र, नंतर आयोगाच्या वतीने संपूर्ण प्रकरणावर अधिकृतपणे निवेदन प्रसिद्ध करून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

केंद्रीय निवडणूक आयोग ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४अंतर्गत कार्य करणारी बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे. आयोगाच्या सदस्यांकडून मसुद्याच्या स्तरावर मांडण्यात येणाऱ्या सूचना, तांत्रिक निरीक्षणे, लेखी नोंदी आणि प्रशासकीय प्रश्न हे संस्थेतील अंतर्गत तपासणी व समतोल राखण्याच्या प्रक्रियेचाच भाग आहेत. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळी मते मांडली जाणे स्वाभाविक आहे, असे आयोगाच्या निवेदनात नमूद केले आहे.

'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी, गेल्या दहा महिन्यांत मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, तसेच वगळणे, मतदारयाद्यांमधील फेरबदल आणि निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीच्या कार्यपद्धतीसह विविध मुद्द्यांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांनी हे आक्षेप लेखी स्वरुपात मांडले आहेत. त्यांनी केंद्रीय सचिवांकडेही हे आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेषतः नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या 'फॉर्म-६'मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतले होते. या बदलासाठी निवडणूक नोंदणी नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. 'फॉर्म-६'मधील बदल 'अनधिकृत' असल्याचा आक्षेप नोंदवत तो तातडीने मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, या आक्षेपांबाबत आयोगाने, अंतर्गत नोंदींचा अर्थ अंतिम निर्णयांशी जोडू नये, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

आयोगातील केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सूचना मांडण्याचा अधिकार आहे. वेगवेगळ्या सूचना आणि निरीक्षणे ही अंतिम निर्णयापूर्वीची विचारविनिमय प्रक्रिया आहे.
- **निवडणूक आयोगाचे निवेदन**

'संपूर्ण चित्र पाहणे आवश्यक'

गेल्या दहा महिन्यांतील काही निवडक अंतर्गत नोंदींवर भर देताना आयोगाने या कालावधीत घेतलेल्या इतर निर्णयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा केला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षभरात पूर्ण आयोगाने एकमताने अनेक निर्णय घेतले असून सुमारे ४० नवे उपक्रम आणि विविध निवडणूक सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये देशभरातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेचाही (एसआयआर) समावेश आहे. बिहार, केरळ, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडल्याचेही आयोगाने नमूद केले. या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रशासकीय यंत्रणेचे संचालन, विविध पातळ्यांवरील मंजुरी आणि आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली, असेही म्हटले आहे.

'डिजिटल प्रणाली सुरक्षित'

- 'ईसीआयनेट'सह आयोगाच्या डिजिटल व्यासपीठांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवरही आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली.
- या प्रणाली अनधिकृत हस्तक्षेप, फेरफार किंवा छेडछाड रोखण्यासाठी कठोर माहिती-सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत चालवल्या जात आहेत.
- राष्ट्रीय पातळीवरील डिजिटल डेटाबेससाठी नियमित आयटी सुरक्षा तपासण्या आणि लेखापरीक्षण व्यवस्था असणे ही प्रमाणित सायबर सुरक्षा प्रक्रिया असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. 'ईसीआयनेट'चा वापर मर्यादित केल्याच्या मुद्द्यावरही अन्य दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता.
- मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे यासंबंधीची वैधानिक जबाबदारी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.
- 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या अन्य अहवालात 'ईसीआयनेट'च्या केंद्रीकृत व्यवस्थेबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
- काही प्रकरणांत स्थानिक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निर्णयांची डिजिटल प्रणालीवर नोंद करण्यास अडचणी आल्याचे वृत्तात स्पष्टपणे नमूद केले होते.
- घटनात्मक जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडण्यास आयोग कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाच्या निवेदनावरून निवडणूक आयोग तसेच इतर सर्व घटनात्मक संस्था लोकशाही पद्धतीने काम करत आहेत आणि देशातील लोकशाहीचे जतन करत आहेत हे स्पष्ट होते.
- **संबित पात्रा,** नेते, भाजप

ज्या राज्यांमध्ये मतदान यंत्रे ताब्यात घेण्यात आली, पळवण्यात आली, तिथे जुन्या मतदारयाद्यांच्या आधारे नव्याने निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्ञानेश कुमार यांना अटक करावी आणि त्यांच्या विरोधात फौजदारी खटला सुरू करावा.
- **ममता बॅनर्जी,** माजी मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

निवडणूक आयोगात जे काही झाले त्याची निष्पक्ष चौकशी केली जावी आणि जबाबदार व्यक्तींना उत्तरदायी ठरवले जावे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या स्फोटक वृत्तामुळे 'एसआयआर'नंतर घेतल्या गेलेल्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
- **एम. के. स्टॅलिन,** अध्यक्ष, द्रमुक

ज्ञानेश कुमारांना हटवा, विरोधकांची मागणी

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घटनात्मक संस्थेचे कामकाज 'हुकुमशाही पद्धतीने' चालवल्याचा आरोप करत, काँग्रेसने बुधवारी त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर नोंदवलेल्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर तसेच, ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर घणाघाती हल्लाबोल केला.

काँग्रेसचे कार्यकारिणी सदस्य, खासदार व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली. "मुख्य निवडणूक आयुक्तांना क्षणभर देखील पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा," अशी मागणी सिंघवी यांनी केली. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असून केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त 'समानांमधील प्रथम' आहेत, त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार नाहीत. इतर आयुक्तांना तितकेच अधिकार आहेत, असे सिंघवी म्हणाले. त्यासंदर्भात सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५च्या निकालाचा संदर्भ दिला.

'विशेष अधिवेशन झाल्यास महाभियोग प्रस्ताव'

"संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले तर विरोधी पक्षांचे खासदार ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुन्हा महाभियोग प्रस्ताव आणतील," असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले. ज्ञानेश कुमार हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांसाठी 'हॅचेट मॅन' म्हणून काम करत असल्याची गंभीर आरोप रमेश यांनी केला.

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पाठिंब्यानेच घेतले गेले आहेत. 'ज्ञानेशगेट'ची संपूर्ण पटकथा 'जी-२'ने (मोदी-शहा) लिहिल्याची टीकाही रमेश यांनी केली.

भाजपने लोकशाहीच्या हत्येसाठी स्वतंत्र कार्यालयच (निवडणूक आयोग) उघडले आहे. दोन बुलडोझर घेऊन लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. त्यासाठी एका बाजूला केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उभे केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय गृहमंत्रालय आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या आतही एक 'बुलडोझर' कार्यरत असल्याचे दोन आयुक्तांच्या आक्षेपामुळे उघड झाले आहे.
- **अभिषेक मनु सिंघवी,** सदस्य, काँग्रेस कार्यकारिणी

'महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूत पुन्हा निवडणुका घ्या'

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आक्षेपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबतच संशय निर्माण झाला असल्याने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व तमिळनाडूतील विधानसभा निवडणुका पुन्हा मतपत्रिकेवर घ्याव्यात, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केली. तसेच ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा असे ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्री या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या या मनमानी कारभाराचा समाचार घेतला. "तीनपैकी दोन आयुक्तांनीच काही निर्णयांवर आक्षेप घेतले असल्याचे समोर आल्याने आयोगाच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आम्ही विरोधी पक्ष सातत्याने निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराविरोधात बोलत होतो. त्यांना पुराव्याची जोड मिळाली आहे," असा दावा ठाकरे यांनी केला. त्यामुळे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूतील निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून या निवडणुका रद्द करा आणि तेथे पुन्हा मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या, असे ते म्हणाले.

राज्याच्या मतदारयादीतील बदलांवरूनही ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले, पण पुढे सहा महिन्यांत झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ४५ लाख नावे घुसवली गेली. त्यातलीच ४० लाख नावांवर आक्षेप घेऊन एसआयआरमधून वगळण्यात आली आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आयुक्तांची निवड निवडणुकीने का नाही?

निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीची तपासणी केली जाते; मात्र आयोगातील आयुक्त कुणाच्या मर्जीने नेमला जातो, त्या पदासाठी निवडणूक का होत नाही, असे प्रश्न ठाकरे यांनी विचारले. आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही पुनर्विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सत्तेची हाव आणि त्यासाठी लोकशाहीचा खून केला जातो आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमारांना तुरुंगात टाकून निवडणूक आयोगाचे चुकीचे निर्णय रद्द केले पाहिजेत.
- **उद्धव ठाकरे,** पक्षप्रमुख, शिवसेना

ठाकरेंचा कारभार म्हणजे 'जखम कपाळाला आणि पट्टी गुडघ्याला' असा सुरू आहे. निवडणुकीत आपला पराभव का झाला याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी ठाकरे केवळ निवडणूक आयोगावर खापर फोडण्याचे काम करत आहेत.
- **देवेंद्र फडणवीस,** मुख्यमंत्री

माजी मुख्य आयुक्तांचे 'एसआयआर'वर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : 'द इंडियन एक्स्प्रेस'चे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी आणि ओ. पी. रावत यांनी 'एसआयआर'वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कुरेशी यांनी यापूर्वी 'एसआयआर'च्या प्रक्रियेवर अनेक वेळा शंका उपस्थित केल्या आहेत. 'एसआयआर'मध्ये चुका झाल्या असतील तर जुन्या मतदारयाद्या पुन्हा वापरता येण्याची कायदेशीर शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले. कायद्याच्या दृष्टीने सदोष पुनरावलोकन पद्धतीने तयार केलेल्या मतदारयाद्यांच्या निवडणुका घेता येऊ शकतात का असा प्रश्न कुरेशी यांनी विचारला. तर, रावत यांनी 'एसआयआर'चा उल्लेख मतदारांच्या मनामध्ये भीती निर्माण केलेला 'फ्रँकेन्स्टाइन' असा केला. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या 'फॉर्म-६'मध्ये केलेले बदल अगदी चुकीचे आणि बेकायदा होते, असे २०१८मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेले रावत म्हणाले.

'पीटीआय व्हिडिओज'शी बोलताना रावत म्हणाले की, "ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे. निवडणूक आयोगात अशी गोष्ट क्वचितच घडली असेल. मी मुख्य आयुक्त असताना निर्णय एकमताने घेतले जातील, याची नेहमीच खबरदारी घेतली. 'एसआयआर'मुळे सर्वत्र मतदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. ही चांगली बाब नाही. हे आपल्या लोकशाहीसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे."

दुसरीकडे, "जर निवडणूक आयोगाचे निर्णय बहुमताने घेतले गेले नाहीत तर ते मूलभूतरित्या बेकायदा आहेत," असे एस.वाय. कुरेशी यांनी 'एएनआय'शी बोलताना स्पष्ट केले. एसआयआर वादावर सार्वजनिक पारदर्शकता असली पाहिजे, असे ते म्हणाले. गेल्या दीड वर्षात घेतल्या गेलेल्या सर्व निर्णयांची संपूर्ण यादी केली पाहिजे आणि त्याचे तपशील सार्वजनिक केले पाहिजेत, असे आवाहनही कुरेशी यांनी केले. कुरेशी २०१० ते २०१२ या कालावधी मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.

'ट्रम्प यांची धमकी ही आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांची कबुलीच!'

संयुक्त राष्ट्रे : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत इराणचा सर्वनाश करणारी दिलेली धमकी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे केल्याची कबुली असल्याचे म्हटले आहे.

"इराणबरोबर शांतता करार झाला नाही, तर इराणचा सर्वनाश करेन," असा इशारा ट्रम्प यांनी आमसभेतील भाषणात दिला. त्यावर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघेई यांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केलेली टिप्पणी म्हणजे त्यांनी पुन्हा पुन्हा इराणवर केलेले तेच ते आरोप होते. त्यांची विधाने हताश भावनेतून आली आहेत." लष्करी कारवाईसारखी कृती करण्याची धमकी देताना आमसभेचे व्यासपीठ वापरण्यावरही बघेई यांनी आक्षेप घेतला.

ट्रम्प यांनी आमसभेत इराणविरोधात टिप्पणी करताना इराणचे शिष्टमंडळ तेथून हलले नाहीत. त्याचे स्पष्टीकरण देताना बघेई म्हणाले, "इराणचे शिष्टमंडळ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या स्तरावरील होते. एक राजनैतिक अधिकारी कायम आमसभेच्या सत्रात उपस्थित असे. एखादयाच्या टिप्पणीमुळे आम्ही तिथून उठून गेलो, तर 'यूएन'मधील आम्ही आमचे कर्तव्य बजावू शकलो नाही, असे होईल."

आमसभेसारख्या ठिकाणी जगातील अनेक देश एकत्र येतात. अशा व्यासपीठाचा अशा धमक्यांसाठी वापर करणे हे बेकायदा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. हे सामर्थ्याचे लक्षण नक्कीच नाही.
- **इस्माईल बघेई,** प्रवक्ते, इराणचे परराष्ट्र मंत्रालय

विजयी कर्णधाराच्या पंचाचा निर्णय संशयास्पदच!

निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतील कार्यपद्धतीवर न्या. दीपंकर दत्ता यांची टिप्पणी

पीटीआय, नवी दिल्ली

"**क्रिकेटमध्ये जर** एखाद्या विजयी संघाच्या कर्णधाराने पंचांची निवड केली असेल, तर त्याने घेतलेला प्रत्येक निर्णय कितीही अचूक असला तरी त्यावर नेहमी संशयाची सूई राहिल," असे उदाहरण देत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये सरकारचा प्रभाव कसा असेल, याकडे बुधवारी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडण करण्याच्या पद्धतीवर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी क्रिकेटमधील रूपकाचा वापर केला. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करायच्या असतील, तर निवडणूक आयोग केवळ एक स्वतंत्र संस्था असून चालणार नाही, तर ती संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचेही दिसून आले पाहिजे, हे तत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

स्वातंत्र्य आणि तटस्थतेच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना, न्यायमूर्ती दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. निवड समितीमध्ये मंत्र्याचा समावेश केल्याने त्या समितीची 'संस्थात्मक तटस्थता' संपुष्टात येते, असे यासंदर्भातील याचिकेत म्हटले होते. "जर ही निवड समिती कार्यरत राहिली, तर निर्णय अपरिहार्यपणे २:१ अशा फरकाने कार्यकारी मंडळाच्या (सरकारच्या) बाजूने आणि प्रत्यक्षात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या बाजूने घेतला जाईल. निवड समितीमध्ये कार्यकारी मंडळाचे दोन सदस्य असल्याने, सरकारकडे प्रभावी नकाराधिकार असतो, असे ते म्हणाले.

निवडीवर पंतप्रधानांच्या प्रभावाची शक्यता अधिक

सुनावणीदरम्यान झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत न्या. दत्ता म्हणाले की, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यात मतभेद झाल्यास, मंत्र्याने पंतप्रधानांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. आधीच्या कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. २०२३च्या त्यात बदल करण्यात आला. नव्या तरतुदीनुसार, सरन्यायाधीशांना वगळून पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.

ज्ञानेश कुमार गोत्यात

(पान १ वरून)

दिल्याचे आयोगाच्या निवेदनावरून स्पष्ट होते.

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात बुधवारी टीकेची झोड उठवली. ज्ञानेश कुमार यांनी घटनात्मक संस्थेचे कामकाज 'हुकूमशाही पद्धतीने' चालवल्याचा आरोप करत, काँग्रेसने बुधवारी त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तर निवडणूक आयुक्तांमधील भिन्न मते पाहता यातून खऱ्या लोकशाहीचे प्रत्यंतर येते अशी प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना अटक करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व 'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून अटक करावी अशी मागणी केली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या ७३ सदस्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्यासाठी २४ एप्रिल २०२६ रोजी नोटीस दिल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले. संसदेचे अधिवेशन अजून संपलेले नाही त्यामुळे राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून देशातील जनतेला उत्तराची अपेक्षा असल्याचे खरगे यांनी नमूद केले. देशभरातून विविध पक्षाच्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीचा आग्रह धरला आहे.

कायदा काय सांगतो? 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, कार्यालयीन सेवेच्या अटी आणि शर्ती) कायदा, २०२३'चे कलम १८अंतर्गत असे नमूद करण्यात आले आहे की, आयोगाचे सर्व कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात एकमताने केले जावे. एखाद्या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांदरम्यान मतभेद झाल्यास त्यावर बहुमताने निर्णय घेतला जाईल. याच कलमानुसार, आयोगाला स्वतःची कार्यपद्धती ठरवण्याचे आणि कामाची विभागणी करण्याची अनुमती आहे, पण ते एकमताने निर्णय घेऊन केले जावे, अशी अट आहे.

जागतिक संकटात आघाडीवर; निर्णयप्रक्रियेत मागे

'ग्लोबल साउथ'कडे पुरेसे अधिकार नसल्याची जयशंकर यांची खंत

वृत्तसंस्था, संयुक्त राष्ट्रे

जागतिक संघर्ष, भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे, वाढते व्यापार निर्बंध आणि हवामानातील बदलांच्या संकटाचा सर्वाधिक परिणाम 'ग्लोबल साउथ'मधील विकसनशील देशांवर होत असताना, जागतिक निर्णयप्रक्रियेत मात्र या देशांना पुरेसे स्थान मिळत नाही, अशी खंत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी व्यक्त केली. जागतिक संकटांच्या काळात 'ग्लोबल साउथ'ने अधिक एकजुटीने काम करण्याची गरज असून, संयुक्त राष्ट्रांसह बहुपक्षीय संस्थांमध्ये या देशांना निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१व्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या 'समविचारी ग्लोबल साउथ देश आणि मित्र' या उच्चस्तरीय बैठकीत जयशंकर बोलत होते. सध्या जग मोठ्या अनिश्चिततेतून जात आहे. संघर्ष आणि भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वाढते व्यापार निर्बंध, गुंतवणुकीच्या प्रवाहातील विस्कळितपणा आणि हवामानाचे धक्के यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे, असे जयशंकर यांनी सांगितले.

भाजपमध्ये संघटनात्मक फेरबदल

नव्या प्रभारींची घोषणा; राज्याची जबाबदारी पांडा यांच्याकडे

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक पातळीवर मोठा फेरबदल करत बुधवारी २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रभारी आणि सहप्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल महत्त्वाचे मानले जात आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रभारीपदी वैजयंत जय पांडा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून अमित मालवीय, सदानंद शेट तानवडे व कमलजीत सेहरावत यांची सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वैजयंत पांडा

२०२७मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा आदी राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यादृष्टीनेही हे बदल महत्त्वाचे असून तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये संघटना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने भाजपने पावले टाकली आहेत. या फेरबदलात काही वरिष्ठ नेत्यांकडे एकापेक्षा अधिक राज्यांची जबाबदारी देण्यात आली.

राज्ये प्रभारी ▮**उत्तर प्रदेश** विनोद तावडे, (जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा आणि अनंत ओझा हे सहप्रभारी) ▮**दिल्ली** विनय सहस्रबुद्धे ▮**गोवा** भारती पवार ▮**मिझोराम** भागवत कराड ▮**हरियाणा** स्मृती इराणी ▮**छत्तीसगड** स्मृती इराणी ▮**उत्तराखंड** राम माधव ▮**तमिळनाडू** राम माधव ▮**पश्चिम बंगाल** सुनील बन्सल ▮**तेलंगण** सुनील बन्सल ▮**पंजाब** सतीश पुनिया ▮**जम्मू-काश्मीर** सतीश पुनिया ▮**बिहार** हरीश द्विवेदी ▮**राजस्थान** संजय भाटिया ▮**गुजरात** तरुण चुग ▮**मध्य प्रदेश** बिप्लब कुमार देब ▮**केरळ** एम. नागराज (पूर्वी प्रकाश जावडेकर) ▮**पुद्दुचेरी** के. सुरेंद्रन ▮**नागालँड** अनिल अँटनी

५ मराठी नेते प्रभारी-सहप्रभारी

महाराष्ट्रातील विनोद तावडे, मेधा कुलकर्णी, विनय सहस्त्रबुद्धे, भारती पवार आणि भागवत कराड या राज्यातील पाच नेत्यांकडे प्रभारी व सहप्रभारी पद देण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशच्या महत्त्वाच्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक असून तिथे तावडे व मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती प्रतिष्ठेची म्हणता येऊ शकते.

मुस्लीम महिलांच्या वारसा हक्कांबाबत केंद्राला निर्देश

पीटीआय, नवी दिल्ली

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार महिलांच्या असमान वारसा हक्कांमधील संहिताबाह्य नियमांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. लिंगभेद लादणाऱ्या या नियमांमुळे महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये पुरूषांपेक्षा अर्धा वाटा मिळत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते इम्तियाझ हुसेन शहाबुद्दीन मुल्ला यांनी केला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्यासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. एम. सिंग आणि ॲड. अनिल सी. निशानी यांनी या नियमांमुळे राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ (समातेचा अधिकार), अनुच्छेद १५ (भेदभाव प्रतिबंध) आणि अनुच्छेद २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

अशा विशिष्ट वैयक्तिक कायद्यामुळे मनमानी होत असल्यास त्याला घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही, असा निकाल यापूर्वीच शायरा बानो प्रकरणात देण्यात आला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे मुस्लीम महिलांना वडिलोपार्जित आणि कौटुंबिक मालमत्तेसह वारसाहक्कामध्ये समान अधिकार मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 24 सितंबर, 2026

कल्पमेधा

जीवन का अर्थ ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान की पिपासा है, क्योंकि इससे उसके चिंतन को बल मिलता है।
- जेम्स जीन्स

पारदर्शिता का प्रश्न

देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। इसकी जिम्मेदारी मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन से लेकर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने की होती है। ऐसे में यदि आयोग के भीतर ही मतभेद पैदा हो जाएं और उनकी चर्चा मतदाता सूची तथा चुनाव प्रक्रिया जैसे मूल विषयों तक पहुंचे, तो उसकी संस्थागत विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो आयुक्तों के बीच मतभेदों को लेकर बुधवार को जिस तरह की खबरें सामने आईं, उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा का तर्क है कि विचार-विमर्श के दौरान निर्वाचन आयुक्तों की ओर से अलग-अलग विचार व्यक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। मगर यहां सवाल वैचारिक मतभेदों का नहीं, बल्कि नियम-कानूनों से जुड़े प्रावधानों का है। अगर चुनाव आयोग के भीतर कोई प्रश्न उठता है, तो क्या उसके कानूनी पहलुओं पर बारीकी से गौर कर आम सहमति बनाना जरूरी नहीं है?

खबरों में कहा गया है कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस माह में निर्वाचन आयोग के फैसलों पर चौदह बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। आयोग में मतभेदों की ये खबरें ऐसे समय में आई हैं, जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी लाखों मतदाताओं के मसविदा सूची से बाहर हो जाने पर चिंता जताई जा रही है। इसकी गंभीरता इस आंकड़े में दिखती है कि देश भर में अब तक पुनरीक्षण के तहत तेरह करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए दिए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग में मतभेदों के दावे ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। हालांकि, आयोग के हवाले से कहा गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के दौरान नाम हटाए जाने सहित कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन एसआइआर से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

यह पहली बार नहीं है, जब चुनाव आयोग के भीतर असहमति सार्वजनिक हुई है। इससे पहले वर्ष 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से अलग विचार व्यक्त कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े आदेशों में असहमति या अल्पमत की राय भी दर्ज करने की मांग की थी। इससे पूर्व वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश भेजी थी। तब इस सिफारिश की वैधता, समय और औचित्य को लेकर सवाल उठे थे। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उसकी संस्थागत स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया का है। जब आयोग के भीतर अलग-अलग मत सामने आते हैं, तो जरूरी है कि असहमति के कारणों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बरती जाए, ताकि मतदाताओं में किसी तरह का भ्रम पैदा न हो। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ मतदाता सूची का अद्यतन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना भी है।

लापरवाही का तंत्र

सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह हर समय सतर्क रहने के बजाय आपराधिक घटनाओं का इंतजार करती है। जब कोई बड़ी वारदात होती है, तो शासन-प्रशसन और सुरक्षा एजंसियों की ओर से कुछ दिनों तक सक्रियता दिखाई जाती है। जांच के आदेश होते हैं, सुरक्षा की कमियां खोजी जाती हैं और फिर व्यवस्था धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर लौट आती है। सवाल है कि सुरक्षा को लेकर यह सतर्कता हमेशा किसी अपराध के बाद ही क्यों नजर आती है? दिल्ली के कालकाजी इलाके में हाल ही में एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद सरकारी तंत्र में जिस तरह की स्फूर्ति आई है, वह देखने लायक है। उपराज्यपाल ने शहर के सभी पार्कों का व्यापक सुरक्षा आडिट कराने का निर्देश दिया है। पार्कों में पर्याप्त रोशनी और आसपास महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया है। जाहिर है कि ये कदम जरूरी हैं, लेकिन यह प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गईं?

गौरतलब है कि कालकाजी मंदिर के पास बीते सोमवार शाम को कुछ लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक किशोरी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और उसे आस्था कुंज पार्क के अंदर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। हालांकि, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात का असर पास के एक शिक्षण संस्थान तक पहुंच गया। लेडी श्रीराम कालेज (एलएसआर) ने छात्राओं की सुरक्षा चिंताओं के कारण मंगलवार को कक्षाएं रद्द कर आनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने कालेज जाकर छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के मामले में पुलिस और स्थानीय निकायों के बीच नियमित समन्वय और निगरानी जरूरी है। पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का फैसला तभी सार्थक होगा, जब उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। कड़ी कानून व्यवस्था किसी आपराधिक घटना के बाद की तत्परता में नहीं, बल्कि इससे पहले की सतर्कता में नजर आती है।

विकास की रफ्तार में समृद्धि का पैमाना

भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मगर विकास के आंकड़ों का एक पहलू यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश अभी काफी पीछे है।

देवेंद्रराज सुथार

भारत की गिनती आज भले ही सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है, लेकिन विकास के व्यापक पैमाने की कसौटी पर परखने से तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। कई बार वास्तविक आंकड़े कुछ ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं, जिसे कभी-कभी नीति निर्माता छिपाना चाहते हैं। वर्ष 1960 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय मात्र 79 डालर थी, जो उस समय उत्तर कोरिया से भी कम थी। आज वही दक्षिण कोरिया 36 हजार डालर से अधिक प्रति व्यक्ति आय के साथ विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सिंगापुर की कहानी और भी चौंकाने वाली है। वर्ष 1965 में मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्र हुए इस देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 500 डालर थी, जो उस समय के मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बराबर थी। न प्राकृतिक संसाधन, न पीने का पर्याप्त पानी, फिर भी आज सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय पचास हजार डालर से अधिक है और वह अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है। दूसरी ओर भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1960 में 312 डालर थी और 2024 तक यह केवल 2,396 डालर तक पहुंच पाई है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में वास्तविक विकास और समृद्धि की रफ्तार के बीच कितना अंतर है।

स्वतंत्रता के बाद लगभग साढ़े चार दशकों तक भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.5 फीसद के आसपास सिमटी रही, जबकि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल कर रहे थे। इसका मूल कारण था लाइसेंस राज की वह प्रणाली, जिसमें उद्योग स्थापित करने से लेकर उत्पादन बढ़ाने तक की अनुमति पाने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वर्ष 1980 के दशक के अंत तक भारत में पूंजीगत वस्तुओं पर 115 फीसद और उपभोक्ता वस्तुओं पर 129 फीसद तक का आयात शुल्क लगाया जाता था। निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसद तक सीमित था। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1991 में देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जब विदेशी मुद्रा भंडार दो सप्ताह के आयात के लायक शेष रह गया था।

इसी क्रम में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुईं। नब्बे के दशक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष लगभग छह फीसद की दर से बढ़ा और निर्यात 17 फीसद वार्षिक दर से बढ़ने लगा। साफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में देश ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। मगर प्रश्न यह है कि यह सुधार 44 वर्ष पहले क्यों नहीं हो सका, जब दक्षिण कोरिया और सिंगापुर पहले ही खुले बाजार और निर्यात आधारित औद्योगीकरण की राह पकड़ चुके थे। सिंगापुर के संस्थापक नेता ने जहां शुरू से ही मुक्त व्यापार और न्यूनतम आयात शुल्क की नीति अपनाई, वहीं भारत में संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता के नाम पर आयात प्रतिस्थापन का माडल दशकों तक जारी रहा, जिसने भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से दूर रखा और वे कमजोर होते गए। दूसरी बड़ी कमी विनिर्माण क्षेत्र की उपेक्षा में दिखी। सिंगापुर में 1965 से 1975 के बीच ही विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा चौदह फीसद से बढ़कर बाईस फीसद तक पहुंच गया था। भारत

में यह हिस्सा आज भी 16 से 17 फीसद के बीच ही अटका हुआ है।

वर्ष 2014 में जब 'मेक इन इंडिया' अभियान आरंभ हुआ, तब विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सोलह फीसद था और सरकार का लक्ष्य इसे 2022 तक पच्चीस फीसद तक ले जाने का था। यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। विनिर्माण

> **वर्ष 2014 में जब 'मेक इन इंडिया' अभियान शुरू हुआ, तब विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सोलह फीसद था और सरकार का लक्ष्य इसे 2022 तक पच्चीस फीसद तक ले जाने का था। यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि उदारीकरण के बाद के पच्चीस वर्षों में भी इस हिस्से में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। विनिर्माण के अभाव का प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ता है, क्योंकि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में श्रमशक्ति को समाहित कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देश की प्रगति अपेक्षा से धीमी रही। वर्ष 2024 में देश की साक्षरता दर लगभग 78 फीसद थी, जबकि विश्व की औसत 86 फीसद के आसपास है। देश के उद्योग जगत को कुशल श्रमशक्ति की जरूरत है, जबकि लाखों स्नातक बेरोजगार हैं।**

के अभाव का सीधा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ता है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में श्रमशक्ति को समाहित कर सकता है। जब कोई राष्ट्र युवा शक्ति को उत्पादक कार्य में नहीं लगा पाता, तब आबादी वरदान के बजाय चुनौती बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की प्रगति अपेक्षा से धीमी रही। वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, देश की साक्षरता दर लगभग 78 फीसद है, जबकि विश्व की औसत 86 फीसद के आसपास है।

दक्षिण कोरिया की बात की जाए, तो उसने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था और तकनीकी शिक्षा में भारी निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप वहां का मानव पूंजी सूचकांक विश्व में अग्रणी बना। भारत में शिक्षा नीति लंबे समय तक उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही, जिससे कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा की नींव कमजोर हुई। परिणामस्वरूप आज भी उद्योग जगत कुशल श्रमशक्ति की कमी की शिकायत करता है, जबकि लाखों स्नातक बेरोजगार हैं। सिंगापुर ने शुरू से ही भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई और प्रशासनिक दक्षता को सर्वोच्च बनाया। जबकि भारत में भ्रष्टाचार, अवसर की राजनीति और अल्पकालिक चुनावी लाभ की सोच ने दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को बार-बार भटकाया। देश में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ नीतियां भी बदलती रहीं, जिससे निरंतरता का अभाव रहा और हर सरकार को पिछली नींव पर नहीं, बल्कि नई शुरुआत से चलना पड़ा।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच के वास्तविक स्वरूप को समझना भी जरूरी है। जिन देशों ने तीव्र विकास किया, उन्होंने पहले अपने घरेलू उद्योग और तकनीक को प्रतिस्पर्धी बनाया, फिर वैश्विक बाजार में साहसपूर्वक कदम रखा। भारत में ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों और क्षमता पर भरोसा करने में झिझक बनी रही। हालांकि, यह भी सच है कि भारत की चुनौतियां कई देशों की अपेक्षा विशाल और जटिल थीं। इतनी बड़ी जनसंख्या, सामाजिक विविधता, अनेक भाषाएं, धर्म और क्षेत्रीय असमानताओं के बीच लोकतंत्र को जीवित रखते हुए विकास करना, किसी छोटे और अपेक्षाकृत सजातीय समाज वाले देश की तुलना में कठिन है। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने प्रारंभिक दशकों में सत्तावादी शासन के सहारे तेजी से निर्णय लिए, जबकि भारत ने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे को अपनाया। जापान और जर्मनी ने भी लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए युद्धोत्तर पुनर्निर्माण किया और सिद्ध किया कि अनुशासित लोकतंत्र भी तेज प्रगति का मार्ग बन सकता है।

अब समय आ गया है कि भारत अपनी कमियों से सीखते हुए नई दिशा तय करे। विनिर्माण को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां, कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, नवाचार को बढ़ावा, अवसंरचना में निवेश और आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये सभी उस दिशा के संकेत हैं, जिसकी आवश्यकता दशकों पहले महसूस की जानी चाहिए थी। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अत्यंत गरीबी की दर नब्बे के दशक के प्रारंभ में पैंतालीस फीसद से अधिक थी, जो वर्ष 2022 तक घटकर लगभग पांच फीसद रह गई है। विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है, जो पराधीनता ने छीन लिया था। जिस भारत ने कभी विश्व की एक चौथाई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया था, वह फिर से अपनी उस पहचान को पाने की राह पर है। अगर संकल्पशक्ति, अनुशासन और स्पष्ट दिशा हो, तो लक्ष्य को हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।

सफलता की नींव

अनंतपद्मनाभन

दुनिया मेरे आगे

तुरंत सफलता का भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ना एक सीधी राह पर लगातार चलते जाने का नाम है। मानो हर कदम हमें मंजिल के करीब ले जाता हो। मगर वास्तविक जीवन शायद ही कभी इतनी सरल रेखा में आगे बढ़ता है। निराशाएं, योजनाओं का विफल होना, अवसरों का हाथ से निकल जाना और भविष्य को लेकर अनिश्चितता- ये सब जीवन-यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा हैं। विडंबना यह है कि जिन परिस्थितियों को हम अपनी प्रगति में बाधा समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और धैर्यवान बना सकती हैं। कई बार जीवन हमें सफलता का रास्ता दिखाने से पहले असफलता से गुजरना सिखाता है।

अचानक लगा कोई बड़ा झटका व्यक्ति को भीतर तक हिला सकता है। नौकरी चली जाना, परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिलना, कारोबार बंद हो जाना या कोई प्रिय अवसर हाथ से निकल जाना- इनमें से कोई भी घटना भविष्य को धुंधला कर सकती है। उस क्षण लग सकता है कि देखा गया सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन असफलता शायद ही कभी स्थायी होती है। वह पूर्ण विराम नहीं, एक पड़ाव है। वह व्यक्ति को सोचने का अवसर देती है कि क्या गलत हुआ और आगे की राह कैसे बेहतर बनाई जाए।

ऐसे उदाहरण हमें आए दिन मिल जाएंगे, जिनमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। बल्कि उसकी वजह से उसने न केवल अपनी मंजिल के बारे में कुछ समय तक सोचना छोड़ दिया, बल्कि खुद को रास्ते से भी बाहर हो गया मानने लगा। मगर उसके भीतर के बचे हुए हौसले ने एक बार फिर धक्का दिया और वह पहले की नाकामी को पीछे छोड़ आगे की ओर बढ़ चला। उसके बाद मिली कामयाबी ने न केवल यह साबित किया कि हारना विकल्प नहीं है, बल्कि हार कर बैठ जाना कैसे व्यक्ति को उसके सपनों से दूर कर देता है। जीवन के हर क्षेत्र में असफलता भी कुछ सिखाती है।

> **कभी-कभी असफलता का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हमें अपने डर से आगे बढ़ना सीखना चाहिए। असफल होने के डर से यदि हम प्रयास ही न करें, तो संभावनाओं के कई दरवाजे हमारे लिए कभी खुलेंगे ही नहीं। हर ठोकर हमें अधिक सजग बनाती है। हर प्रतीक्षा हमारे भीतर विश्वास जगाती है।**

खेल के मैदान में चोट से लौटने वाला खिलाड़ी मन को भी मजबूत बनाता है। चोट उसे अपनी सीमाएं समझने और धैर्य रखने का अवसर देती है। इसी तरह परीक्षा में असफल विद्यार्थी अपनी कमियां पहचानकर अगली कोशिश को अधिक व्यवस्थित बना सकता है। कभी-कभी असफलता हमें वह सिखाती है, जो सफलता नहीं सिखा सकती। सफलता आत्मविश्वास देती है, लेकिन असफलता आत्ममंथन का अवसर देती है। सफलता क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती है, जबकि असफलता कमजोरियों को पहचानने का साहस देती है। त्वरित सफलता की कहानियां यह भ्रम पैदा करती हैं कि सफलता शीघ्र मिलनी चाहिए, लेकिन उपलब्धियां समय, निरंतर प्रयास और छोटे सुधारों से बनती हैं। दैनिक अनुशासन और धैर्य का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन वही स्थायी परिवर्तन की नींव रखते हैं। नदी को चट्टान काटने के लिए असाधारण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उसका निरंतर बहाव रास्ता बनाता है। जीवन में भी निरंतरता प्रतिभा से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

हर दिन का छोटा प्रयास भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर असफलता के तुरंत बाद सफलता मिल जाएगी। कभी-कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है, कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ सपने बदलने पड़ते हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। कई बार बंद हुआ दरवाजा ऐसी राह खोल देता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। वास्तविक लचीलापन यही है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से बचने के बजाय उनका सामना करने की क्षमता विकसित करे। गिरना कमजोरी नहीं है। गिरने के बाद उठने की इच्छा ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है।

हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है, किसी की देर से। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना उचित नहीं। दिखाई देने वाली सफलता के पीछे अक्सर ऐसे संघर्ष छिपे होते हैं, जिन्हें दुनिया नहीं देखती। कभी-कभी असफलता का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हमें अपने डर से आगे बढ़ना सीखना चाहिए। असफल होने के डर से यदि हम प्रयास ही न करें, तो संभावनाओं के कई दरवाजे हमारे लिए कभी खुलेंगे ही नहीं।

जोखिम उठाने का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर प्रयास का परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी प्रयास करते रहना जरूरी है, क्योंकि अवसर अक्सर उन्हीं लोगों के सामने आते हैं, जो असफल होने की आशंका के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जीवन आसान राह का वादा नहीं करता। मगर हमारे पास एक विकल्प हमेशा रहता है- हम परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने दें या उससे सीखकर आगे बढ़ें।

जब हम असफलता को अंत नहीं, पड़ाव मानते हैं, निराशा को ठहराव नहीं, आत्ममंथन का अवसर बनाते हैं और बाधाओं को दीवार नहीं, सीढ़ी की तरह देखते हैं, तब जीवन का अर्थ बदलने लगता है। हर ठोकर हमें अधिक सजग बनाती है। हर प्रतीक्षा हमारे भीतर विश्वास जगाती है। हर पुनःप्रयास हमारी इच्छाशक्ति को और दृढ़ करता है। धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास के साथ देखी जाएं, तो असफलताएं रास्ता रोकने वाली दीवारें नहीं रह जातीं। वे वही सीढ़ियां बनती हैं, जिन पर कदम रखकर हम अपने भीतर की उस शक्ति तक पहुंचते हैं, जिसका हमें पहले अंदाजा भी नहीं था। यही असफलता से सफलता की सच्ची और सार्थक यात्रा है।

संप्रभुता का सम्मान

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश और आर्थिक नीतियां किसी दूसरे देश के निर्देशों से तय नहीं होंगी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद कर भारत ने न केवल अपनी विशाल आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि घरेलू स्तर पर महंगाई को भी नियंत्रित रखा। यदि भारत ने उस समय रूस से तेल न खरीदा होता, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगतीं, जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता। अमेरिका खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम तय करता है, जबकि भारत के लिए उसके 140 करोड़ नागरिकों का हित सर्वोपरि है। उसका यह दो टूक जवाब उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, संप्रभुता और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को मजबूती से रेखांकित करता है। आज का भारत किसी भी वैश्विक महाशक्ति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर दबाव बनाना और सौ फीसद तक शुल्क लगाने की धमकी देना स्पष्ट तौर पर उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है।

- भगवानदास छारिया, इंदौर

स्वदेशी को प्रोत्साहन

देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआइ ने क्रांतिकारी बदलाव किया है। आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक यूपीआइ का सहजता से उपयोग कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआइ की हिस्सेदारी 84 फीसद तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा दो हजार रुपए से अधिक के व्यवसायिक भुगतान पर 0.4 फीसद शुल्क लगाना चिंताजनक है। यूपीआइ लेन-देन पर किसी भी प्रकार का शुल्क डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली कंपनियों और बैंकों की लागत का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। इस लागत की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि स्थायी समाधान नहीं हो सकती। फोनपे और गूगलपे मिल कर अस्सी फीसद यूपीआइ लेन-देन संभालते हैं। यूपीआइ को सस्ता और सुलभ बनाए रखने के लिए स्वदेशी 'फिनटेक कंपनियों' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

आतंकवाद की कीमत

'आतंक की जड़' (संपादकीय, 21 सितंबर) पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या पर एक गंभीर प्रश्न उठाता है। आखिर जिस आतंकवाद को कभी रणनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया, वही अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है? निस्संदेह आतंकवाद को केवल सीमा पार की समस्या मानने के बजाय उसके घरेलू कारणों और नीतिगत पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देना होगा। आतंकवादी संगठनों के बीच भेद करने की नीति अंततः सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि हिंसा का रास्ता एक बार खुलने के बाद उसके लक्ष्य और सीमाएं तय करना कठिन हो जाता है। आखिर पाकिस्तान ने जो बीज बोए हैं, अब उसी की फसल उसे काटनी पड़ रही है। कोहाट में आतंकी हमले की घटना इसी खतरे का उदाहरण है। इससे स्पष्ट है कि आतंकवाद अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए भी गंभीर संकट है।

- ओपी चौधरी, रतलाम, मप्र

शिक्षा में बदलाव

शिक्षा अब तकनीक की अंगुली थाम कर एक नए युग में प्रवेश कर रही है। कभी यह मनुष्य के भीतर छिपे विवेक को जगाने वाली वह धीमी लौ थी, जिसकी रोशनी में समाज अपने अंधविश्वासों और असमानताओं को पहचानता था। मगर समय के बदलते व्याकरण में शिक्षा का चरित्र भी बदल गया है। विद्यार्थी जो कभी जिज्ञासा का पर्याय था, आज कई बार 'पैकेज' और 'प्लेसमेंट' का पर्याय बना हुआ प्रतीत होता है। विद्यालयों की दीवारों पर नैतिक शिक्षा संबंधी विचार अब भी मुस्कराते हैं, लेकिन उनके नीचे भारी-भरकम फीस की सूची दिखाई देती है। तकनीक ने शिक्षा के क्षितिज को विस्तृत किया है, लेकिन सबसे गंभीर प्रश्न शिक्षा के उद्देश्य का है। शिक्षा का नया चेहरा आधुनिक अवश्य है, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी सामाजिक विषमताएं अब भी दिखाई देती हैं।

- प्रबल मिश्रा, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

एक शिक्षक और शून्य-नामांकन वाले विद्यालयों में कमी

तथ्य

यूडीआइएसईप्लस रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में केवल एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 3 फीसद की कमी आई और यह घटकर 1,00,843 रह गई, जबकि पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में शून्य-नामांकन वाले स्कूलों में 29 फीसद की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई और इनकी संख्या घटकर 5,663 हो गई। ये सुधार शिक्षकों के आवंटन को तर्कसंगत बनाने, उनके बेहतर पदस्थापन और देश भर में छात्रों की जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

स्कूलों में कुल नामांकन में लड़कियों की हिस्सेदारी 48.4 फीसद

यूडीआइएसइप्लस 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में कुल नामांकन में लड़कियों की हिस्सेदारी 48.4 फीसद रही, जो स्कूलों में एक संतुलित लैंगिक वितरण को दर्शाती है। इसके अलावा, शिक्षकों में भी महिलाओं का फीसद 54.9 है जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। कुल दाखिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 44.9 फीसद है, इसके बाद सामान्य वर्ग (27.5%), अनुसूचित जाति (17.7%) और अनुसूचित जनजाति (10%) का स्थान रहा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलाकर कुल दाखिलों में इनकी हिस्सेदारी 27.7% रही, जो स्कूली शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों को दर्शाता है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार

विशेषज्ञ की कलम

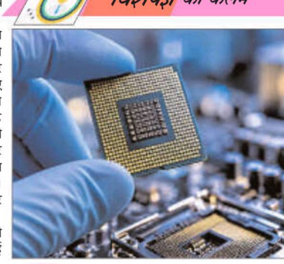

भारत का सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र इस समय देश के सबसे तेजी से बढ़ते 'सनराइजिंग सेक्टर्स' में से एक बन चुका है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हाल ही में आयोजित हुए सेमीकान इंडिया 2026 में सरकार ने सेमीकान 2.0 नीति को 1.27 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट के साथ हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय के अनुसार, इस नए अभियान और बढ़ते निवेश से इस पूरे इकोसिस्टम में 1 लाख से अधिक नई नौकरियों के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

इसी को देखते हुए प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरतें पूरी करने की भी तैयारियां तेज हो गई है। सेमीकंक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन, चिप निर्माण, सिस्टम डिजाइन, उपकरण सहित पहलुओं पर युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाएं इस पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा के तौर पर आगे आने लगी हैं। अगले छह साल में एक लाख युवाओं को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। प्रणाली और उपकरणों की जरूरत के लिए प्रशिक्षित और दक्ष कर्मियों की मदद से कम लागत में गुणवत्ता से चिप विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ेंगे।

> केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय के अनुसार, इस नए अभियान और बढ़ते निवेश से इस पूरे इकोसिस्टम में 1 लाख से अधिक नई नौकरियों के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

सेमीकान इंडिया 2026 के दौरान सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत में निवेश संभावनाएं बढ़ाने के लिए कई कंपनियों से साझेदारी भी की गई है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण के कई हिस्से हैं। किसी भी उपकरण या प्रणाली की जरूरत के मुताबिक चिप तैयार किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए चिप डिजाइन, रसायन, गैस और फैब समेत अलग अलग प्रणालियों की जरूरत के लिए तैयार किए जाने वाले उकपरणों की गुणवत्ता बेहद अहम है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ), इंजीनियरिंग सहित विभिन्न स्तर के कर्मियों की जरूरतें पूरी की जाएंगी।

वेतन

फ्रेशर्स : 4 लाख से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष (शीर्ष संस्थानों जैसे आइआइटी से पास होने वालों के लिए यह 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है।

2 से 5 वर्ष का अनुभव: 8 लाख से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष।

I5 से 10 वर्ष का अनुभव: 15 लाख से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष।

सीनियर इंजीनियर और विशेषज्ञ : 30 लाख से 60 लाख रुपए प्रति वर्ष या अधिक।

प्रमुख संस्थान व पाठ्यक्रम

आइआइएससी बैंगलोर (भारतीय विज्ञान संस्थान): यहां सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए विशेष 'सेंसे' लैब है। आइआइएससी द्वारा ताइवानी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर टेक्नोलाजी में ज्वाइंट एमटेक कोर्स भी चलाया जा रहा है।

आइआइटी मुंबई आइआइटी दिल्ली, आइआइटी मद्रास और आइआइटी खड़गपुर: ये संस्थान सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, नैनोइलेक्ट्रानिक्स और वीएलएसआइ डिजाइन के लिए देश के सबसे प्रमुख केंद्र हैं। आइआइटी दिल्ली इसके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी कराता है।

आइआइटी भुवनेश्वर: यह संस्थान एमओएसर्ट लैब्स के साथ साझेदारी में सेमीकंडक्टर टेक्नोलाजी व चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स आफर करता है।

आइआइटी हैदराबाद और एनआइटी त्रिची और एनआइटी सुरथकल): यहां एडवांस हार्डवेयर-साफ्टवेयर को-डिजाइन और चिप आर्किटेक्चर के विशेष ट्रैक्स उपलब्ध हैं।

विशिष्ट स्किल्स और डिप्लोमा संस्थान, गांधीनगर: यह संस्थान आइआइटी गांधीनगर और सिंगापुर के सहयोग से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग में इंटरनेशनल प्रोफेशनल टेक्नोलाजिस्ट प्रोग्राम कराता है।

मनोज चौधरी, *गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति*

जानें-सीखें

यूपीआइ : फोन में इंटरनेट न होने पर भी हो सकेगा भुगतान

यूपीआइ से भुगतान करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब कुछ परिस्थितियों में फोन में मोबाइल इंटरनेट न होने पर भी भुगतान किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआइ ने यूपीआइ टैप एंड पे और माययूपीआइ नाम के दो नए फीचर पेश किए हैं। इनमें एक सुविधा एनएफसी के जरिए भुगतान आसान करेगी, जबकि दूसरी एआइ की मदद से यूपीआइ से जुड़ी कई समस्याओं और सेवाओं को एक जगह लाने की कोशिश है। ये दोनों सुविधाएं हाल ही में मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लान्च की हैं।

यूपीआइ टैप एंड पे की सबसे खास बात यह है कि भुगतान के समय फोन में मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं होगा। इसके लिए यूजर के स्मार्टफोन में एनएफसी सपोर्ट होना चाहिए और जिस भुगतान मशीन पर पेमेंट किया जा रहा है, उसमें भी एनएफसी की सुविधा मौजूद होनी चाहिए। भुगतान करने के लिए यूजर को फोन अनलाक करके एनएफसी सपोर्ट वाली पाइंट आफ सेल मशीन पर टैप करना होगा। इसके बाद लेनदेन के लिए मशीन का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल होगा। यानी फोन का मोबाइल डेटा बंद होने पर भी भुगतान किया जा सकेगा। यूपीआइ टैप एंड पे में अलग-अलग तरह के यूपीआइ खाते इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसमें यूपीआइ से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड का विकल्प भी शामिल है। 5,000 रुपए तक के भुगतान बिना यूपीआइ पिन के किए जा सकेंगे। इससे ज्यादा रकम के लेनदेन के लिए पॉइंट आफ सेल मशीन पर यूपीआइ पिन दर्ज करना होगा। इससे छोटे भुगतान को तेज बनाने के साथ बड़े भुगतान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की गई है।

एनपीसीआइ ने इसके साथ माययूपीआइ भी पेश किया है। यह एआइ पर आधारित सेवा है, जो एनपीसीआइ के फाइनेंस माडल फार इंडिया यानी फाइमी नाम के विशेष भाषा माडल पर तैयार की गई है। फाइमी को भारतीय भुगतान व्यवस्था को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और यह पहले से यूपीआइ हेल्प असिस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है। माययूपीआइ का मकसद यूजर को अलग-अलग बैंकों और यूपीआइ एप में मौजूद लेनदेन और आटोपे मैंडेट की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराना है। इससे यूजर को अपनी यूपीआइ गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो सकता है। माययूपीआइ में सेफ्टी स्विच भी दिया जाएगा। अगर किसी यूजर को लगता है कि उसका बैंक खाता या यूपीआइ एक्सेस किसी खतरे में है, तो वह आने वाले यूपीआइ डेबिट लेनदेन को रोकने का अनुरोध कर सकेगा।

युवा शक्ति डेस्क

सेवा संकल्प अभियान

प्रयागराज : 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत छात्रों ने बुधवार को भारत के नक्शे के आकार में मानव शृंखला बनाई।

नौकरी के लिए अकादमिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक शिक्षण भी जरूरी

परामर्श

व्यावहारिक शिक्षण और केस स्टडी के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ानाआज के प्रतिस्पर्धी समय में नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं जिनके पास न केवल अकादमिक ज्ञान हो, बल्कि पेशेवर वातावरण में सफल होने के लिए व्यावहारिक कौशल का अनुभव भी हो। कार्यस्थल की गतिशील मांगों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पारंपरिक कक्षा शिक्षण अब पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यावहारिक शिक्षा भी जरूरी है।

शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यावहारिक शिक्षण अनुभव को शामिल करने से छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक परिदृश्यों में महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और निर्णय लेने के कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। व्यावहारिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है जो उनके करियर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का अनुकरण करते हैं। इंटर्नशिप, वास्तविक परियोजनाओं या उद्योग भ्रमण के माध्यम से, यह शिक्षण छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया के संदर्भों में लागू करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, छात्र व्यावसायिक सिमुलेशन में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उद्योग जगत के पेशेवरों के साथ सहयोग कर सकते हैं, या कंपनियों के साथ मिलकर परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं। व्यावसायिक जगत की रोजमर्रा की वास्तविकताओं का अनुभव करके, छात्र उन कौशलों के साथ कार्यबल में प्रवेश करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं जिन्हें नियोक्ता सबसे अधिक महत्व देते हैं। व्यावहारिक शिक्षा छात्रों को उद्योग की कार्यप्रणाली से परिचित कराती है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और नियोक्ता अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा रखते हैं।

अब जेईई, नीट का प्रतिरूप स्कोरकार्ड निकलवा सकेंगे

जरूरी जानकारी

नेशनल टेस्टिंग एजंसी (एनटीए) ने स्कोरकार्ड की प्रतिरूप कापी लेने की प्रक्रिया जारी की है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मूल स्कोरकार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, खराब हो गया है या किसी वजह से नष्ट हो गया है। यह नियम जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी पीजी समेत एनटीए की ओर से आयोजित अन्य परीक्षाओं के स्कोरकार्ड पर भी लागू होता है। एनटीए ने जारी सूचना में प्रतिरूप स्कोरकार्ड पाने का तरीका बताया है।

अभ्यर्थियों के पास इसके लिए दो विकल्प हैं। अगर आपका स्कोरकार्ड डिजीलाकर पर उपलब्ध है, तो उसे वहीं से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए अलग से प्रतिरूप स्कोरकार्ड का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर डिजीलाकर पर स्कोरकार्ड नहीं मिल रहा है, तभी एनटीए की तय प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

यह आवेदन पत्र एनटीए की सूचना में अनुलग्नक-1 (एनेक्सचर-1) के रूप में दिया गया है। एनटीए इसके लिए एक आनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराएगा। जब तक वह पोर्टल शुरू नहीं होता, तब तक अभ्यर्थी एनटीए की ओर से बताए गए दूसरे तरीकों से आवेदन भेज सकते हैं। एक तरीका है कि पूरा आवेदन और जरूरी दस्तावेज पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से एनटीए के निदेशक (परीक्षा) को भेजें। अभ्यर्थी सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कापी एक पीडीएफ फाइल में बनाकर ईमेल भी कर सकते हैं। हालांकि, केवल ईमेल भेजना पर्याप्त नहीं होगा।

> यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मूल स्कोरकार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, खराब हो गया है या किसी वजह से नष्ट हो गया है।

ईमेल भेजने के बाद 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की हार्ड कापी पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी। डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि परीक्षा का परिणाम जारी हुए कितना समय बीत चुका है। यह 1,500 रुपए से लेकर 2,500 रुपए के बीच होगी।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज देने होंगे

-डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करते समय एनटीए के तय प्रारूप में भरा और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र।

-अनुलग्नक-2 में दिए प्रारूप के अनुसार तैयार हलफनामा।

-स्कोरकार्ड खोने या चोरी होने से जुड़ी पुलिस रिपोर्ट, जैसे एफआइआर, डीडीआर, एनसीआर या खोई वस्तु की रिपोर्ट।

-दो हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो। एक आवेदन पत्र और दूसरी हलफनामे के साथ लगानी होगी।

-परीक्षा का प्रवेश पत्र या पंजीकरण पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति, यदि उपलब्ध हो। यह अनिवार्य नहीं है। डुप्लीकेट स्कोरकार्ड की फीस जमा करने का प्रमाण।

-वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। पहचान पत्र के तौर पर आधार, पैन, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है।

-जहां जरूरी हो, निर्धारित तरीके से छिपे अंकों वाला आधार कार्ड की प्रति देनी होगी।

-भारत से बाहर रहने वाले अभ्यर्थी जरूरी पासपोर्ट की प्रति दे सकते हैं।

-एनटीए के अनुलग्नक-3 में दिए प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति सह वचनपत्र भी देना होगा।

सूचनापट्ट

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय

शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए पंजीकरण और प्रवेश की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 24 सितंबर तक संबंधित संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहित और संबद्ध महाविद्यालयों के अनुरोध को देखते हुए यह निर्णय किया है। प्रवेश समन्वयक प्रो. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इसके लिए 200 रुपए प्रति छात्र की दर से शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण कराने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में पंजीकरण और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एलएलएम प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों और संबद्ध महाविद्यालयों को निर्धारित तिथि के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को प्रवेश की विस्तारित तिथि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

आवेदन की अंतिम तिथि : 24 सितंबर

यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) वेंचर फंड इंटर्नशिप-2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यूनिसेफ के स्टाकहोम स्थित नवाचार कार्यालय में यह छह महीने की पार्ट-टाइम इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप के लिए दुनिया भर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

इसके प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लाकचेन, यूएवी, इंटरनेट आफ थिंग्स, डाटा साइंस और सहायक तकनीक आदि शामिल हैं। इंटर्न के तौर पर आपको एक ऐसी नई टेक्नोलाजी वाली कंपनियों/आइडियाज को ढूंढना होगा, जो समाज की किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकें। यह अवसर तकनीक, नवाचार और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है। चयनित इंटर्न को अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ यूनिसेफ वेंचर फंड की टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। वे स्टार्टअप की खोज और जांच-पड़ताल, बाजार अनुसंधान और आवेदनों की समीक्षा, तथा मूल्यांकन नोट्स और शोध सामग्री तैयार करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, वे संसाधन जुटाने के लिए सामग्री व केस स्टडी तैयार करेंगे, पोर्टफोलियो और जानकारी से जुड़े रिकार्ड संभालेंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि : 25 सितंबर

जामिया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि जारी कर दी है। नियमित और पार्ट टाइम पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों के लिए परीक्षा फार्म 25 सितंबर से 20 अक्तूबर तक आनलाइन उपलब्ध रहेंगे। बैकलाग पेपर वाले छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं पीएचडी कोर्स वर्क के छात्रों के लिए भी आनलाइन परीक्षा फार्म इसी अवधि में भरे जाएंगे। इसमें सत्र 2025-26 के सेमेस्टर-2 और सत्र 2026-27 के सेमेस्टर-1 के शोधार्थी शामिल हैं। इसके अलावा बिना विलंब शुल्क के फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर है। इसके बाद 30 अक्तूबर तक एक हजार रुपए विलंब शुल्क के साथ फार्म जमा कर सकेंगे। फार्म में सुधार या संशोधन एक से पांच नवंबर तक हो सकेगा।

अंतिम तिथि : 30 अक्तूबर

आइसीएआर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) ने कृषि और संबद्ध विज्ञान में मास्टर डिग्री धारकों से नेताजी सुभाष (एनएस)-आइसीएआर इंटरनेशनल फेलोशिप-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप कृषि क्षेत्र की उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों से जुड़े आइसीएआर के प्राथमिकता वाले शोध क्षेत्रों में पीएचडी करने का अवसर देती है। इसके तहत उम्मीदवार कृषि विश्वविद्यालयों में शोध कर सकेंगे। एनएस-आइसीएआर इंटरनेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी के लिए 30 फेलोशिप दी जाएगी। इसकी अवधि तीन साल होगी। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में नई तकनीकों पर शोध के लिए विशेषज्ञ तैयार करना और भारतीय कृषि अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। इसके लिए आवेदक के पास कृषि या संबद्ध विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। विदेश में पीएचडी करने वाले चयनित भारतीय फेलो को हर महीने 2,000 अमेरिकी डालर और एक वर्ष में 1,000 अमेरिकी डालर की अतिरिक्त आकस्मिक राशि दी जाएगी। भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी फेलो को 40,000 रुपऐ प्रतिमाह और 25,000 रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिक और तैयारी संबंधित खर्च के लिए राशि मिलेगी।

अंतिम तिथि : 25 सितंबर

प्रेरणा

जीवन का लक्ष्य है अपने स्वभाव को पूरी तरह से जानना, इसी प्रयोजन से हम इस दुनिया में हैं। -ऑस्कर वाइल्ड

संपादकीय

श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान तो जातिवाद से ग्रस्त ना हों

देश की प्रथम पांच आईआईटी में से दूसरी आईआईटी-बॉम्बे में एक दलित छात्र की आत्महत्या पर उसके परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि डीन/प्रोफेसर ने उस पर जातिवादी टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्हें डीन पद से हटा दिया गया। प्रतिक्रिया में डीन के पक्ष में भी छात्रों/फैकल्टी का एक वर्ग उठ खड़ा हुआ। एक अन्य घटना में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज एनएलयू के एचओडी-वार्डन को सभी प्रशासनिक पदों से मुक्त करने के आदेश दिए। उन पर भी दलित छात्रों के खिलाफ जातिवादी पूर्वग्रह का आरोप था। सवाल इन प्राध्यापकों की अपराध-लिप्तता से बड़ा है। चिंता इन संस्थाओं के वातावरण में जातिवादी जहर घुलने की है, जो शैक्षणिक माहौल को और कलुषित ही करेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी समुन्नत देशों में अकादमिक संस्थाओं का प्रशासन भी प्रोफेसर ही सम्भालते हैं, ताकि शैक्षिक स्वायत्तता बनी रहे। लेकिन अगर छात्रों का एक वर्ग जातिवादी आरोप के समर्थन में प्रोफेसर के खिलाफ है और दूसरा प्रोफेसर के साथ, तो आने वाले दिनों में परिसर में क्या कोई खुद्दार प्राध्यापक प्रशासनिक पद स्वीकार करेगा? क्या कोई डीन या वार्डन बनाना चाहेगा? इससे भी बड़ा मसला है जातिवाद या साम्प्रदायिकता जैसी कुरीतियों के प्रसार का, जो समय के साथ बढ़ती ही गई हैं। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई से आए बच्चे या इन विषयों में महारत हासिल किए प्राध्यापकों को तो जातिवाद या साम्प्रदायिकता के मर्ज से अछूता ही रहना चाहिए।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

जब भी संकल्प लें, सबसे पहले मन को नियंत्रित करें

कुछ अभियानों की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती। आपको दौड़ना भी पड़ेगा, वक्त आने पर छलांग भी लगानी पड़ेगी। अब आज छोटे-मोटे काम, सामान्य सफलताएं बहुत अर्थ नहीं रखतीं। नई पीढ़ी कुछ अनूठा करने में माहिर है। उनकी तैयारी में उत्साह और सक्रियता तो है, पर संकल्प-शक्ति की कमी है। और इसके बिना वे आधे रास्ते में थक जाते हैं। जब भी कोई संकल्प लें, ध्यान रखें कि संकल्प सात्विक होना चाहिए, वरना हिंसा में बदल सकता है। संयम के साथ संकल्प लें। लोग समझते हैं संकल्प मन में लिया जाता है। दरअसल संकल्प आत्मा, हृदय और मस्तिष्क का विषय है। मन तो उस संकल्प को तोड़ने का काम करता है। आपने संकल्प लिया कि प्रातःकाल उठेंगे, सैर करने जाएंगे। अलार्म लगाया। जिनके पास दो मोबाइल हैं, वो दो में लगाते हैं। और जब वह अलार्म बजता है तो कौन है, जो भीतर से हाथ निकालकर उसको बंद करके आपको समझाता है कि आज नहीं, कल से करेंगे? यह काम मन का है। तो जब भी संकल्प लें, पहले मन को नियंत्रित करें। लिया गया संकल्प शत-प्रतिशत सफल होगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

झुकी हुई औरतें

औरतें झुकी रहती हैं उम्र भर
कभी शारीरिक कभी मानसिक रूप से
झुक के धुलती जाती हैं, जल्दी जल्दी बर्तन
खंगाल लेती हैं, सबके छोड़े कपड़े
दाल उतार के चावल चढ़ाती हैं झुके झुके
खेतों में धान बोती जाती हैं

झुककर खींचती थीं पानी, परोसती थीं खाना
झुककर ही था, उसका हर जगह आना जाना
झुकके उठाती हैं बिखरे सामान
टूटे से रिश्ते और कई खानदान...

फिर धीरे धीरे वो झुककर चढ़ने लगती हैं सीढ़ियां
चलती भी हैं, अब झुक कर ही
वो झुककर उठाना चाहती थीं अपना कद

पर अब उनकी मुड़ गई है रीढ़,
निकलने लगे हैं कूल्हे
उन्हें अब याद दिलाना पड़ता है
कि वह सीधी भी चल सकती हैं
औरतें जीवन भर झुकते झुकते झुक जाती हैं।

-मनीषा पांडेय, कानपुर (यूपी)
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

यूपीआई शुल्क की राशि बढ़ाई जाए

डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जनता की सुविधा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। इस पर कोई भी शुल्क लगाने का भार तो आम जनता पर ही पड़ता है। शुल्क लेना ही है तो दो हजार नहीं, एक लाख रुपए से अधिक की राशि से शुरुआत हो।
-प्रतिभा शाह, इन्दौर, मध्यप्रदेश

बढ़ती बरोजगारी देश के लिए चुनौती

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी सर्वे के नतीजे बताते हैं कि देश के युवाओं में बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जितनी यह दिख रही है, स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह है। आगे चलकर इससे देश में अस्थिरता का नया दौर शुरू हो सकता है।
-जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

मन की प्रयोगशाला

पेट्स का साथ एंग्जायटी भी घटाता है

पालतू जानवरों के साथ बिताए चंद पल ही टीनएजर्स के मूड में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक शोध में यह सामने आया। शोध में 61 किशोरों ने मिनिएचर हॉर्स और अन्य जानवरों को महज 3 मिनट सहलाया। उन्होंने माना कि इससे उनकी एंग्जायटी और अकेलेपन के भाव में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया जनित तनाव से ग्रस्त किशोरों को शामिल किया था।

सुर्खियों से आगे • ये आततायी क्या खाकर बड़े हुए होंगे, जो इनके भीतर निर्दयता का इतना भंडार है?

अपने ही वजूद की आंच में खुद को सानती वो...

देशकाल

नवनीत गुर्जर

navneet@dbcorp.in

एक सुंदर कविता है-

वो रोटी बेलती है जैसे पृथ्वी
जैसे ज्वालामुखी बेलते हैं पहाड़
जैसे भूचाल बेलते हैं घर
सन्नाटे शब्द बेलते हैं, भाटे समंदर।
रोज सुबह सूरज में एक नई उचकन लगाकर
एक नई धाह फेंककर।
वो रोटी बेलती है जैसे पृथ्वी।
पृथ्वी जो खुद लोई है, सूरज के हाथों में
रख दी गई है पूरी की पूरी सामने
कि लो, इसे बेलो, पकाओ
जैसे मधुमक्खियां पकाती हैं शहद
अपने पंखों की छांह में...।
तब भी, जब सारा शहर सो चुका हो!
धुल चुके हों सारे बरतन
बुझ चुकी हो आखिरी चूल्हे की राख भी
...और वो? अपने ही वजूद की आंच के आगे
औचक हड़बड़ी में, खुद को ही सानती
खुद को ही गूंधती बार-बार
खुश है कि रोटी बेलती है जैसे पृथ्वी...!

महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हर क्षेत्र में। उनमें भी जिन्हें पुरुष कभी अपना एकाधिकार या आधिपत्य मानते थे! लेकिन जमाना इन महिलाओं की राह में आज भी रोड़ा बना हुआ है।

इसी महीने दिल्ली में एक किशोरी के साथ गैंगरेप, एक और किशोरी की हत्या और जमुई में युवती के साथ छेड़छाड़ तथा मारपीट वाली घटनाएं हाड़ कंपा देने वाली हैं।

एक बच्ची पर अत्याचार और यह अत्याचार करते वक्त उसकी चीख सुनकर पसीजना, भागना तो दूर, ऊपर से चीखों का वीडियो बनाते रहना! इस तरह की वैमनस्यता आखिर कहां से और कैसे आती होगी?

सही है- पूरा पुरुष समाज ऐसा नहीं है। केवल कुछ नरभक्षी, आततायी ही यह सब कर रहे हैं। उन्हें किसी समाज, किसी सरकार का खौफ नहीं। किसी दण्ड का भय नहीं। जंगल के चीतों से भी जालिम हैं ये। जमाने भर से तेज हैं नाखून इनके। इनकी ये शैतानी भूख आखिर कब मिटेगी?

जाने कितने दिन और कितनी रातें निगल जाएंगे ये इसी तरह!

कभी कोई तो ये समझे, कि महिलाएं आज अपनी हरियाली को खुद ही अपने लहू से सींच रही हैं।

किसी बाहरी हवा और किसी तरह की बारिश का जरा-सा भी कर्ज नहीं है उन पर। वे जब चाहें खिल सकती हैं। जब चाहें बड़ी, बहुत बड़ी हो सकती हैं।

लेकिन क्या करें! उनकी शारीरिक संरचना ही ऐसी है कि भीतर एक पतली, सुंदर बेल पल रही होती है। यह बेल जब कभी बहुत तेज आंधी हो, किसी मजबूत पेड़ से लिपटना चाहती है।

सिवाय इसके वो हर तरह से मजबूत है। निडर है। बेखौफ भी। माना कि वो हिरनी हैं जन्म से ही। मगर अब शेरनी बनना चाहती हैं।

तो बनने दो।

उस समाज का क्या करें?

हर जगह, नुक्कड़ और गांव-गली में सरकार तो नहीं हो सकती, लेकिन उस समाज का क्या किया जाए, जो इस तरह की घटनाओं पर अपने होंठ सी लेता है, जैसे होंठ न हुए, जेल के बंद दरवाजे हों। सबसे पहले हमारे समाज को संभलना, समझना होगा, जो अभी भी कई दर्द भरी चीखें सुनकर जाग नहीं पाता या नींद में गाफिल होने का प्रहसन करता रहता है!

इन आततायी पुरुषों को आखिर हर्ज ही क्या है?

दरअसल महिलाओं पर अत्याचार के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार अगर सख्त से सख्त कानून बनाए तो कुछ हद तक यह सब सीमित हो सकता है, लेकिन सरकारें तो चाहे जिस दल या पार्टी की हों, उनका स्वभाव एक जैसा ही होता है।

चुनाव-जिताऊ घोषणाओं को राज्य या देश के प्रति कर्तव्य बताकर राज करना ही उनका उद्देश्य रहा है।

खैर, हर जगह, नुक्कड़ और गांव-गली में सरकार तो नहीं हो सकती, लेकिन उस समाज का क्या किया जाए, जो इस तरह की घटनाओं पर अपने होंठ सी लेता है, जैसे होंठ न हुए, जेल के बंद दरवाजे हों।

सबसे पहले हमारे समाज को संभलना, समझना होगा, जो अभी भी कई दर्द भरी चीखें सुनकर जाग नहीं पाता या नींद में गाफिल होने का प्रहसन करता रहता है!

समझना होगा कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही महिलाओं या अन्य किसी के भी सम्मान की शिक्षा किस तरह दे।

किस तरह उन्हें सत का मार्ग दिखाए। गलत रास्तों पर जाने से रोके!

हमें समझना होगा कि बेशक, पत्थरों को हथौड़े से कूटने पर किसी तरह का खून नहीं बहता लेकिन दर्द तो उन्हें भी होता ही होगा! फिर हम सब तो मनुष्य हैं।

कितना दर्द होना चाहिए। क्यों नहीं होता?

आखिर ये आततायी पुरुष क्या खाकर बड़े हुए होंगे, इनके भीतर निर्दयता का आखिर कितना बड़ा भंडार इकट्ठा है, जो आज के युग में भी महिलाओं, स्त्रियों, बच्चियों को चीज समझ रहे हैं? उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें लूट रहे हैं!

आखिर क्यों? क्यों?...

और क्यों?

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दूरदृष्टि • दोनों महाशक्तियों में वर्चस्व की जंग

ट्रम्प और शी की मुलाकात में बहुत कुछ दांव पर लगा है

भू-राजनीति

सैयद अता हसनैन

बिहार के राज्यपाल और कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा दुनिया के कूटनीतिक रंगमंच की बड़ी घटना है। खुद ट्रम्प उन्हें निजी तौर पर रिसीव करने पहुंच सकते हैं, जो कि एक दुर्लभ बात होगी। लेकिन रेड कार्पेट, व्हाइट हाउस डिनर और सुनियोजित ढंग से हाथ मिलाने के दृश्यों के पीछे एक अजीब विरोधाभास भी छिपा है : दो महाशक्तियां- जो एक-दूसरे प्रतिद्वंद्विता में गहराई तक उलझी हुई हैं- घरेलू दबावों और बिखरती विश्व-व्यवस्था के बीच रास्ता तलाशते हुए स्थिरता का बाहरी आवरण पेश करने की कोशिश कर रही हैं। यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति के एक निर्णायक मोड़ पर हो रहा है और इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है।

हकीकत यह है कि आज का वैश्विक परिदृश्य सहयोग नहीं, गुटों और समूहों में ध्रुवीकरण से तय हो रहा है। कुछ ही सप्ताह पहले हुई ब्रिक्स समिट और उससे पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में चीन ने सैन्य गठबंधनों के बिना आगे बढ़ने वाले दृष्टिकोण को सामने रखा था और अमेरिका पर परोक्ष हमले किए थे। लेकिन यह भी सच है कि बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग के अभाव ने दुनिया भर में जारी संघर्षों को खतरनाक ढंग से अनियंत्रित छोड़ दिया है।

ट्रम्प प्रशासन ईरान में महंगी साबित हो रही लड़ाई और होर्मुज में लगातार जारी व्यवधानों में बुरी तरह उलझा हुआ है। यह ऐसा भू-राजनीतिक दलदल है, जिसने ट्रम्प की अप्रूवल-रेटिंग को निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। अमेरिका को लगता है कि चीन के पास तेहरान पर आर्थिक दबाव डालने की क्षमता है। लेकिन चीन ने अपने हितों की कीमत पर किसी की राह में रोड़ा बनने की बहुत कम इच्छा दिखाई है और प्रतिबंधों से बचने के उपायों के जरिए ईरान से अपने व्यापारिक संबंधों को भी लगातार मजबूत बनाए रखा है।

ट्रम्प-शी मुलाकात का बुनियादी प्रयोजन लेन-देन पर आधारित व्यापार है। 10 नवंबर की वह डेडलाइन निकट आती जा रही है, जब अमेरिका-चीन टैरिफ 'युद्धविराम' की अवधि समाप्त होनी है। दक्षिण कोरिया के बुसान में हुए समझौते के तहत इस युद्धविराम ने चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 20 प्रतिशत पर सीमित रखने में सफलता हासिल की और उस आर्थिक तबाही को टाल दिया, जिसकी आशंका तब पैदा हो गई थी, जब जवाबी शुल्कों की होड़ के चलते टैरिफ के तीन अंकों तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। समिट से पहले न्यूयॉर्क में इस बात की बुनियाद तैयार कर दी गई है कि कम टैरिफ के दायरे में लाए जा सकने वाले गैर-रणनीतिक उपभोक्ता सामानों की पहचान की जा सके। लेकिन इसके बदले में ट्रम्प चीन से अमेरिकी कृषि उत्पादों की बड़े पैमाने पर खरीद और 500 तक बोइंग विमानों की खरीद की मांग कर रहे हैं।

मुख्य टकराव के मुद्दे एआई और महत्वपूर्ण खनिज भी हैं। ट्रम्प ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी एआई की दौड़ जीतेगा, वही विजेता होगा। अमेरिका रेयर-अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भी आक्रामक प्रयास कर रहा है।

एक अन्य आयाम दोनों नेताओं की शारीरिक क्षमताओं का भी है। 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स के एक प्रमुख रात्रिभोज में शी जिनपिंग के शामिल न होने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें चरम पर पहुंच गई थीं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन अफवाहों को गलत करार दिया और बाद में सामने आए वीडियो में शी को बिना किसी की मदद के अपने विमान में सवार होते हुए देखा गया। 80 वर्षीय ट्रम्प की सेहत को लेकर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। हाल के कई सर्वेक्षणों में अनेक मतदाताओं ने लम्बे समय तक काम कर पाने की ट्रम्प की क्षमता को लेकर सवाल उठाए हैं।

वॉशिंगटन समिट की असली प्राथमिकता कोई बड़ा भू-राजनीतिक समझौता हासिल करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बनी अनिश्चित स्थिति को मैनेज करना है। शी और ट्रम्प दोनों जानते हैं कि आपसी रिश्तों का पूरी तरह टूट जाना आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा।

वॉशिंगटन समिट की असली प्राथमिकता कोई बड़ा भू-राजनीतिक समझौता हासिल करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बनी अनिश्चित स्थिति को मैनेज करना है। शी और ट्रम्प दोनों जानते हैं कि आपसी रिश्तों का पूरी तरह टूट जाना आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। आज की विभाजित विश्व-व्यवस्था में, अच्छी तरह से मैनेज किया गया वैसा कोई गतिरोध ही शायद इन दोनों महाशक्तियों के बीच शांति की सबसे करीबी स्थिति हो सकती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विश्लेषण • क्योंकि ये एक-दूसरे की पूरक होती हैं

कोर्ट की निगरानी और सरकार की कार्रवाई साथ में ही असरदार

ज्यूडिशियरी

अर्घ्य सेनगुप्ता
स्वप्निल त्रिपाठी
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में पदाधिकारी

पिछले सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक असामान्य टिप्पणी की। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह नई दिल्ली स्थित एनटीए के नए मुख्यालय का दौरा कर सकती है। मकसद यह देखना है कि एनटीए ने कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे को लेकर कोर्ट के सामने जो दावे किए हैं, वे जमीन पर कितने सही हैं और क्या वह परीक्षाएं ठीक से कराने में सक्षम है।

आम तौर पर न्यायाधीश अदालत के भीतर उनके समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन स्थल निरीक्षण के भी इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। 1978 में सुनील बत्रा ने तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई कर रही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एच. बेग और जस्टिस कृष्ण अय्यर तथा कैलासम की पीठ स्वयं तिहाड़ पहुंची और वहां जेल तथा कैदियों की स्थिति देखी। उस समय कोर्ट के सामने एक अन्य कैदी चार्ल्स शोभराज भी था, जिसने लंबे समय तक बेड़ियों में रखे जाने के नियम को चुनौती दी थी। न्यायाधीशों ने निरीक्षण के दौरान जो देखा, उसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। अंततः शोभराज की बेड़ियां हटाने और उसे विचाराधीन कैदियों को मिलने वाली अन्य स्वतंत्रताएं देने का आदेश दिया।

ऐसा ही एक मामला 2017 में गुजरात हाई कोर्ट के सामने आया। जस्टिस हर्षा देवानी और ए.एस. सुपेहिया 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा पाटिया नरसंहार में दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे थे। दोनों न्यायाधीश स्वयं नरोदा पाटिया गए, ताकि घटनास्थल और उसकी भौगोलिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें। दोनों पक्षों के वकीलों ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था।

जमीनी हकीकत जानने के लिए इस तरह के निरीक्षण का इस्तेमाल विशेष रूप से जनहित याचिकाओं में होता रहा है। जनहित याचिका में कोई व्यक्ति दूसरों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला भी कोर्ट के सामने उठा सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में न्यायाधीश स्वयं मौके पर गए हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में अदालतें अपनी ओर से कमिश्नर या न्यायमित्र नियुक्त करती रही हैं। इसका एक उदाहरण विधि विशेषज्ञ प्रो. उपेंद्र बक्षी द्वारा आगरा के सरकारी संरक्षण गृहों में रह रही महिलाओं की खराब स्थिति को लेकर दायर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रहने वाली लड़कियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे और आगरा के जिला न्यायाधीश को संरक्षण गृह का निरीक्षण करने को कहा था।

यही सिद्धांत एनटीए से जुड़े मौजूदा मामले पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि एनटीए के ढांचे में क्या बदलाव जरूरी हैं। क्या उसके पास पर्याप्त स्थायी कर्मचारी हैं? क्या अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए विशेष विभाग हैं? क्या उसके पास देशभर में इतनी बड़ी परीक्षाएं ठीक से कराने के लिए जरूरी सुविधाएं हैं? ऐसे में एनटीए मुख्यालय जाकर देखने से न्यायाधीश समझ सकते हैं कि एक सक्षम परीक्षा एजेंसी के लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्थाएं केवल कागज पर हैं या वास्तव में भी हैं।

अदालतें सरकार से सवाल पूछ सकती हैं, उसकी जवाबदेही तय कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कार्रवाई करने का निर्देश भी दे सकती हैं। लेकिन किसी जटिल प्रशासनिक व्यवस्था को तैयार करने और चलाने की जिम्मेदारी अंततः कार्यपालिका की ही है।

लेकिन केवल एक अच्छा मुख्यालय किसी परीक्षा को पेपर लीक से सुरक्षित नहीं बना सकता। परीक्षा कराने की प्रक्रिया काफी लंबी है। प्रश्नपत्र तैयार करने और उसे सुरक्षित रखने से लेकर उसकी छपाई या डिजिटल माध्यम से भेजे जाने, परिवहन, सुरक्षित अभिरक्षा और अंत में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और बांटने तक कई चरण होते हैं। इनमें से किसी भी चरण में हुई एक चूक पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकती है। इसलिए सरकार को पूरी व्यवस्था को बार-बार परखना होगा।

लेकिन कोर्ट को भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना और चलाना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसे उदाहरण भी हैं, जब अच्छे उद्देश्य से शुरू हुआ अदालती हस्तक्षेप धीरे-धीरे प्रशासन के रोजमर्रा के फैसलों तक पहुंच गया था। 2000 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की बसों को सीएनजी में बदलने को लेकर दिखलाई सक्रियता इसी की मिसाल है।

(ये लेखकों के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • रोजर हों या सचिन, वास्तविक रोल मॉडल वे ही हैं, जो परिवार में भी मनुष्यता के नायक हों...

चैम्पियन माइंडसेट क्या है? जीवन में जीतना, पर सही उसूलों के साथ

फैमिली फर्स्ट

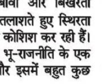

नन्दितेश निलय

वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक

nanditeshnilay@gmail.com

किसी भी क्षेत्र में चैम्पियन तो बना जा सकता है, पर रोल मॉडल बने रहना तभी संभव है, जब समय आपका आकलन जीवन-मूल्यों से करे। क्या आप भी इस बात से राजी नहीं हैं कि एक रोल मॉडल बनने का अर्थ परिवार की ओर मुड़कर फिर से अपने जीवन-मूल्यों को याद करना और संभाले रहना होता है? इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हमें मिरका फेडरर के उस भाषण से गुजरना होगा, जो उन्होंने 29 अगस्त 2026 को हॉल ऑफ फेम में आधिकारिक रूप से शामिल होने के लिए अपने पति, टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर का परिचय देने के लिए मंच संभालते हुए दिया था। मिरका ने कहा..., मेरा यकीन मानिए, मैंने उनकी मेहनत, उनकी घंटों की प्रैक्टिस, उनका अनुशासन और समर्पण देखा है। मैंने वह सब देखा है, जिससे यह सब इतना आसान लगता है। और उनके हजार से ज्यादा मैच देखने के बाद भी मैं हमेशा हैरान रह जाती थी। लेकिन इसके पीछे का इंसान और भी कमाल का है। ...उनके माता-पिता उन्हें एक प्यारे बेटे के तौर पर जानते हैं। उनकी बहन उन्हें एक बेहतरीन भाई मानती है। और उनके दोस्त उन्हें ऐसे इंसान के तौर पर जानते हैं, जिनके पास हमेशा उनके लिए समय होता है, चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए। और ये खूबियां अचानक नहीं आईं। उन्होंने ये बातें अपने माता-पिता से सीखीं। उन्होंने उन्हें विनम्रता, आभार और दयालुता सिखाई। और उन्होंने उन्हें सिखाया कि सबके साथ एक जैसा सम्मानजनक व्यवहार करें।

आगे उन्होंने कहा, दुनिया रोजर फेडरर को जानती, उससे बहुत पहले ही, रॉबी और लिनेट (रोजर के पैरेंट्स) ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया, जिसकी मैं और भी ज्यादा तारीफ करती हूं : मेरा साथी रोजर, दोस्त रोजर और आखिर में एक पति और पिता रोजर।

जिस दौर में सबकुछ टूट रहा हो, इंसानियत या इंसान बने रहने का भाव अनावश्यक और कुछ बोझिल-सा महसूस हो रहा हो, जहां परिवार में सभी के साथ रहना और माता-पिता को सुनना-समझना कठिन होता जा रहा हो, जहां दाम्पत्य जीवन और पैरेंटिंग के नित-नए सूत्र ढूंढे जा रहे हों, वहां स्विट्जरलैंड के हीरो रोजर फेडरर के परिवार की जड़ों को अटूट देखना बहुत सुखद लगता है और इससे यह विश्वास भी प्रबल होता है कि वास्तविक चैम्पियन सबसे पहले और आखिर तक एक बहुत अच्छा इंसान ही होता है।

वहीं, रोजर फेडरर भी मानते हैं कि अगर मिरका न होतीं तो वे इतने बेफिक्र होकर लंबे समय तक टेनिस नहीं खेल पाते। रोजर से रोजर फेडरर बनने में भी उनके परिवार की ही सबसे बड़ी भूमिका रही। जब वे जूनियर खिलाड़ी के तौर पर गुस्सा करते थे या रैकेट फेंकते थे, तब भी उनके माता-पिता उन्हें शांत रहकर खेल का सम्मान करना सिखाते थे। उनके शब्दों में, आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने माता-पिता के बिना शर्त प्यार और समर्थन की वजह से हूं।

टेनिस में रोजर फेडरर की ही तरह क्रिकेट की दुनिया की किंवदंती सचिन तेंदुलकर ने भी हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर अपने पिता को याद करते हुए एक फेलोशिप की घोषणा की और इस अवसर पर बहुत कुछ कह गए। उनके पिता उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि असफलता ठीक है, लेकिन शॉर्टकट ठीक नहीं। खेल में या कहीं भी धोखा देना ठीक नहीं है। लोग उनके शतकों को भूल जाएंगे, लेकिन वे कितने अच्छे इंसान रहे और समाज के लिए क्या किया, यह याद रखा जाएगा।

यानी रोजर हों या सचिन, चैम्पियंस तभी वास्तविक चैम्पियन और रोल मॉडल बनते हैं, जब वे अपने परिवार में भी इंसानियत के चैम्पियन हों। इसलिए जहां दुनिया उनको चैम्पियन और रोल मॉडल के रूप में याद करती है, वहीं वे परिवार द्वारा सिखाए जीवन-मूल्यों को नहीं भूलते। और यह न भूलिए कि सफलता और शोहरत जब सिर चढ़कर बोलती है तो कृतज्ञता, सादगी, विनम्रता और अच्छाइयों को अपने व्यवहार में संभाले रखना आसान नहीं होता। लगातार अच्छा इंसान बने रहना ही सही मायनों में चैम्पियन माइंडसेट होता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हुरुन लिस्ट • दस साल पहले 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वालों की संख्या सिर्फ दो थी, अब 23 हुई, रिकॉर्ड 70% सेल्फ मेड, 5 साल पहले ऐसे 55% थे

घरेलू सामान के कारोबारियों की दौलत घटी, डिफेंस में 69% बढ़ी; नए एआई अमीरों की औसत संपत्ति 5 गुना

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश में दौलत बनाने वाले कारोबार की तस्वीर बदल रही है। घरेलू खरीदारी से जुड़े कई सेक्टर के अमीरों की संपत्ति घटी है, जबकि डिफेंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रिन्युएबल एनर्जी से जुड़े कारोबारियों की दौलत तेजी से बढ़ी है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, टिकाऊ उपभोक्ता सामान सेक्टर में संपत्ति 21% घटी। इसके उलट विमानन-अंतरिक्ष और डिफेंस सेक्टर में 69% बढ़ी। एआई जैसी नई तकनीक में भी संपत्ति बन रही है। पहली बार इस लिस्ट में जुड़े एआई सेक्टर में 19 लोग हैं, औसत संपत्ति 12,100 करोड़ है। यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नए एंट्रेंट की औसत संपत्ति से 5 गुना है।

उद्योगों में निवेश से जुड़े सेक्टर पैसे बनाने में आगे

सेक्टर	संपत्ति में बदलाव
विमानन-अंतरिक्ष व रक्षा	+69%
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स	+31%
रिन्युएबल एनर्जी	+31%
धातु और खनन	+30%
फॉर्मा इंडस्ट्री	+25%
वित्तीय सेवाएं	+23%
खुदरा कारोबार	-5%
उपभोक्ता वस्तुएं	-8%
खाद्य और पेय	-9%
टिकाऊ उपभोक्ता सामान	-21%

▪ हुरुन की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता आधारित सेक्टरों में गिरावट की वजह घरेलू खर्च में सुस्ती और पहले से ऊंचे वैल्यूएशन हैं।

एआई की बड़ी दौलत उसके बुनियादी ढांचे में; 4 के पास नए समूह की 77% संपत्ति

भारत में एआई की ग्रोथ स्टोरी उसके इस्तेमाल वाले एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। लिस्ट में डेटा सेंटर और चिप की टेक्नोलॉजी से जुड़े चार नए एंट्रेंट की संयुक्त संपत्ति अब 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह एआई से जुड़े सभी 15 नए नामों की संपत्ति का करीब 77 फीसदी है।

नाम	कंपनी	संपत्ति
श्रीधर पिन्नापुरेड्डी	सीटीआरएलएस	46,100
दर्शन हीरानंदानी	योट्टा	37,900
जितेन्द्र मोहन	एस्टेरा लैब्स	28,800
संजय गजेंद्र	एस्टेरा लैब्स	27,600
कुल	(आंकड़े करोड़ रु. में)	1,40,400

▪ 19 में से 13 एआई लिस्टर्स भारत के बाहर हैं। यह भारतीय मूल की टेक्नोलॉजी टैलेंट की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। मुंबई 93 डॉलर अरबपतियों का घर, कुल संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा है।

अदाणी की संपत्ति बढ़ी, अंबानी की घटी, पर मित्तल की दोगुना बढ़ी टॉप 10 में अदाणी-अंबानी की कुल संपत्ति 59% से 46% रह गई

रैंक	फैमिली	संपत्ति	बदलाव
1 (+1)	गौतम अदाणी	9,22,800	▲ 13%
2 (-1)	मुकेश अंबानी	8,63,400	▼ 10%
3 (नए)	एलएन मित्तल	3,39,300	▲ 93%
4 (–)	साइरस पूनावाला	3,03,400	▲ 23%
5 (-2)	रोशनी नाडार	2,78,500	▼ 2%
6 (-1)	के एम बिड़ला	2,68,700	▲ 15%
7 (–)	दिलीप संघवी	2,64,600	▲ 15%
8 (–)	अजीम प्रेमजी	2,62,800	▲ 19%
9 (नए)	अनिल अग्रवाल	2,08,300	▲ 87%
10 (नए)	समीर मेहता	1,89,400	▲ 52%

नोट: संपत्ति करोड़ रुपए में, (–) कोई बदलाव नहीं।

▪ इस साल भारत में 76 नए डॉलर अरबपति बने, जिनमें 51 भारत में रहते हैं। हैदराबाद के श्रीधर पिन्नापुरेड्डी एंड फैमिली (46,100 करोड़) भारत-निवासी नए अरबपतियों में टॉप पर रहे।

▪ 2022 में टॉप-10 की कुल संपत्ति में अदाणी-अंबानी की संयुक्त संपत्ति 18.89 लाख करोड़ थी और हिस्सेदारी 59% थी। टॉप-10 के बाकी 8 की संपत्ति 13 लाख करोड़ से ₹5.84 लाख करोड़ ज्यादा थी।
▪ 2026 में अदाणी-अंबानी की संपत्ति घटकर 17.86 लाख करोड़ रह गई, जबकि बाकी 8 की 21.15 लाख करोड़ हो गई। यह अदाणी-अंबानी की कुल संपत्ति से 3.3 लाख करोड़ ज्यादा हैं।
▪ टॉप-10 में दोनों की हिस्सेदारी घटकर 46% रह गई है।

छोटे शहरों के उद्यमी दे रहे नई पहचान, तो 70% ने खुद बनाई संपत्ति, दो तिहाई नई पीढ़ी को देंगे कुर्सी

▪ एआई कैटेगरी के 68% नाम और शीर्ष 10 नए प्रवेशकों में से 8 अमीर विदेश में रहते हैं; अमेरिका और यूएई में इनकी संख्या बढ़ी है।
▪ एक लाख करोड़ से अधिक संपत्ति वाले 23 महाअमीरों के पास 54 लाख करोड़ है। इसके विपरीत, 1,000 से 5,000 करोड़ के दायरे वाले 1,157 नामों की संयुक्त संपत्ति 26.70 लाख करोड़ है। यानी संख्या के लिहाज से सूची के महज 1.3% नामों के पास ही कुल संपत्ति का 28.9% हिस्सा केंद्रित है।
▪ सूची में 9 नए कस्बे और शहर जुड़े हैं, जहां बागलकोट, सोलन, मंडी गोबिंदगढ़ और मिर्जापुर के उद्यमी जैव ऊर्जा, विशेष धातुओं और इंजीनियरिंग सेक्टर से उभरे हैं।
▪ देश में अपने दम पर संपत्ति बनाने वाले कारोबारियों की हिस्सेदारी पिछले पांच सालों में 55% से बढ़कर 70% हो गई है। सूची में ऐसे 1,266 नाम शामिल हैं जिन्होंने खुद अपनी दौलत खड़ी की है, जबकि विरासत में संपत्ति पाने वाले कुल 544 लोग हैं। इस अमीर सूची के लोगों की औसत उम्र 64 साल है।
▪ दो-तिहाई अब नई पीढ़ी को कुर्सी देने के करीब हैं, जिसके चलते आने वाले समय में उत्तराधिकार और पेशेवर प्रबंधन कारोबार की दिशा तय करने में अहम होंगे।

बिजनेस ब्रीफ

जोहो ने पेश किया एआई टूल जिया चैट, ये लागत घटाएगा

चेन्नई | घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने बुधवार को कंपनियों के लिए एआई टूल जिया चैट पेश किया। इसके साथ ही जोहो ने रिटेल, ऑटोमोटिव और बैंकिंग समेत 7 अलग-अलग उद्योगों के लिए नए सॉफ्टवेयर भी उतारे हैं। सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने बताया कि जिया चैट काम की लागत घटाएगा। साल 2025 में जोहो का कारोबार 47% बढ़ा है। कंपनी के पास 19 हजार कर्मचारी हैं।

यूएस बैंक जेपी मॉर्गन गिफ्ट सिटी बिजनेस दोगुना करेगा

अहमदाबाद | अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन गुजरात के गिफ्ट सिटी में बिजनेस दोगुना करने जा रहा है। अभी इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में बैंक का बिजनेस करीब ₹9,574 करोड़ का है। इसे अगले कुछ वर्षों में बढ़ाकर ₹19,148 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। मार्च 2026 तक यहां की बैंकिंग संपत्तियां ₹10.6 लाख करोड़ हो गई हैं। सीईओ जेमी डिमन के अनुसार 7.8% ग्रोथ के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

मास्टरकार्ड ने पाइन लैब्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली | ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड ने बीएसई पर ब्लॉक डील के जरिए पाइन लैब्स में अपनी पूरी 4.31% हिस्सेदारी बेच दी। यह डील ₹933 करोड़ में 13 अलग चरणों में हुई। इसमें 4.97 करोड़ शेयर ₹187.75 के भाव पर बिके। ये हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा, एडलवाइस, फ्रैंकलिन टेम्पलटन और कई विदेशी निवेशकों ने मिलकर खरीदी। बीएसई पर बुधवार को पाइन लैब्स के शेयर 4.6% गिरकर 188.40 पर बंद हुए।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदला

मुंबई | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 22 सितंबर से अपना नाम बदलकर आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कर लिया है। इसके लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी और नया सर्टिफिकेट मिल गया है। शेयरधारकों से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी संशोधन कर दिया गया है।

भारत: 89 करोड़ योग्य लोगों में से सिर्फ 28% लोन ले रहे

नई दिल्ली | देश की कुल आबादी में लोन लेने योग्य 89 करोड़ लोगों में से सिर्फ 28% ही कर्ज ले रहे हैं। करीब 60 करोड़ लोगों के पास अपना कोई पुराना क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है। डेटा सूत्रम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में कर्ज लेने वालों का दायरा बहुत सीमित है। बैंकिंग व्यवस्था से दूर इन करोड़ों लोगों तक पहुंचना ही वित्तीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका है।

टाटा ग्रुप • होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में विवाद के बीच नए खुलासे से बढ़ा टकराव

जिन वेणु के वोट से 'चंद्रा' को एक्सटेंशन, उन्हीं के ग्रुप से परिवार का बिजनेस लिंक

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

टाटा ग्रुप में मौजूदा खींचतान के बीच एक नया विवाद सामने आया है। होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (चंद्रा) के परिवार का टीवीएस मोटर से कारोबारी रिश्ता सामने आया है। टीवीएस के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन ने टाटा संस के बोर्ड में चंद्रशेखरन को तीसरा कार्यकाल देने के पक्ष में निर्णायक वोट डाला था।

एन. चंद्रशेखरन | वेणु श्रीनिवासन | नोएल टाटा

दूसरी तरफ कंपनी में करीब 66% हिस्सेदारी वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा बोर्ड के इस फैसल के खिलाफ हैं। दस्तावेजों के मुताबिक, चंद्रशेखरन के बेटे प्रणव और पत्नी ललिता, हैन्रो वन वेयरहाउसिंग नाम की कंपनी में डायरेक्टर हैं। इसे टीवीएस मोटर ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में 17 एकड़ जमीन लीज पर दी हुई है। इसके दम पर एचडीएफसी बैंक से कंपनी को 60 करोड़ रुपए का लोन भी मिला। इसकी जानकारी कथित तौर पर बोर्ड को नहीं दी गई थी। यह खुलासा टाटा संस के बोर्ड में नोएल टाटा और चंद्रशेखरन गुट के बीच पहले से जारी खींचतान बढ़ा सकता है।

मामला गंभीर क्यों... हितों के टकराव का डिस्क्लोजर नहीं करने का आरोप, श्रीनिवासन उस कमेटी के सदस्य, जो चंद्रशेखरन के काम की समीक्षा करती है

टाटा संस की कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (हितों का टकराव) तब माना जाता है जब कोई अधिकारी किसी डील को प्रभावित करके खुद, परिवार या करीबी को फायदा पहुंचाए। नियम कहता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऐसे संभावित टकराव की जानकारी बोर्ड को पहले से देनी होती है। यहां सबसे बड़ा पेंच ये है कि श्रीनिवासन नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के सदस्य हैं, जो चंद्रशेखरन के परफॉर्मेंस की समीक्षा करती है। यही वजह है कि डिस्क्लोजर न होना गंभीर माना जा रहा है।

टर्निंग पॉइंट: नोएल टाटा को मिल सकता है चंद्रशेखरन के खिलाफ मौका... टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा पहले ही चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल और टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध कर चुके हैं। श्रीनिवासन का वोट उनके खिलाफ गया था। अब पारिवारिक कारोबारी रिश्ते की बात सामने आने से नोएल टाटा गुट को यह तर्क देने का नया आधार मिल सकता है कि निर्णायक वोट निष्पक्ष नहीं था।

असर: चंद्रशेखरन का एक्सटेंशन और लिस्टिंग, दोनों के प्रस्ताव अब कमजोर पड़ सकते हैं
अगर बोर्ड या ट्रस्ट इसे गंभीर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं, तो श्रीनिवासन के वोट की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे चंद्रशेखरन की नियुक्ति और लिस्टिंग प्रस्ताव, दोनों कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स, टीवीएस मोटर या एन चंद्रशेखरन में से किसी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बोर्ड पर जांच शुरू करने का दबाव बढ़ेगा
▪ यह नया मामला सामने आने के बाद टाटा संस के बोर्ड पर जांच शुरू करने का दबाव बन सकता है, जैसा पिछले साल कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय के मामले में हुआ था।
▪ रिपोर्ट आने के एक हफ्ते के भीतर जांच बिठाई गई थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञ श्रीनाथ श्रीधरन के मुताबिक, चूंकि श्रीनिवासन खुद नॉमिनेशन कमेटी में हैं, इसलिए पूरा खुलासा जरूरी था।

भास्कर नॉलेज

कौन हैं वेणु श्रीनिवासन?

वेणु श्रीनिवासन टीवीएस ग्रुप के संस्थापक टीवी सुंदरम अयंगर के पोते हैं। उन्होंने 1980 के दशक में तत्कालीन सुंदरम-क्लेटन के दोपहिया कारोबार की कमान संभाली।
▪ टीवीएस मोटर को देश के प्रमुख दोपहिया-तिपहिया निर्माताओं में शामिल कराने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।
▪ पिछले साल इन्होंने बेटे सुदर्शन वेणु को टीवीएस मोटर की कमान सौंपी थी। श्रीनिवासन टीवीएस मोटर के मानद चेयरमैन हैं।
▪ 2016 से टाटा संस के बोर्ड में हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट के वाइस-चेयरमैन हैं।
▪ 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीनिवासन 2022 से रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर भी हैं।
▪ ये हाल में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के निर्देश को दरकिनार करके टाटा संस के आईपीओ के पक्ष में वोट देकर सुर्खियों में आए थे।

इक्विटी मार्केट • ज्यादा कमाई के लालच में छोटे-मझोले शेयरों पर दांव

बाजार चढ़ा, पर संतुलन बिगड़ रहा... लार्जकैप के मुकाबले स्मॉलकैप शेयर दोगुना महंगे हुए

भास्कर न्यूज | मुंबई

शेयर बाजार में बुधवार को हल्की तेजी रही। सेंसेक्स 299 अंक चढ़कर 74,828 पर और निफ्टी 118 अंकों की तेजी के साथ 23,447 पर बंद हुआ। लेकिन बाजार संतुलित नहीं है। लार्जकैप के मुकाबले स्मॉलकैप और मिडकैप शेयर काफी महंगे हो गए हैं। मसलन, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 अभी 19.7 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 100 स्मॉलकैप इंडेक्स का पीई लगभग दोगुना 34.4 है। निफ्टी मिडकैप 100 का पीई भी करीब 30 है। पीई यानी प्राइस-टू-अर्निंग रेशियो बताता है कि किसी कंपनी का शेयर उसकी प्रति शेयर कमाई (ईपीएस) के मुकाबले कितने गुना भाव पर ट्रेड कर रहा है।

ग्रोथ शेयरों पर निवेशकों का फोकस, छोटी कंपनियों में मौके, एनएसई की तगड़ी लिस्टिंग की उम्मीद कम

भास्कर एक्सपर्ट

वीके विजयकुमार,
मुख्य निवेश रणनीतिकार, जियोजीत इंवेस्टमेंट्स

अभी निवेशकों का फोकस ग्रोथ शेयरों पर है, इसलिए डिजिटल और नई पीढ़ी की कंपनियों को ऊंचा वैल्युएशन मिल रहा है। विदेशी निवेशक जुलाई-अगस्त में खरीदार बने पर सितंबर में फिर बिकवाल हो गए। उनकी वापसी से यह अंतर कम हो सकता है।

इस माह 69% आईपीओ से लिस्टिंग गेन एस इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में लिस्ट 16 आईपीओ में से 11 (69%) ने लिस्टिंग गेन दिया। सिर्फ 5 इश्यू प्राइस से नीचे लिस्ट हुए। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर 74% प्रीमियम पर लिस्ट होकर अब इश्यू प्राइस से 297% ऊपर है। ग्लास वॉल सिस्टम्स (70%), करमतारा इंजीनियरिंग (44%) शुरुआती बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे।
▪ मास्टर कैपिटल के मुताबिक, ऊपरी प्राइस बैंड पर एनएसई का वैल्युएशन वित्त वर्ष 2025-26 में कमाई का 43 गुना है। इतने बड़े इश्यू में छोटे इश्यू की तर्ज पर तगड़ी लिस्टिंग की उम्मीद कम।

19 फीट 8 इंच लंबी यह कार दो शेवरले इम्पाला के चेसिस जोड़कर बनाई गई थी

बैटमैन की 'बैटमोबाइल' नीलाम होगी; 67 करोड़ तक लग सकती है बोली, इस कीमत पर यह अब तक की सबसे महंगी 'मूवी कार'

लॉस एंजेलिस | टिम बर्टन की 1992 की फिल्म बैटमैन रिटर्न्स में माइकल कीटन जिस बैटमोबाइल में सवार होकर गॉथम सिटी की गलियों में दौड़े थे, वो अब बिक रही है। यह कार 23 नवंबर को जूलियन्स ऑक्शन में नीलाम होगी। अनुमानित कीमत 50-70 लाख डॉलर (₹67 करोड़ तक) आंकी जा रही है। इस कीमत पर यह अब तक की सबसे महंगी 'मूवी कार' बना सकती है। 19 फीट 8 इंच लंबी यह कार दो शेवरले इम्पाला के चेसिस जोड़कर बनाई गई थी। फाइबरग्लास बॉडी पर जेट-टर्बाइन डिजाइन और विशाल 'बैट-विंग्स' इसे खास बनाते हैं। इसमें दमदार शेवरले वी8 इंजन लगा है।

भ्रामक दावों, प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर शिकंजा

अमेजन, स्विगी समेत 5 प्लेटफॉर्म के खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया शुरू

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

ऑनलाइन बिक रहे फूड प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर भारतीय खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सख्ती बढ़ा दी है। प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन और भ्रामक दावे करने पर देश के पांच बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। इसकी जद में आने वाले प्लेटफॉर्म्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट, बिगबास्केट और जेप्टो हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत की जा रही है। हालांकि, सामने आई शुरुआती जानकारी में किसी जुर्माने की राशि या अंतिम आदेश का आधिकारिक ब्योरा अभी साझा नहीं किया गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ऑनलाइन बाजार और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स की नियामकीय निगरानी तेज की जा रही है।

हैपिलो के दावे, मिल्की मिस्ट की जानकारी, धतूरा बेचने पर सवाल

भ्रामक दावे: एफएसएसएआई ने 'हैपिलो प्रीमियम डेट बाइट्स-जेस्टी ऑरेंज' को लेकर किए गए दावों पर तीखी आपत्ति जताई है। नियामक के मुताबिक, ये नियमों के अनुरूप नहीं हैं। यह प्रोडक्ट पांचों प्लेटफॉर्म्स पर चल रही इस कार्रवाई का हिस्सा है।
डेयरी उत्पाद: प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट पर 'मिल्की मिस्ट' के तीन प्रोडक्ट्स की जानकारी और दावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इनमें फ्रेश लो फैट क्रीम, फार्म फ्रेश कर्ड और ग्रीक योगर्ट शामिल हैं।
प्रतिबंधित और जहरीली वस्तुएं: बिगबास्केट, अमेजन और स्विगी इंस्टामार्ट पर धतूरे के फल और बीज बेचे जाने का गंभीर मामला भी सामने आया है। इन्हें प्रतिबंधित व जहरीली खाद्य वस्तुओं की कैटेगरी में रखा गया है।

हाईकोर्ट से करण जौहर को राहत

डिलीवरी के तरीके से टैक्स तय नहीं होता, डिमांड खारिज

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने करण जौहर की दो कंपनियों धर्मा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच की 79.7 करोड़ रुपए की टैक्स मांग खारिज कर दी है।

कोर्ट ने साफ किया कि सिनेमैटोग्राफिक फिल्म आईटी सॉफ्टवेयर नहीं है। डिजिटल लिंक या हार्ड डिस्क से भेजने पर भी यह आईटी सॉफ्टवेयर नहीं बनती। सेल्स टैक्स विभाग का तर्क था कि हार्ड डिस्क या डिजिटल लिंक से भेजी जाने वाली फिल्में सॉफ्टवेयर सर्विसेज की श्रेणी में आती हैं, इसलिए इन पर 18% जीएसटी लागू होना चाहिए। जबकि कंपनियां इसे बौद्धिक संपदा अधिकार मानकर 12% टैक्स चुका रही थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिलीवरी के तरीके से टैक्स तय नहीं होता।

सुधार • नियामक इरडा ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर

इंश्योरेंस प्रीमियम 28%, पर कमीशन 125% बढ़ा, अब खर्च की सीमा तय होगी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

बीमा कंपनियां जितना प्रीमियम कमा रहीं, उससे ज्यादा तेजी से एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन दे रही हैं। इसका बोझ पॉलिसीधारकों पर पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए बीमा नियामक इरडा ने बुधवार को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसके मुताबिक, 5 साल में कंपनियों के कुल खर्च की सीमा तय की जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस में यह 12.5% और जनरल इंश्योरेंस में 20% होगी। दरअसल 2023 से 2025 के बीच नया प्रीमियम सिर्फ 28% बढ़ा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 125% उछाल के साथ ₹9,580 करोड़ से बढ़कर ₹21,600 करोड़ हो गया। जनरल इंश्योरेंस में तो ब्रोकर कमीशन 173% तक बढ़ गया। बैंकों के जरिए बिकने वाली पॉलिसियों में कमीशन 72% तक पहुंच जाता है, जबकि लोन के साथ बिकने वाले ग्रुप क्रेडिट लाइफ प्रोडक्ट में यह सिर्फ दो साल में 5% से बढ़कर 45% हो गया।

मुंबई एयरपोर्ट: कोर्ट की सख्ती

ड्यूटी-फ्री दुकानें देश के कानून से बाहर नहीं

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मुंबई एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री दुकानों पर देश के कानून लागू होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन दुकानों को कानूनों से बाहर बताने वाली अदाणी समूह की दलील मंगलवार को खारिज कर दी। इस फैसले से स्पष्ट है कि यहां बिकने वाले निकोटीन पाउच पर घरेलू नियम पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।

सरकार इन पाउच को अवैध दवा मानती है और इसे जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताती है। अदाणी समूह ने अप्रैल में इनकी बिक्री पर रोक को चुनौती दी थी। समूह का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र देश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे होते हैं। कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए स्पष्ट किया कि सीमा शुल्क बाधा के पार होने वाले हर लेनदेन पर देश का कानून लागू रहता है।

अदाणी का यह भी कहना था कि निकोटीन पाउच नया प्रोडक्ट है और यह दवा की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने इस पर स्पष्ट किया कि वह अभी इस सवाल का फैसला नहीं करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने समूह को अपने दस्तावेजों के साथ ड्रग नियामकों के सामने पक्ष रखने की पूरी छूट दी है।

चिंता भी • कमजोर मानसून से महंगाई बढ़ सकती है

वैश्विक एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर अब 7% किया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर (ग्रोथ) का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। पहले इनका अनुमान 6-6.6% था। एसएंडपी, मूडीज और फिच ने भी अपने-अपने अनुमान बढ़ाए हैं। लेकिन कमजोर मानसून और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें महंगाई का नया खतरा बनकर उभर रही हैं। इससे रिजर्व बैंक को नीतिगत दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती हैं। एडीबी के मुताबिक, मानसूनी बारिश लंबे समय के औसत से 15% कम रही है। इससे अगस्त में रिटेल महंगाई 4.8% हो गई। एडीबी ने इस साल औसत महंगाई दर 5.2% रहने का अनुमान लगाया है।

2026 में भारत के लिए पांच ग्लोबल संस्थाओं का अनुमान

संस्था	अब	पहले
एडीबी	7.0%	6.6%
एसएंडपी ग्लोबल	7.0%	6.6%
मूडीज रेटिंग्स	7.0%	6.0%
फिच रेटिंग्स	6.9%	6.4%
ओईसीडी	7.1%	6.3%

बिजनेस एंकर स्नैक्स मार्केट बदल रहा, अब ब्रांड के बजाय अपनी जरूरत बताकर विकल्प खोज रहे ग्राहक

एआई से पूछ रहे अमेरिकी- क्या खाएं; चटपटे स्नैक्स की मांग बढ़ी

भास्कर न्यूज | मुंबई

अमेरिका में हल्की भूख लगने पर क्या खाएं, इसका जवाब अब लोग एआई से भी मांग रहे हैं। ग्राहक किसी खास उत्पाद को खोजने के बजाय ज्यादा प्रोटीन या फाइबर वाले स्नैक्स के विकल्प पूछ रहे हैं। खाद्य कंपनी कोनाग्रा ब्रांड्स के मुताबिक, यह बदलाव ज्यादा प्रोटीन, चटपटे स्वाद और खास स्वास्थ्य जरूरतों के हिसाब से बने उत्पादों की मांग बढ़ाने में मदद कर रहा है।

स्लिम जिम मीट स्टिक और हंट्स केचप बनाने वाली कोनाग्रा ने शोध कंपनी सर्काना के साथ अमेरिकी स्नैक्स बाजार के 17,000 प्रोडक्ट्स से जुड़े 5.3 करोड़ से अधिक खरीदारी लेनदेन का विश्लेषण किया। इस बाजार की सालाना खुदरा बिक्री 198.2 अरब डॉलर (करीब 19 लाख करोड़ रुपए) है। इसकी बढ़ने की रफ्तार व्यापक खाद्य बाजार से करीब 1.4 गुना है। कोनाग्रा के मुताबिक, वजन घटाने वाली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल और व्हाइट हाउस के 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' अभियान से भी स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन में दिलचस्पी बढ़ रही है। ग्राहक सामग्री को ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं और खरीदारी का फैसला करने में एआई की मदद ले रहे हैं। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट बॉब नोलन ने कहा, 'स्नैक्स उपभोक्ताओं की जिंदगी में बड़ी और अधिक व्यक्तिगत भूमिका निभा रहे हैं। कोई प्रोटीन चाहता है, कोई लंबे समय तक ऊर्जा और कोई पसंदीदा स्वाद से सुकून।' सेहत की चाह इस बदलाव का सिर्फ एक हिस्सा है। इस रिसर्च के मुताबिक, युवा ग्राहक, खासकर जेनरेशन जेड, ज्यादा चटपटे स्वाद की मांग बढ़ा रहे हैं। मीठे और तीखे स्वाद के मेल के साथ खट्टे व नमकीन स्वाद वाले स्नैक्स भी उनकी पसंद में हैं। नोलन के मुताबिक, पोषक तत्वों से भरपूर और खास जरूरत के लिए खाए जाने वाले स्नैक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं, कुकीज और नमकीन स्नैक्स जैसी कुछ पारंपरिक श्रेणियां दबाव में हैं। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने ग्राहक एआई से सलाह ले रहे हैं या उसकी सलाह से बिक्री कितनी बढ़ी।

एआई ने स्नैक्स चुनने का पैमाना ही बदल दिया; प्रोटीन, एनर्जी पर फोकस बढ़ा

अमेरिका के साथ ही दुनियाभर में खरीदारी का आधार बदल रहा है। ग्राहक अब पसंदीदा ब्रांड के साथ यह भी देख रहे हैं कि कौन-सा उत्पाद उनकी जरूरत पूरी करेगा। स्वाद के साथ पोषण और पैकेट पर किए गए दावों के साथ उसमें इस्तेमाल सामग्री पर ध्यान बढ़ रहा है। स्नैक्स चुनते समय सिर्फ कुछ खाने की इच्छा नहीं, बल्कि प्रोटीन, ऊर्जा और स्वास्थ्य की खास जरूरतें भी मायने रखने लगी हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

नए सहयोग का समय

यह सुखद और स्वागतयोग्य है कि भारत दुनिया की महाशक्तियों से परे एक अलग मजबूत बहुदेशीय आवाज बनाने की कोशिश करता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान ही भारत, लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों के समूह (सीईएलएसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोटूक कहा है कि ग्लोबल साउथ को वैश्विक व्यवस्था का भविष्य तय करने में मजबूत आवाज हासिल होनी चाहिए। यह कहने में हर्ज नहीं कि ग्लोबल साउथ अर्थात दुनिया के गरीब व विकासशील देशों को परस्पर तालमेल रखते हुए साझा हित देखना ही चाहिए। आज बड़ी शक्तियां किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। खासकर अमेरिका जिस ढंग से दुनिया के हालात बदलने की कोशिश कर रहा है, उसमें गरीब और विकासशील देशों पर सर्वाधिक मार पड़ रही है। यह मार दोहरी है। अव्वल तो आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, विकास के लिए मिलने वाले धन में कमी आई है, तो दूसरी ओर, इन देशों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अमेरिका टैरिफ की एक ही तलवार हर तरफ भांज रहा है। साथ ही, ज्यादातर देशों में ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ाने में लगा है।

ऐसे में, जरूरी है कि उपेक्षित हो रहे देशों की एक संगठित आवाज बने। भारत स्वाभाविक ही सीईएलएसी को समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में एक अहम भागीदार के रूप में देख रहा है। लैटिन अमेरिकी देश हों या कैरेबियाई देश, इन सभी की पीड़ा कमोबेश भारत के समान है। ये देश एक-दूसरे से सीख सकते हैं, एक-दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं और अगर ये मिल जाएं, तो इनकी सुनवाई के रास्ते खुलना तय है। लैटिन और कैरेबियाई देशों के इस समूह की बैठक न्यूयॉर्क में हुई है, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए तमाम देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। इस समूह में 30 देश शामिल हैं और इनकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने की है। इस समूह में बेचैनी है, तभी इसकी बैठक में इतने देश शामिल हुए हैं। न्यूयॉर्क में जो गंभीरता दिखी है, उससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। इन देशों को मिलकर एक ठोस रोडमैप तैयार करना चाहिए। भारत को इस दिशा में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। 1950 के दशक में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन जोर-शोर से शुरू हुआ था, तब उसमें भारत की बड़ी भूमिका थी। बाद में गुटनिरपेक्षता में दरार पड़ी और सब देश अपनी-अपनी राह चल पड़े। बीच में एक ऐसा समय आया, जब बड़े युद्ध की कोई आशंका नहीं थी और महाशक्तियां स्वयं आगे बढ़कर गरीब व विकासशील देशों की मदद करती थीं। बीते दशक में कुछ आला वैश्विक नेताओं की वजह से मदद की वह जरूरी कड़ी टूट गई है और अब जरूरतमंद देशों को नई मजबूत कड़ी का इंतजार है।

लैटिन अमेरिकी देश हों या कैरेबियाई देश, इन सभी की पीड़ा कमोबेश भारत के समान है। अपने साझा हित के लिए इन देशों को एक मंच पर आना ही चाहिए।

यह इन देशों के बीच व्यापार व विकास सहयोग बढ़ाने का सही वक्त है। इस दिशा में भारत सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। आए दिन अपना रुख बदल रही महाशक्तियों से परे भारत को अपना नया बाजार और संसार चाहिए। अब तक भारत-सीईएलएसी व्यापार प्रतिवर्ष 50 अरब डॉलर से अधिक का हो चुका है और इसके बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कोरोना हो या कोई अन्य आपदा, अनेक मौके आए हैं, जब भारत इन देशों की निःस्वार्थ मदद करता रहा है। उम्मीद कीजिए, नए वर्ष में ग्लोबल साउथ के देशों के बीच समानता का सशक्त स्वाभाविक संगठन बनेगा और ये देश कंधे से कंधा मिलाकर अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ेंगे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 24 सितंबर, 1951

हिन्दू कोड विधेयक

भारतीय संसद ने आखिर हिन्दू कोड विधेयक की धाराओं पर विचार प्रारंभ कर दिया है। इस विधेयक ने देश में जितना उग्र विवाद उत्पन किया है, उतना शायद ही और किसी विधेयक ने किया होगा। यह विधेयक काफी समय से संसद के सामने है। उस पर जनमत जान लिया गया है। हिन्दू समाज के विद्वानों और विशिष्ट व्यक्तियों से परामर्श भी किया जा चुका है। सरकार ने इस बारे में काफी समझौते की भावना का परिचय दिया है। इस विधेयक को जल्दी से जल्दी स्वीकार करवाने की उसकी इच्छा के बावजूद वह एक अथवा दूसरे कारण से टलता गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विधेयक हिन्दू समाज की पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और इसीलिए उसका इतना विरोध हो रहा है। आम चुनाव सिर पर है और अधिकारारूढ़ दल को इस विधेयक के कारण चुनावों में कुछ घाटा भी उठाना पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने इस विधेयक को संसद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया, यह उनकी दृढ़ता और साहस का ही द्योतक हो सकता है।

मौजूदा संसद का यह आखिरी अधिवेशन है और सरकार आम चुनावों की निकटता को ध्यान में रखते हुए उसे अधिक लम्बे समय तक जारी नहीं रख सकती। उसके लिए उपलब्ध समय के भीतर पूरे विधेयक को इसी अधिवेशन में स्वीकृत करवा लेना असंभव था, अतः भारत सरकार के विधि मंत्री डा. अम्बेडकर ने इस आशय की घोषणा कर दी है कि हिन्दू कोड विधेयक का विवाह और तलाक से संबंध रखने वाला भाग ही एक अलग विधेयक के रूप में संसद के इस अधिवेशन में स्वीकृत करवाया जायेगा और उत्तराधिकार और साम्पत्तिक अधिकार संबंधी धारायें आगे के लिए रखी जायेंगी। मौजूदा परिस्थितियों में यही व्यावहारिक भी था। हिन्दू समाज रूढ़परस्त रहा है। वह पुरानी व्यवस्था में कोई भी हेर-फेर करने के लिए सहज ही प्रस्तुत नहीं होता। उसने प्रत्येक वस्तु को धार्मिक रूप देने की कोशिश की है। हिन्दू समाज शास्त्रकारों के वचनों को प्रमाण मानता है। समाज को अगर प्रगति करनी है, तो उसे गतिशील बनना चाहिए। उसे बदलते हुए जमाने के अनुकूल पुरानी रीति-नीति में परिवर्तन करना चाहिए। स्थिरता जड़ता की निशानी है और कोई भी समाज जो स्थिर होगा, वह जड़ता को प्राप्त हो जायेगा।

चुनाव आयोग की साख बचाई जाए

यहां स्कैन करें

ओपी रावत | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

चुनाव आयुक्तों के सच और झूठ का फैसला तो सांविधानिक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिन पर ईमानदारी से चिंतन आवश्यक है।

चुनाव आयोग के अंदर से जो खबर निकलकर सामने आई है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद चुनाव आयोग ने इसे जारी रखा, जिसके कारण देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर उंगली उठने लगी है।

चुनाव आयोग के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कानून कहता है कि इस सांविधानिक संस्था में फैसले सर्वसम्मति से होंगे या फिर बहुमत के आधार पर। खबरों की मानें, तो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने गुजरे 10 महीनों में कम से कम 14 बार (एक दिन तो चार बार) उन फैसलों व संदेशों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी के बिना लिए गए अथवा जारी किए गए थे। इसका सीधा अर्थ है कि एसआईआर से संबंधित प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि इसे पूरे देश में कराने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों निर्वाचन आयुक्तों (मुख्य चुनाव आयुक्त सहित) के कंधों पर है।

इस प्रकरण के सार्वजनिक होने के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को मीडिया में एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय सामने आना सामान्य बात है। यह फैसला लेने से पहले की प्रक्रिया है और आयोग ने अपने तमाम फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से ही लिए हैं। मीडिया में खास तरह के नोट्स ही दिखाए जा रहे। चूंकि, यह बयान आयोग ने जारी किया है, इसलिए माना जाना चाहिए कि इसे तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी होगी, जिसका अर्थ है कि उनमें अब एकराय है।

इन सबको देखते हुए दो तरह की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। एक, दोनों चुनाव आयुक्त सच बोल रहे होंगे, और दूसरी, मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों में सच्चाई होगी। सच और झूठ का फैसला तो सांविधानिक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं,

जिन पर ईमानदारी से चिंतन आवश्यक है।

पहला, अगर दोनों चुनाव आयुक्त एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट नहीं थे, तो क्या उन्होंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की? अगर उन्होंने की, तो क्या फैसला उनकी राय के खिलाफ हुआ? यह स्पष्ट है कि अगर दोनों चुनाव आयुक्त लिखित रूप से आपत्ति जताते या अपने रुख पर अड़े रहते, तो फैसला उनके हिसाब से ही होता, क्योंकि बहुमत उनके पास था। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त के रुख से लग रहा है कि चुनाव आयुक्तों को आपत्ति जरूर रही होगी, लेकिन उन्होंने यह काम मौखिक रूप में किया, जिनका निपटारा समय पर कर दिया गया था।

गौरतलब है, चुनाव आयोग के कामकाज में आपत्तियां मौखिक भी रहती हैं। मेरे खुद के कार्यकाल में ऐसे मौके आए, जब शेष दोनों चुनाव आयुक्त किसी सवाल पर अपनी राय देने में वक्त लगाया करते। एक बार तो सांविधानिक संकट पैदा होने की नौबत आ गई, तब मैंने उन्हें यह 'धमकी' दी कि अब भी उन्होंने अगर तत्परता नहीं दिखाई, तो मैं यह बात 'सार्वजनिक' कर दूंगा। यह सुनकर उन्होंने तुरंत अपनी राय बताई। इस तरह, हम बहुमत अथवा सर्वसम्मति से फैसले लिया करते थे। ऐसा आज भी होता होगा या किया जा सकता है। वैसे, इस सवाल को दरकिनार नहीं कर सकते कि अगर दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी आपत्तियां लिखित में दर्ज कीं, तो फिर उन पर क्या कार्रवाइयां हुईं?

अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने वाकई अपने तईं फैसले लिए, तब उनके खिलाफ सांविधानिक कदम उठाए जा सकते हैं। कानून यही कहता है कि किसी भी चुनाव आयुक्त, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी व्यक्तिगत तौर पर यह अधिकार नहीं है कि वह निजी फैसला लें। इनको अधिकार आयोग के रूप में मिलता है, अधिकारी के रूप में नहीं। इसलिए अगर दोनों चुनाव आयुक्त की बातों में सच्चाई है, तो उनको राष्ट्रपति के पास इसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर उनकी शिकायत सही पाई जाती है, तो सांविधानिक प्रक्रिया अपनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है या अदालत में उनके कामकाज को चुनौती दी जा सकती है। चुनाव आयोग की छवि से खेलने का हक किसी को नहीं है।

जाहिर है, इस पूरे मामले का पटाक्षेप आवश्यक है और जो भी दोषी साबित हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सीधे-सीधे सांविधानिक अधिकारों का हनन है। और तो और, इससे चुनाव आयोग की साख का धक्का लगा है, जबकि इस संस्था की निष्पक्षता की दुहाई पूरी दुनिया देती रही है। रही बात एसआईआर की, तो इसमें गड़बड़ियां हैं, जिनको दुरुस्त करने की मांग बार-बार की जाती है। यह पहला मौका है, जब चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने की जवाबदेही खुद मतदाताओं के सिर पर डाल दी है। इससे हो रही परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नामचीन हस्तियों को भी चुनाव आयोग की नोटिस जा रही है, क्योंकि उनके नए व पुराने डाटा में मिलान नहीं हो पा रहे।

यहां पश्चिम बंगाल का जिक्र लाजिमी है। वहां करीब 37 लाख मतदाताओं की अपील ट्रिब्यूनल के पास है, जिनमें से करीब एक लाख मामले अब तक निपटाए गए हैं। इनमें से लगभग 93,000 मतदाताओं को उसने वैध माना है, जिसका अर्थ है कि महज सात फीसदी वोटर ही 'फर्जी' हैं। जाहिर है, वैध होने के बावजूद हजारों मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया द्वारा वोट देने के सांविधानिक अधिकार से वंचित किया गया, जो एक बड़ा अपराध है। अगर एक लाख मतदाताओं में 93 हजार वैध हैं, तो 37 लाख अपील में यह आंकड़ा 34 लाख तक हो सकता है। कल्पना कीजिए, इससे हमारी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता कितनी संदिग्ध हो जाती है! एसआईआर में प्रक्रियागत चूक हो रही है, जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नेकनीयत होना आवश्यक है।

लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजाक समझने की इस मानसिकता को खत्म करना जरूरी है। सरकार को इस बाबत जरूरी कदम उठाने चाहिए। विपक्षी दलों की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन यह समय राजनीति करने से कहीं अधिक शुचिता बनाने का है। लोकतांत्रिक और सांविधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है और भारत इस शर्त को हमेशा पूरी करता रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दवाओं के बेहिसाब दाम पर लगाम लगाना जरूरी

यहां स्कैन करें

राजीव दासगुप्ता | प्रोफेसर (कम्यूनिटी हेल्थ), जेएनयू

दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लागत और कीमत में भारी अंतर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसके गहरे निहितार्थ हैं। कोर्ट ने कहा है कि 2,700 रुपये में खरीदी गई दवा को 27,000 रुपये में बेचने की इजाजत देना 'जबरिया वसूली' या 'दिन-दहाड़े डकैती' के बराबर है।

पाठकों की आसानी के लिए बता दूं कि किसी भी वस्तु की कीमत के दो पहलू होते हैं- 'पीटीआर' और 'एमआरपी'। पीटीआर वह कीमत है, जिस पर निर्माता कंपनी रिटेलर को कोई वस्तु या दवा उपलब्ध कराती है और ग्राहकों से जो अधिकतम कीमत रिटेलर वसूलता है, वह एमआरपी कहलाती है। हमारे यहां सन् 1997 में गठित 'नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी' (एनपीपीए) दवाओं की कीमत नियंत्रित करने वाली केंद्रीय नियामक संस्था है। 'ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर' (डीपीसीओ) के जरिये वह नियमित रूप से दवाओं और उनके अधिकतम खुदरा मूल्य की सूची जारी करती है। यह सुनिश्चित करना उसकी ही जिम्मेदारी है कि दवाएं लोगों को किफायती कीमत पर मिलें। पूर्व में एनपीपीए के पास दर्ज कराई गई कुछ शिकायतों की जांच से यह पता चला कि संबंधित कॉरपोरेट अस्पतालों ने एक खास उपकरण पर 1,737 प्रतिशत का मुनाफा कमाया था! 'नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स' (एनईएलएम) में शामिल 800 दवाओं के एक विश्लेषण में यह पाया गया था कि अस्पताल और डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाओं के 'कॉम्बिनेशन' लिखते थे, जो कीमत-नियंत्रण के दायरे से बाहर होती हैं। अध्ययन में देखा गया कि नई दवाओं और 'फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन' की वजह से दवा निर्माता कीमत-नियंत्रण के नियमों से बाहर रह जाते थे।

800 दवाओं के एक विश्लेषण में पाया गया था कि अस्पताल और डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाएं लिखते हैं, जो कीमत-नियंत्रण के दायरे से बाहर होती हैं।

डीपीसीओ 2013 के तहत गैर-सूचीबद्ध दवाओं की शुरुआती कीमत तय करने के बारे में कोई नियम नहीं है। डीपीसीओ सूची में शामिल लगभग 1,000 दवाओं के लिए अधिकतम कीमत तय करता है। गैर-सूचीबद्ध दवाएं सरकार की जरूरी दवाओं की सूची या सख्त कीमत-नियंत्रण वाली सूची में शामिल नहीं होती हैं। अलबत्ता, इनमें यह शर्त अवश्य होती है कि निर्माता बाद में उस कीमत को 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार, लगभग 82 फीसदी दवाएं गैर-सूचीबद्ध श्रेणी में आती हैं और बाजार में इनके लगभग 60,000 ब्रांड मौजूद हैं; कीमत तय करने का नियम लगभग 5,000 ब्रांड पर लागू होता है। हालांकि, आपातस्थिति में सरकार अपेक्षित अवधि तक किसी दवा का अधिकतम मूल्य तय कर सकती है।

बहरहाल, सवाल यह है कि खरीदारों और विक्रेताओं, दोनों के लिए 'सही कीमत' क्या है? 78 देशों के 1,500 मरीज समूहों के एक ग्लोबल सर्वे में सिर्फ नौ फीसदी लोगों ने माना था कि दवा कंपनियां 'सही कीमत वाली नीतियां' अपनाने में ईमानदार हैं। साल 2011 से आज तक यह धारणा 11 से 15 फीसदी के बीच ही रही है। निस्संदेह, दवाएं रोजमर्रा के सामान जैसी नहीं होतीं और इनकी कीमतें समाज की जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। कीमत से जुड़े मुद्दे विक्रेताओं और खरीदारों, दोनों पर लागू होते हैं और निष्पक्षता का सिद्धांत भी दोनों पर लागू होता है।

बेचने वालों में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) क्षेत्र के डेवलपर आते हैं। इनमें अकादमिक व सरकारी प्रयोगशालाएं, प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल करने वाली छोटी कंपनियां, नियामक मंजूरी के जरिये दवाएं बनाने वाली बड़ी कंपनियां और फॉर्मूलेशन में बदलाव करने वाली जेनेरिक कंपनियां शामिल हैं। थोक निर्माता दवा विकसित करने वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी, जबकि वितरक निर्माता से मरीज और मेडिकल संस्थानों तक दवाएं पहुंचाते हैं। इनके अलावा बड़े ऑनलाइन और अनौपचारिक सेक्टर भी हैं। खरीदारों में परिवार, बीमा कंपनियां, मंत्रालय और क्लिनिकल संस्थान शामिल हैं।

दवाओं के कीमत-निर्धारण में शोध एवं विकास, निर्माण, वितरण लागत और उचित मुनाफे को शामिल किया जाना चाहिए। दवा की कीमत खरीदार की क्रय-क्षमता के भीतर दवा की 'वैल्यू' के हिसाब से होनी चाहिए, तभी सभी पक्षों के साथ इंसाफ हो सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अध्ययन-मनन में जीवन

हमें बहुत चिंतन-मनन से जीवन जीना चाहिए। बताया जाता है कि समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया एक बार आइंस्टीन से मिलने गए, तो पूछा, जो अनुसंधान आपने किया, क्या उससे संतुष्ट हैं? तब आइंस्टीन की आंखें भर गईं, उन्होंने कहा, मुझे मालूम होता कि मेरे अनुसंधान से जो प्रयोग होगा, उससे लाखों लोगों की बलि हो जाएगी, प्राण पखेरू उड़ जाएंगे, तो मैं वैज्ञानिक बनना पसंद नहीं करता। ऐसे ही कपड़े का एक टुकड़ा पहनकर हाथ में छड़ी लेकर जीवनयापन कर लेता। मैं एक मनुष्य नहीं बना सकता, एक वृक्ष विकसित नहीं कर सकता, किंतु वहां कितने लोग राख हो गए।

अभिप्राय यह कि आदमी को यह चिंतन करना चाहिए कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, वह कहां जा रहा है या तो पढ़ें शास्त्रों को, सुने अच्छे लोगों को, सही मार्ग वालों को सुनें। ऐसा नहीं कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई, तो सही चलावें और बाद में छोड़ दें। कदम-कदम पर सावधानी आवश्यक है। तत्परता आवश्यक है। कई लोगों को देखकर लगता है कि देवपुरुष हैं, किंतु उनके ज्ञान की दुर्बलता ने, अभ्यास की दुर्बलता ने, उन्हें गलत आदमी बना दिया। वेदों में लिखा है कि स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

स्वाध्याय कहते हैं कल्याणकारी शास्त्रों को पढ़ने को। मोक्ष शास्त्र पढ़ें, अध्यात्म पढ़ें और पालन करें, मनन करें, उसके अर्थ को अपने मन से जोड़ें। निरंतरता की आवश्यकता है, भोजन निरंतर, कपड़ा निरंतर, तो श्रद्धा-प्रवचन निरंतर क्यों नहीं? जैसे हम निरंतर धन कमाना चाहते हैं, भोग कमाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हमें निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन की आवश्यकता है।

यह क्रम चलता रहना चाहिए। लोग जवानी में भी बिगड़ रहे हैं और बुढ़ापे में भी बिगड़ रहे हैं। प्रेरणा, विचार, भाव में मंदी आ गई। विचार प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए यह ध्यान में हमें रखना होगा कि जो प्रारंभिक काल में शिक्षा दी गई थी, जीवन की परम सार्थकता के लिए, वह बंद नहीं होनी है। बड़े होने पर भी उस शिक्षा को नवीन करते रहना है, अपने साथ जोड़े रखना है।

भोजन बंद नहीं, स्नान बंद नहीं, तो शिक्षा कैसे बंद हो जाए? श्रेष्ठ कर्म कभी बंद नहीं होने चाहिए। बंद हो जाएंगे, तो आदमी राक्षस ही हो जाएगा। आज इसीलिए समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते हैं, तो वेदों को नहीं पढ़ते। यदि पैसे हैं और यज्ञ में उपयोग नहीं हो रहा है, दान में नहीं हो रहा है, मानव सेवा में नहीं हो रहा है, तो वह कौन-सा पैसा? ऐसा पैसा नहीं चलेगा। पैसे का सदुपयोग हो। यदि हमारे शरीर में बल है और लोगों को सताने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो शरीर नहीं चलेगा। यह दुर्लभ मानव शरीर सदुपयोग के लिए मिला है और यह सत्कर्मों में ही खर्च होना चाहिए।

भोजन निरंतर, कपड़ा निरंतर, तो श्रद्धा-प्रवचन निरंतर क्यों नहीं? जैसे हम निरंतर धन व भोग कमाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हमें निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन की आवश्यकता है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

इमैनुएल मैक्रों | फ्रांसीसी राष्ट्रपति

अगर हम गाजा के मामले में निष्क्रिय बने रहते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? क्या हमें उस मंजर को देखते रहना होगा, जो हम सबको शर्मिंदा करता है?

सवालों के घेरे में महिला सुरक्षा का दावा

बिहार के जमुई की घटना हो या दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास की, इन मामलों से कानून-व्यवस्था, विशेष रूप से महिला सुरक्षा को लेकर सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये उस व्यापक प्रवृत्ति के उदाहरण मात्र हैं, जो पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार दिख रही है। सवाल यह है कि जब सरकारें बार-बार कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा करती हैं, तो ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, जिनमें अपराधी बेखौफ होकर सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का साहस जुटा लेते हैं।

इस समस्या के कई आयाम हैं, जिनको व्यापकता में समझना जरूरी है। पहला आयाम पुलिस प्रशासन की सक्रियता और उसकी प्रतिक्रिया से जुड़ा है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस तभी हरकत में आती है, जब कोई घटना सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है और जन-दबाव बनता है। यह इस बात का संकेत है कि निवारक पुलिसिंग, यानी अपराध होने से पहले उसे रोकने की व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक मानसिकता और अपराधियों के भीतर कानून के भय की कमी है। जब बार-बार यह देखा जाता है कि अपराध करने के बाद भी सजा मिलने की प्रक्रिया धीमी है या राजनीतिक संरक्षण के चलते कई मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही, तो समाज में यही संदेश जाता है कि कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। तीसरा आयाम राजनीतिक जवाबदेही का है। सरकारों की ओर से केवल घटना के बाद प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई होती है। राजनीतिक जवाबदेही का यह अभाव लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच के रिश्ते को कमजोर करता है। चौथा आयाम आंकड़ों और वास्तविकता के बीच के अंतर का है। सरकारी आंकड़े अक्सर अपराध दर में गिरावट का दावा करते हैं, पर जमीनी अनुभव इसके विपरीत होता है।

इस समस्या का एक और पहलू शिक्षा और कोचिंग जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए दूर-दराज के कोचिंग संस्थानों तक आते-जाते हैं, अक्सर सुनसान सड़कों से होकर। इन रास्तों पर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस गश्त जैसी सुविधाओं का अभाव उन्हें असुरक्षित बना देता है। साफ है, महिला सुरक्षा एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता की मांग करती है, जिसमें प्रशासनिक सुधार, त्वरित न्याय प्रक्रिया, सामाजिक जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक इच्छाशक्ति शामिल हैं। हमारी सरकारें इस पैमाने पर खरी नहीं उतर रहीं।

गंगा पाण्डेय, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
महिला सुरक्षा

पुलिस तत्परता की सराहना होनी चाहिए

महिला सुरक्षा आज केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों का प्रश्न बन चुकी है। पिछले एक दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने कानूनी सुधार, तकनीकी व्यवस्था, त्वरित पुलिस कार्रवाई और पीड़िता सहायता तंत्र को मजबूत करने के कई कदम उठाए हैं। चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, लेकिन यह कहना भी उचित होगा कि महिला सुरक्षा के लिए संस्थागत प्रयास पहले की तुलना में अधिक संगठित और सक्रिय हुए हैं।

सबसे जरूरी प्रयास तो कानूनी और संस्थागत पहल के रूप में किया गया। साल 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद बलात्कार, पीछा करना (स्टॉकिंग), एसिड अटैक और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए कठोर प्रावधान बनाए गए। इसके बाद निर्भया फंड के माध्यम से सेफ सिटी परियोजनाएं, सीसीटीवी नेटवर्क, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट और महिला हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया। गृह मंत्रालय की 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ने पुलिस, एंबुलेंस और अग्निशमन सेवाओं को एकीकृत कर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की। पुलिस की सक्रियता भी स्पष्ट रूप से बढ़ी है। अधिकांश राज्यों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो पेट्रोलिंग और महिला सुरक्षा को लेकर गश्त नियमित रूप से हो रही है। सार्वजनिक स्थानों, मेट्रो स्टेशन, स्कूल-कॉलेज और बाजारों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ने से माहौल पर असर पड़ा है। तकनीक ने भी पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बना दिया है। दिल्ली पुलिस का हिम्मत एप, उत्तर प्रदेश की 1090 महिला पावर लाइन व विभिन्न राज्यों के मोबाइल सुरक्षा एप महिलाओं को एक बटन दबाते ही पुलिस तक अपनी लोकेशन भेजने की सुविधा देते हैं।

हालांकि, केवल पुलिस की सक्रियता से यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की शिकायतें अब बड़ी संख्या में दर्ज होती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पहले की तुलना में महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं। इसलिए अपराध के आंकड़ों को केवल असुरक्षा नहीं, बल्कि बढ़ती कानूनी पहुंच के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। रही बात जमुई और दिल्ली जैसी घटनाओं की, तो समझना यह भी होगा कि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। पुलिस की सक्रियता घटना के बाद की उसकी प्रतिक्रिया से पता चलती है। इस मामले में दोनों राज्यों की पुलिस ने काम किया है।

स्वीकृति कुमारी, टिप्पणीकार

उत्पाद निर्माण उद्योग में ऐसे पांव जमाएं

मैन्युफैक्चरिंग में करियर केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण और अनुभव के साथ यही राह अपना कारोबार शुरू करने तक ले जा सकती है। निर्माण का क्षेत्र चुनने से पहले योग्यता, बाजार की मांग एवं निवेश क्षमता समझें। सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता द्वारा छोटे स्तर से शुरुआत करें। नौकरी से कारोबार तक कैसे बढ़ें, बता रही हैं तृप्ति मिश्रा

9.65 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में।

उद्यमिता-1

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार के साथ अपना कारोबार शुरू करने के भी मौके दे रहा है। कृषि के बाद इसे दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्यम माइक्रो, स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइज (एमएसएमई) के तहत आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, एमएसएमई का देश की जीडीपी में 31.1 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन में 35.4 फीसदी और निर्यात में 48.58 फीसदी योगदान है।

वर्तमान में उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के तहत 1 करोड़ 90 लाख से अधिक इकाइयां मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित दर्ज हैं। यह आंकड़ा छोटे कारोबारों के बढ़ते दायरे और मैन्युफैक्चरिंग में कारोबार की संभावनाओं को दिखाता है। वाराणसी के अमित पाल इसका उदाहरण हैं। उन्होंने जूट बैग यूनिट में दो साल काम कर मशीन, कच्चे माल, लागत और ऑर्डर का काम सीखा। अनुभव के बाद 5 लाख रुपये से अपनी यूनिट शुरू की। उनका सफर बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग में पहले काम सीखकर छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है।

मांग के हिसाब से काम

छोटे स्तर पर जूट बैग, पैकेजिंग, फुटवियर, डिस्पोजेबल कप-प्लेट, टेक्सटाइल, एलईडी बल्ब और पेपर बॉक्स जैसे उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। जूट बैग की 2025-26 में घरेलू खपत 12.05 लाख टन रही, जबकि सरकारी खरीद करीब 12,000 करोड़ रुपये की थी। ई-कॉमर्स और कारोबार बढ़ने से पैकेजिंग की मांग भी बढ़ रही है। कम पूंजी में अगरबत्ती या मसालों से संबंधित काम भी किया जा सकता है। वहीं, फूड प्रोसेसिंग का विकल्प भी अच्छा है। बी2बी बाजार के लिए पैकेजिंग और स्थानीय कच्चे माल से जुड़े काम देखे जा सकते हैं।

शुरुआती पूंजी का इंतजाम

यूनिट के आकार के हिसाब से पूंजी तय करें। पहले अपनी बचत से निवेश करें, फिर जरूरत होने पर बैंक या सरकारी योजना से मदद लें।

- **पीएमईजीपी** : 50 लाख रुपये तक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट पर 15-35 फीसदी तक सरकारी सहायता मिल सकती है। आवेदक को 5-10 फीसदी अपनी पूंजी लगानी होती है।
- **मुद्रा योजना** : छोटे कारोबार के लिए बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक कर्ज मिलता है। 10 लाख से अधिक के लिए पुराना कर्ज चुकाया होना जरूरी है।
- **सीजीटीएमएसई** : यह बैंक से लिए गए कर्ज पर गारंटी देता है। पात्र कारोबार के लिए गारंटी सीमा 10 करोड़ रुपये तक है।
- **आवेदन और पात्रता** : पीएमईजीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति पात्र है, जबकि 10 लाख रुपये से अधिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। जनसमर्थ और 'पीएसबी लोन इन 59 मिनट' भारत सरकार के डिजिटल पोर्टल हैं, जहां कारोबार के लिए कर्ज के विकल्प देखे और आवेदन किए जा सकते हैं।
- **कागजी तैयारी** : एमएसएमई के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कारोबार के स्तर के अनुसार फैक्ट्री लाइसेंस प्रमुख हैं।

साल-दर-साल बढ़ीं रोजगार संभावनाएं

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का दायरा बढ़ा है। 2006-07 की चौथी एमएसएमई जनगणना में 2.61 करोड़ उद्यम दर्ज थे। इनमें करीब 6 करोड़ लोग कार्यरत थे। वहीं 2010-11 में जिला उद्योग केंद्रों में कुल 21 लाख ईकाइयां आधिकारिक रूप से पंजीकृत थीं, जिनमें 93 लाख के लगभग लोगों को रोजगार मिला था। वहीं पंजीकृत और गैर पंजीकृत इकाइयों को मिलाकर उस वित्तीय वर्ष के लिए 4.29 करोड़ कामकाजी उद्यम और 9.65 करोड़ रोजगार का आंकड़ा पाने का अनुमान लगाया गया था। वर्तमान में उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म मिलाकर 9.65 करोड़ से अधिक कुल पंजीकरण हैं और इनसे 42.72 करोड़ लोगों के रोजगार जुड़े हैं। एक मैन्यूफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आमतौर पर 10 से 50 लोगों को रोजगार मिलता है।

रोजगार चाहने वालों के लिए

कारोबार शुरू नहीं करना चाहते, तो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी से शुरुआत की जा सकती है। मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, प्रोडक्शन ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन और पैकेजिंग जैसे पदों पर अवसर मिलते हैं। 10वीं के बाद आईटीआई या अन्य तकनीकी प्रशिक्षण से जरूरी कौशल हासिल किया जा सकता है। अनुभव बढ़ने पर बेहतर पद और वेतन के अवसर मिलते हैं। नौकरी तलाशने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पर रिक्तियां देखी जा सकती हैं। यह पोर्टल कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता व स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

विशेषज्ञ की राय

मैन्युफैक्चरिंग उद्यम में आने वाले युवा सिर्फ मौके देखकर फैसला न करें। पहले अपनी रुचि, तकनीकी जानकारी और सीखने की क्षमता देखें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर पूंजी, जगह, मशीन और मैनपावर की जरूरत समझें। तकनीकी जानकारी न हो तो किसी जानकार को साथ लें। आसपास की इकाइयों और बाजार को भी देखें। लाइसेंस -रजिस्ट्रेशन की जानकारी पहले लें। कर्ज लेने से पहले यह जरूर देखें कि बिक्री कम रहने पर भी किस्त और जरूरी खर्च निकल पाएंगे या नहीं। शुरुआत छोटी रखें। अनुभव लें। काम समझ आने पर निवेश बढ़ाएं।

-डॉ. योगेंद्र सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंगारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

शुरुआत से पहले तैयारी जरूरी

10वीं के बाद आईटीआई से तकनीकी प्रशिक्षण और आगे पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, फुटवियर टेक्नोलॉजी या अपने चुने क्षेत्र का डिप्लोमा किया जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित आईटीआई-पॉलिटेक्निक, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर और कौशल केंद्र प्रशिक्षण के विकल्प हैं। मशीन चलाने के साथ लागत, गुणवत्ता, पैकिंग, हिसाब-किताब और बिक्री की समझ जरूरी है। किसी चलती यूनिट में काम करने से कच्चे माल, ऑर्डर और रोजमर्रा के खर्च की व्यावहारिक जानकारी मिलती है।

- **जानकारी कहां से:** कोर्स, प्रशिक्षण व आवेदन की जानकारी स्किल इंडिया डिजिटल **(skillindiadigital.gov.in)** एवं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी सेंटर्स **(msmetc.gov.in)** पर देख सकते हैं।
- **बाजार देखकर काम चुनें :** मशीन खरीदने से पहले बाजार की जरूरत और प्रतिस्पर्धा को समझें। संभावित ग्राहकों की जरूरत, बजट और उत्पाद की गुणवत्ता से अपेक्षाएं समझें। यह भी देखें कि इलाके में पहले से कितनी इकाइयां काम कर रही हैं और उनके उत्पाद की कीमत क्या है। नमूना बनाकर ग्राहकों की प्रतिक्रिया लें और बाजार को परखें।
- **निवेश और कमाई का हिसाब :** काम तय करने के बाद मशीन, जगह, बिजली, कच्चे माल, मजदूरी, पैकिंग, ढुलाई और शुरुआती खर्च का अनुमान लगाएं। ऐसी जगह चुनें, जहां कच्चा माल लाना और तैयार माल भेजना आसान हो। सभी खर्च घटाकर असली मुनाफा देखें। शुरुआत आसपास के बाजार से करें। काम बढ़ने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और बी2बी माध्यमों से शहरों व नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाएं।

चुनौतियां समझें

औद्योगिक अध्ययनों और एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नए विनिर्माण व्यवसाय के शुरुआती 3 से 5 साल 'डेथ वैली' का दौर माने जाते हैं। इस चरण में वर्किंग कैपिटल और मार्केट की मांग संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जो इकाइयां यह चरण पार कर लेती हैं, उनकी स्थिरता एवं वृद्धि की संभावना बढ़ती है।

जॉब/करियर

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सर्विसेज इग्जामिनेशन 2027 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
कुल पद: 480
अंतिम तिथि: 06 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें-**upsc.gov.in**
- सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एमटीएस, साइंटिफिक असिस्टेंट समेत अन्य पद रिक्त हैं।
कुल पद: 110
अंतिम तिथि: 12 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **cpri.res.in**
- गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीआईएमएस), ग्रेटर नोएडा में स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने का अवसर है।
कुल पद: 100
अंतिम तिथि: 07 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन माध्यम से। संबंधित वेबसाइट **gims.ac.in** पर लॉगइन करें।
- मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कन्सल्टेंसी लिमिटेड में अकाउंटेंट, टेक्निशियन समेत अन्य पदों पर आवेदन का अवसर है।
कुल पद : 122
अंतिम तिथि: 11 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन माध्यम से। बैंक की वेबसाइट है - **mecl.co.in**
- जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। केवल महिला उम्मीदवार आवेदन ही पात्र होंगी।
कुल पद : 207
अंतिम तिथि: 05 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। इस वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर जाएं।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एवं पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।
कुल पद : 150
अंतिम तिथि: 05 अक्तूबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें **delhihighcourt.nic.in**
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद रिक्त हैं। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
कुल पद : 225
अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है - **uiic.co.in**
- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
कुल पद: 1871
अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें-**ssc.gov.in**

- नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर में साइंटिफिक/ टेक्निकल असिस्टेंट-ए के पद पर ऑनलाइन आवेदन का मौका है।
कुल पद : 376
अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है- **nic.gov.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

जेईई मेन और एडवांस्ड की तैयारी का तरीका समझें

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

■ आईआईटी जेईई मेन और एडवांस्ड क्या हैं? इनमें क्या अंतर है और अच्छे स्कोर के साथ इन्हें क्रैक करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए?
- अमित कुमार

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) भारत में स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रमुख प्रवेश परीक्षा है। इसके दो चरण हैं- जेईई मेन व जेईई एडवांस्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन के माध्यम से एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य संबद्ध संस्थानों के बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।

यह जेईई एडवांस्ड के लिए पात्रता परीक्षा भी है। जेईई मेन साल में दो सत्रों-जनवरी और अप्रैल में आयोजित होती है। विद्यार्थी किसी एक या दोनों सत्रों में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, 12वीं पास करने के बाद उम्मीदवार लगातार तीन वर्षों तक जेईई मेन दे सकते हैं और हर वर्ष अधिकतम दो सत्रों में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जेईई एडवांस्ड आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली प्रमुख कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। पात्रता शर्तें पूरी करने वाला उम्मीदवार लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार यह परीक्षा दे सकता है। जेईई मेन में एनटीए पर्सेंटाइल स्कोर जारी किया जाता है, जो परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों की तुलना में छात्र के प्रदर्शन को दर्शाता है।

वहीं, जेईई एडवांस्ड के परिणाम के आधार पर मुख्य रूप से आईआईटी में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया रैंक तय की जाती है। तैयारी की शुरुआत कक्षा 11वीं और 12वीं के भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित (पीसीएम) के पाठ्यक्रम की मजबूत समझ के साथ करनी चाहिए। खासकर रसायन विज्ञान के लिए एनसीईआरटी को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।

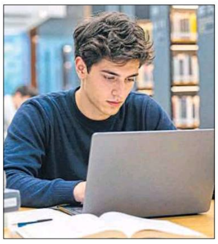

छात्रों को धीरे-धीरे कठिन होते सवालों का अभ्यास करना चाहिए, नियमित रूप से रिवीजन करना चाहिए और लगातार मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जेईई मेन की तैयारी में तेजी, सटीकता और समय प्रबंधन पर जोर देना चाहिए, जबकि जेईई एडवांस्ड के लिए विषयों की गहरी समझ, तार्किक सोच और एक से अधिक अवधारणाओं को जोड़कर सवाल हल करने की क्षमता जरूरी है।

■ पढ़ाई के दौरान अक्सर घबराहट रहती है कि मैं जो पढ़ रहा हूं, वह सही है या नहीं। इस कारण बार-बार टॉपिक बदल देता हूं और कोई भी टॉपिक पूरा नहीं हो पाता। इस समस्या से कैसे निकलूं?
- करन राजभर

यह पढ़ाई से जुड़ी एक आम समस्या है। इसकी मुख्य वजह है कि छात्र यह तय करने में ही ज्यादा समय लगा देते हैं कि क्या पढ़ना सही रहेगा। इस असमंजस में वे बार-बार विषय बदलते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी विषय पूरा नहीं कर पा रहे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर समय अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहना संभव नहीं है। एक बार पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री और आगे की रणनीति तय कर लें, तो बार-बार बेहतर विकल्प तलाशने के बजाय उसी पर भरोसा करें और लगातार उसी के अनुसार पढ़ाई करें।

पहले से तय करें कि क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। दूसरे विषय पर जाने से पहले एक छोटा और स्पष्ट लक्ष्य पूरा करें, जैसे एक अध्याय पूरा करना या तय संख्या में सवाल हल करना। अपने सवालों और शंकाओं को नोट करते जाएं और उनके समाधान के लिए एक तय समय निर्धारित करें।

बेहतर होगा कि दिन के अंत में एक बार ऐसा करें। 45-60 मिनट तक एकाग्र होकर पढ़ें और फिर थोड़ा ब्रेक लें। अंत में यह लिखें कि आपने वास्तव में क्या पूरा किया, न कि तैयारी को लेकर कितनी चिंता की। हर सप्ताह के अंत में एक छोटी परीक्षा दें और उसके नतीजे से तय करें कि किन विषयों में सुधार की जरूरत है। जैसे-जैसे पढ़ाई पूरी होगी और प्रगति दिखेगी, असमंजस कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

(www.sanjibacharya.com)

हिन्दुस्तान क्विज-24

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. हिन्दुस्तान के किस राज्य में गारो- खासी- जयंतिया पर्वत स्थित है?
2. भारतीय परंपरा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान किस पर्वत को मंथन के लिए देवताओं और असुरों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था?
3. रामायण में लंकापति रावण की महारानी का क्या नाम था?
4. हिन्दुस्तान की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है?
5. हिन्दुस्तान में आधुनिक समय की औद्योगिक स्तर पर काम करने वाली तांबे की सबसे पुरानी खदान कहां है?
6. रणजी ट्रॉफी का जो स्थान क्रिकेट में है हिन्दुस्तान में फुटबॉल में किस ट्रॉफी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्थान प्राप्त है?
7. किस मशहूर हिन्दुस्तानी की आत्मकथा का नाम 'गोल' है?
8. मोहन राकेश के मशहूर नाटक 'आषाढ़ का एक दिन' किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है?
9. हिन्दुस्तान के किस राज्य में ' खीर भवानी देवी' का मंदिर स्थापित है?
10. 'जिगरठंडा' नाम का पेय हिन्दुस्तान के किस राज्य में मिलता है ?

उत्तर : 1. मेघालय 2. मंदार पर्वत 3. मंदोदरी 4. विवेक एक्सप्रेस 5. घाटशिला (झारखंड) 6. संतोष ट्रॉफी 7. ध्यानचंद 8. कालिदास 9. जम्मू और कश्मीर 10. तमिलनाडु

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। संतान की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

वृष : आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी।

मिथुन : संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। किसी पारिवारिक कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। सेहत के प्रति सचेत रहें।

कन्या : आत्मविश्वास से तो परिपूर्ण रहेंगे, परंतु संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। बातचीत में संतुलित रहें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा पर जाना हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मकर : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में सुधार होगा।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा।

मीन : शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

24 सितंबर, गुरुवार, **शक संवत्** : 02, आश्विन (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग** : 08, आश्विन मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम** : 12, रबि-उल्सानी,1448 **विक्रमी संवत्** : भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि रात्रि 11.19 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 10.35 मिनट तक पश्चात शतभिषा नक्षत्र, धृति योग अपराह्न 03.55 मिनट तक पश्चात शूल योग, चन्द्रमा कुंभ राशि में (दिन रात)।

सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

स्वयं का नर्सरी स्कूल होने के बावजूद बच्चे बढ़ नहीं पा रहे, तो क्या करें-

- स्कूल पूर्व मुखी है, जिसका मुख्य द्वार पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर है। इस कारण सफलता नहीं मिल रही है। यह द्वार आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। स्कूल की पश्चिम दिशा भी नीची है। इस कारण बच्चे बढ़ नहीं पा रहे। इस दिशा का नीचा होना वास्तु अनुसार आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है।
- स्कूल का मुख्य द्वार बदलकर पूर्व दिशा की ओर कर दें। पश्चिम दिशा की नीची जगह को ऊंचा करवाएं। मुख्य द्वार पर एक गमले में हरसिंगार का पौधा लगाएं।
- कक्षा में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था ऐसी करें कि उनका मुख पूर्व की ओर हो।

वर्ग पहेली : 8461

■	1	■	2	■	3	4		5
6				7	■		■	
■		■	8					
9		10	■		■		■	
■	11			■	12		13	■
14	■		■	15	■	16		
17					18	■		■
	■		■	19				
20				■		■		■

बाएं से दाएं
3. बिना विलंब किए; तत्काल; तुरंत; फौरन; शीघ्र (4)
6. क्रीड़ा उपवन; इंद्र की वाटिका (5)
8. आभा; कांति; तड़क भड़क; दीप्ति; शान (3,3)
9. एक ही तरह की सौ चीजों का संग्रह; सैकड़ा (3)
11. पांसे फेंक कर शुभ अशुभ फल जानने की विद्या (3)
12. घातक; नाशक; निवारक; प्रभाव मंदक; प्राणघाती; मर्मांतक; हिंस्र (3)
16. नामवाला; नाम से प्रसिद्ध (3)
17. ठसक; नाज नखरा; बनाव सिंगार; वेशविन्यास और हावभाव (3,3)
19. स्वार्थ सिद्ध करना; काम पूरा करना (2,3)
20. तरल धातु; सबसे भारी तरल; पारद; पारा (4)

ऊपर से नीचे
1. उत्तरकाल में; उसके उपरांत; बाद में (5)
2. छाल; आवरण; जिरह बख्तर (3)
4. झगड़ा करना; दावा करना; बहस करना; मुकदमा चलाना (3,3)
5. भटकना; पथभ्रष्ट होना; चूकना; आपे में न रहना (4)
7. औषर, करकच; खारी; लवण (3)
10. आमादा होना; तैयार होना; दृढ़ निश्चय करना; सन्नद्ध होना (3,3)
13. विष्णु (5)
14. नाचमहल; नृत्यशाला; नृत्यालय (4)
15. डर; भय; चिंता; दरवाजे की सिटकनी (3)
18. रमा; लक्ष्मी (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8460

■	1 प	■	2 स	3 ह	ले	4 ख	क	■
5 ता	रि	का	■	म	■	र	■	6 त
■	चा	■	7 पू	रा	न	प	ड़	ना
8 सा	रि	9 का	■	ज	■	त	■	व
■	10 का	म	ना	■	11 से	वा	12 ले	■
13 प	■	क	■	14 का	■	15 रे	ह	ना
16 सं	हा	र	क	र	ना	■	ल	■
द	■	वा	■	ग	■	17 मु	हा	ना
■	18 म	ना	क	र	ना	■	ना	■

सुडोकू : 8415

*कठिन

	3	6			2			7
		7					5	
	5					3		1
			6		9	7		
4								8
		9	8		3			
7		5					1	
	2					4		
8			3			5	6	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8414

7	4	9	8	6	1	2	5	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
2	6	3	4	9	5	8	7	1
4	9	5	1	3	6	7	8	2
8	7	2	9	5	4	3	1	6
1	3	6	2	7	8	4	9	5
3	5	7	6	4	9	1	2	8
9	1	4	5	8	2	6	3	7
6	2	8	3	1	7	5	4	9

संपादकीय

'अ'धर्माचे विसर्जन व्हावे

कानठळ्या बसतील असे शेकडो ढोल रस्त्यांवर बडविले, कर्णकर्कश आवाजात थिल्लर गाणी वाजवून हिडीस नाच केला, डीजे, लेझर बीमचा वापर केला, फटाक्यांचा दणदणाट केला की, कोणत्या धर्माचे पालन होते आणि कोणता देव प्रसन्न होतो? कोणते सुख गवसते? कोणत्याही धर्मग्रंथांमध्ये याचा उल्लेख नाही. मात्र, हे सर्व बंद करायला गेले की, लगेच धार्मिक भावना दुखावल्याची आवई उठविली जाते. या सर्व गोष्टींवर कायदे आणि नियमांनी बंदी असूनही हा धांगडधिंगा राज्यभरातच नव्हे, तर देशातही कमी-अधिक प्रमाणात सर्रास सुरू आहे. तो कमी होण्यापेक्षा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. शिक्षण, विज्ञान, प्रगती, विकास यामुळे समाज प्रगल्भ, विकसित होतो, या दाव्यात फारसे तथ्य नाही अशीच एकंदरीत वागणूक दिसते. मुंबई उच्च न्यायालयाने याच अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित करत उत्सवी धांगडधिंगा हताशपणे पाहत असलेल्या सरकारचे कान उपटले आहेत. समाजात वावरताना इतर कोणालाही त्रास होऊ नये, महिला, वृद्ध, लहान मुलांसह दुर्बलांची काळजी घ्यावी, ही सर्वच धर्मांची शिकवण आहे आणि हा माणुसकीचा धर्मही आहे. मात्र, वाद्यांचा दणदणाट आणि कानठळ्या बसविणारे फटाके वाजविल्यावर यांना त्रास होतो आणि सर्वांनाच रक्तदाब, कानाचे व अन्य आजार संभवतात. ढोल, डीजे, वाद्यांचा व फटाक्यांचा दणदणाट यावर कायद्याने बंदी आहे आणि पोलिसही प्रत्येक उत्सवाआधी तसे परिपत्रक जारी करतात. मात्र, त्याची काडीमात्रही अंमलबजावणी सार्वजनिक मंडळांचे कार्यकर्ते करीत नाहीत आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनाही त्यात अजिबात रस नसतो. सरकारही केवळ कागदावर राहणारे कायदे करून सुखासीन असते. केंद्र सरकारकडून ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे व नियम १९९९-२००० मध्ये करण्यात आले, सर्वोच्च न्यायालयाची अनेक निकालपत्रेही आली आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारांना देण्यात आले. रात्री १० ते सकाळी ६ कोणताही मोठा आवाजच नव्हे, तर गाड्यांचे हॉर्न वाजविण्यासही मनाई आहे. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना केवळ दंडच नव्हे, तर तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्रातच काय, देशातही ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना तुरुंगवास झाल्याचे ऐकिवात नाही. मग कागदावर राहणारे कायदे करून सरकार काय साधते? मुंबई उच्च न्यायालयानेही स्वतःहून दाखल (स्यूओमोटो) करून घेतलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत गेल्या दोन दिवसांत सरकारपुढे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक नियम व कायद्यांचे पालन सरकारकडून का होत नाही, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर राज्य सरकार देऊ शकलेले नाही. बहुमताला खुश करण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे जे कायद्याचे पालन करण्याचा आग्रह धरतात, त्यांना एकटे पाडून हिंदूंच्या उत्सवावर निर्बंध येऊ देणार नाही, अशा घोषणा भाजप, सत्ताधारी नेत्यांकडून आणि तथाकथित हिंदुत्ववादी नेत्यांकडून केल्या जातात. मशिदींवरचे भोंगे आधी बंद करा, अशी मागणी केली जाते आणि धार्मिक वादातून कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी सरकारही हताशपणे हा कायदेभंग पाहत राहते. जर कायदे व नियमांचे पालन करायचेच नसेल, तर प्रचंड बहुमताच्या सरकारने ते बदलून किंवा रद्दच करून टाकावेत. फटाके, कर्णकर्कश ढोल, डीजे हे कायदेसंमतच करून टाकावे. म्हणजे निदान पुण्यातील विद्यानंद बापट, भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यासारख्यांना आवाज उठविताच येणार नाही. केवळ नागपूरमध्ये पोलिस आयुक्त ध्वनिप्रदूषण रोखण्याचा प्रयत्न करतात आणि मुंबई-पुणे व अन्य शहरांमधील पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हातावर हात ठेवून शांत बसतात. कायदा हा निवडक क्षेत्रापुरताच आहे का? धांगडधिंगा, ध्वनिप्रदूषण न करता पंढरपूरची वारी लाखो वारकरी शांतपणे पार पाडतात, मग हे गणेशोत्सव व अन्य धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये का जमू नये, असे प्रश्न न्यायालयास पडले आहेत. अमेरिका, जपान, ब्रिटनसारख्या अन्य देशांमध्ये कायद्यांचे किती चांगल्या प्रकारे पालन होते, याच्या गप्पा करणारी मंडळी येथे मात्र कायदे धुडकावून लावत असतात. त्यामुळे धर्मभावना जपताना नागरिक म्हणून असलेला नागरी धर्म आणि माणुसकीच्या धर्माचे पालन सर्वांकडून केले जावे आणि राज्यघटनेच्या, कायद्याच्या पालनाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेल्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव होऊन 'अ' धर्माचे विसर्जन व्हावे, अशी बुद्धिदात्या श्री गणेशाकडे प्रार्थना.

यंत्राला 'माणूस' करण्याच्या नादात माणसाचेच यंत्र!

मानवाच्या वैयक्तिक अवकाशात तंत्रज्ञानाने किती ढवळाढवळ करावी आणि माणसाच्या मताचं महत्त्व किती असावं, याचा तोल कसा राखणार?

डॉ. पराग काळकर
प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

तंत्रज्ञानाने मानवी संस्कृतीच्या विकासात नेहमीच मदत केली आहे आणि भविष्यातही करत राहील. मानवी इतिहास पाहिला तर चाकाच्या शोधापासून ते संगणकाच्या युगापर्यंत तंत्रज्ञानाने माणसाचे जीवन सुकर आणि प्रगतिपथावर नेण्याचे काम केले आहे. परंतु, आजच्या घडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग आणि डिजिटल जगताच्या या अफाट गदारोळात माणसाच्या अनेक मूलभूत आणि समृद्ध सवयी हळूहळू लोप पावत आहेत. कधीकाळी तासन्तास पुस्तकाच्या पानांमध्ये रमणारा माणूस, स्वतःच्या हाताने कागदावर विचार उतरवणारा माणूस आणि स्वतंत्रपणे विचार करणारा माणूस आज या आभासी जगात कुठेतरी हरवून गेला आहे.

जेव्हा आपण 'मशीन लर्निंग' असा शब्दप्रयोग वापरतो, तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की, यंत्र माणसाच्या सवयी, आवडीनिवडी, वागण्याच्या पद्धती आणि निर्णयक्षमता शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगभरात वेगवेगळ्या क्लिष्ट अल्गोरिदमच्या माध्यमातून या सर्व सवयी रोबोट आणि संगणकीय यंत्रांपर्यंत कशा आणता येतील आणि माणसाचं काम अधिक अचूकतेने यंत्राकडून कसं करून घेता येईल, यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च करून प्रचंड संशोधन सुरू आहे. परंतु, हे सर्व होत असताना माणूस स्वतः मात्र हळूहळू विचारहीन आणि यंत्रवत होत चालला आहे. आणि दुसरीकडे माणसाच्या भावना आणि त्यातील सूक्ष्म बदलसुद्धा आज डेटाच्या रूपात गोळा करून अल्गोरिदममध्ये रूपांतरित केले जात आहेत. ही तजवीज मशीन लर्निंगसाठी चालली आहे.

आपल्या रोजच्या खरेदीच्या पद्धती आणि व्यवहार पूर्णपणे बदलले आहेत. पूर्वी बाजारपेठेत किंवा दुकानात स्वतः जाऊन वस्तू निरखून घेणारा माणूस आता डिजिटल व्यासपीठांवर स्थिरावला. तिथूनही पुढे जाऊन आता अवघ्या १० मिनिटांत वस्तू दारात आणून देणाऱ्या क्विक-डिलिव्हरी ॲप्सच्या आहारी आपण गेलो आहोत. या सगळ्या सोयीस्कर व्यवस्थेत एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, माझं आयुष्य खरोखर मी माझ्या इच्छेने जगतोय की, माझं आयुष्य या अल्गोरिदम भोवती नाचत आहे?

आपले जिओ-लोकेशन आणि आपण भूतकाळात डिजिटल माध्यमांवर केलेले सर्व व्यवहार या सर्व गोष्टींच्या आधारे आपल्यावर सतत एक अदृश्य पाळत ठेवली जात आहे. आपल्या नकळत आपले एक डिजिटल मॉडेल तयार केले जात असून,

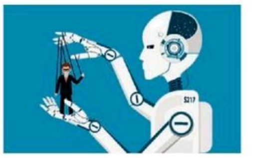

आपल्याला काय आवडतं यापेक्षा आपल्याला काय आवडायला हवं, याचा अंमल आपल्या हातात ठेवून आपल्यासाठी सर्वकाही आता हे तंत्रज्ञान ठरवू लागलं आहे. आपल्यावर नकळत कसे नियंत्रण मिळवले जात आहे, याचं एक रंजक पण डोळे उघडणारं उदाहरण पाहण्यासारखं आहे. मोबाइलचे लोकेशन ऑन ठेवा किंवा ऑफ, ही यंत्रणा आपल्या दैनंदिन दिनक्रमावर आणि मानसिक स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असते. समजा, संध्याकाळी शहरात पाऊस पडत आहे आणि तुम्ही ऑफिसमधून घराकडे निघाला आहात. गेल्या दोन-तीन पावसाळी संध्याकाळी तुम्ही महाराष्ट्रातील नेहमीच्या ५ ते ६ या वेळेत एखाद्या दुकानातून गरमागरम वडापाव किंवा भजी खरेदी केली होती आणि त्याचा ऑनलाइन फीडबॅक खूप चांगला दिला होता.

ही सर्व माहिती यंत्राकडे आधीपासून नोंदवलेली असते. तुम्ही गाडीतून घराच्या रस्त्याला लागताच मोबाइलवर अचानक नोटिफिकेशन येतं - आजही बाहेर छान पाऊस पडतोय! गेल्यावेळी मागवलेला अमुक अमुक दुकानातील वडापाव आज पुन्हा मागवणार का?

पहिल्या नजरेत ही गोष्ट अत्यंत नाविन्यपूर्ण, इनोव्हेटिव्ह, सोयीस्कर आणि आपली काळजी घेणारी वाटू शकते. परंतु, सखोल विचार केला तर लक्षात येईल की, आपली आवड, आपली वेळ आणि वातावरणाचा फायदा घेऊन आपल्या विचारांवर आणि कृतीवर थेट नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. या सगळ्या डिजिटल चक्रव्यूहात माणसाची स्वतःची समृद्ध भाषा आणि सर्जनशीलता हरवत चालली आहे. अवांतर वाचन करून, कानावर पडलेले नवे शब्द पचवून, स्वतःच्या बुद्धीला ताण देऊन नवीन शब्द किंवा वाक्प्रचार तयार करणं आपण पूर्णपणे विसरून जाऊ लागलो आहोत. तंत्रज्ञानाने मानवी संस्कृतीच्या विकासात नेहमीच मदत केली आहे. परंतु, माझ्याविषयीची कोणती आणि किती माहिती या डिजिटल विश्वाकडे असावी, याला काही मर्यादा असणार की नाही? मानवी आयुष्यात आणि त्याच्या वैयक्तिक अवकाशात या तंत्रज्ञानाने किती ढवळाढवळ करावी आणि माणसाच्या स्वतःच्या स्वतंत्र मताचं महत्त्व किती आणि त्याला कोणतं स्थान असावं, याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आता नक्कीच आली आहे.

तंत्रज्ञान हे माणसाच्या सेवेसाठी आणि प्रगतीसाठी असावं, माणसाला आपला गुलाम बनवण्यासाठी नाही; अन्यथा या आभासी सोयींच्या मोहात माणूस आपली स्वायत्तता, विचार स्वातंत्र्य आणि मूळ मानवी अस्तित्व पूर्णपणे गमावून बसेल.

अन्वयार्थ

जपानमध्ये क्रिकेट प्रेम अचानक का वाढू लागले आहे?

जपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघाच्या नाकी दम आणणाऱ्या जपानी क्रिकेट संघाच्या प्रवासाची गोष्ट मोठी रंजक आहे. त्याबद्दल...

मेघना ढोके
संपादक, लोकमत सखी डॉट कॉम

२५ जून १८६३ आणि २२ सप्टेंबर २०२६. किती मोठा काळ लोटला आणि जग किती बदललं! जपानमध्ये मात्र या दोन तारखा एका वेगळ्या खेळाची गोष्ट सांगतात. ब्रिटिश लोक १८६३ मध्येच बॅट-बॉल घेऊन जपानमध्ये पोहोचले होते. खलाशी आणि तटावरचे लोक यांच्यात एक मॅच होणार होती. त्यावर सामुराई हल्ल्याची भीतीही होती; पण तो सामना झाला, त्याविषयी अत्यंत रंजक गोष्ट ब्रिटिश इतिहासकार माइक गालब्रेथ यांनी २०१२ साली 'जपान टाइम्स'मध्ये लिहिली होती.

त्यानंतर उजाडले २०२६. जपानच्या मातीवर टोक्योपासून १०० किलोमीटर दूर सानो शहरात जपानी पुरुष संघ भारताबरोबर क्रिकेटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. विशेष म्हणजे सामना अत्यंत चुरशीचा झाला, मातब्बर भारतीय संघाला जपानी संघाने जवळजवळ मात दिलीच होती. सामना भारतीय संघाने जिंकला; पण जपानी क्रिकेटची एक नवी गोष्ट सुरू झाली.

सन १८६३ मध्ये आलेले ब्रिटिश क्रिकेट जपानमध्ये हरले आणि अमेरिकन बेसबॉलने जपानी मातीत आपले स्थान पक्के केले. जपानमध्ये बेसबॉलला मोठी लोकप्रियता आहे. बॅट-बॉल असलेला दुसरा तसाच खेळ तिथे रुजेल का, अशी शंका अनेकांना होती, आजही आहेच. मात्र, जपानी तरुण-तरुणींना क्रिकेट नावाच्या या नव्या खेळाचे आकर्षण वाटू लागले आहे. २०२८ चे ऑलिम्पिक डोळ्यांसमोर ठेवून तयारीही सुरू झाली आहे. विराट कोहली नावाचा एक भारतीय खेळाडू जपानी तारुण्यालाही ओळखीचा वाटतो.

महत्त्वाचे म्हणजे जपान क्रिकेट असोसिएशनने खेळात लिंगभेद केला नाही. पैसा आणि सुविधा या बाबतींत हात आखडता घेतला नाही. आयसीसी नियमानुसार महिला आणि पुरुष दोन्ही क्रिकेट संघ मैदानात उतरले. जपानी महिला संघात खेळणारी माई यानागिदा ही उत्तम बेसबॉल खेळाडू आहे. वयाच्या ३३ व्या वर्षी तिने ठरवले, आता क्रिकेट खेळू, तर तिला कोणी विरोध केला नाही की वेड्यात काढले नाही. महिला संघानेही उत्तम तयारी केली. जपानी मातीवर एकीकडे भारतीय महिला संघाने उत्तम खेळ करत आशियाई स्पर्धेत देशासाठी पहिले सुवर्ण जिंकले तेव्हा जपानी महिला क्रिकेट त्या सुवर्णपदकाच्या

जपानी प्रेक्षकांना क्रिकेट समजावे म्हणून अशी जपानी भाषेतील कार्डस देण्यात आली होती. साक्षात सचिन तेंडुलकरनेही त्याचे कौतुक केले.

दिशेने जाण्याचे स्वप्न पाहू लागलेले होतेच.

तीच गोष्ट पुरुष क्रिकेटची. त्यात एक स्थलांतरित स्वप्नांची गोष्ट आहे. पुरुष संघात खेळणारे अनेकजण हे सेकंड जनरेशन जपानी खेळाडू आहेत. म्हणजे कुणाचे वाडवडील भारतीय उपखंडातील आहेत, तर कुणाचे ऑस्ट्रेलियन आणि ब्रिटिश. मुले जपानी नागरिक खरी; पण पालकांच्या मनातील क्रिकेटप्रेम आपसूक मुलांच्या रक्तात उतरले. जपानी ऑफस्पिनर इब्राहिम ताकाराशीचे वडील पाकिस्तानी. एकेकाळी ते स्वतः क्रिकेट खेळत. या देशात आपल्या मुलाला क्रिकेट मिळणार नाही, याची त्यांना खंत होती; पण हळूहळू त्यांनी मुलाला क्रिकेट शिकवले. त्याच काळात त्या वयाची अनेक मुले क्रिकेटकडे वळली. सानो हे जपानी क्रिकेटचे केंद्र बनू लागले आणि म्हणता-म्हणता आयसीसी जपानपर्यंत पोहोचली.

क्रिकेटची बाजारपेठ वाढवायची म्हणून आयसीसी आता पूर्वेकडील देशांसह आखाती देश, अमेरिका, कॅनडा आणि अगदी दक्षिण अमेरिकी देशांतही क्रिकेट प्रोत्साहन धोरण आखत आहे आणि दुसरीकडे जगभरात स्थलांतरित झालेले अनेकजण, आपल्या पुढच्या पिढ्यांना क्रिकेट शिकवू लागले आहेत. त्यात मुलगा-मुलगी भेद दिसत नाही. जपानसारखा विकसित देश जर क्रिकेटशी जोडला गेला तर ते क्रिकेटसाठी फार महत्त्वाचे आहे.

एक प्रश्न असाही विचारला जातो की, एवढे काय जपानमध्ये क्रिकेट पोहोचण्याचे कौतुक, अशी किती लोकसंख्या आहे त्या देशाची? पण ब्रिटिश लोकसंख्या किती आहे? तरी क्रिकेट जगभर पोहोचले ना? खेळाची बाजारपेठ संख्यात्मक ताकदीवर चालते; पण खेळाचा आनंद वेगळा आणि त्यामुळे मूळ धरणारी स्वप्ने वेगळी! नव्या जागतिक सत्ता समीकरणात रुजू लागलेली सॉफ्ट पॉवर आणि स्पोर्ट डिप्लोमसीची गणितेही वेगळी आहेत.

जपानी क्रिकेटची ही गोष्ट अशी नव्या स्वप्नांसह देशातील नव्या उत्सुकतेचीही गोष्ट आहे. म्हणून तर जपान क्रिकेट असोसिएशनने सामना पाहायला आलेल्या प्रेक्षकांना स्पोर्ट कार्डे दिली, त्यांवर खेळाचे नियम जपानी भाषेत लिहिलेले होते. जपानी प्रेक्षक स्थानिक माध्यमांत सांगत आहेत की, आम्हांला बेसबॉल कळतो; त्यामुळे हा खेळही कळेल, त्यातला थरारही लवकरच समजेल.. क्रिकेट मने जोडते असे म्हणतात. त्याचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे, म्हणून ही नोंद महत्त्वाची...!

meghana.dhoke@lokmat.com

जगभर

एआयची एक चूक, अन् जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर!

सध्या सगळीकडे एआयचा बोलबाला आहे. सर्वसामान्य माणसांपासून ते उद्योजक, कंपन्यांपर्यंत सारेच जण आता एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करू लागले आहेत. एआयमुळे अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत, अपरिहार्यता म्हणून एआयविरुद्धची ओरडही हळूहळू कमी होते आहे, पण तरीही एआयच्या धोक्यांकडे अजूनही कानाडोळा करता येत नाही. मानवी डोळ्यांची सूक्ष्म आणि चाणाक्ष नजर एआयवर कायम ठेवावीच लागणार आहे, याचा अतिशय मोठा धडाही नुकताच मिळाला आहे.

एआयच्या एका छोट्याशा चुकीमुळे दोन बलाढ्य देश नुकतेच युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले होते आणि लक्षावधी लोकांचे प्राण संकटात आले होते, हे लक्षात घेता एआयचा वापर किती जबाबदारीने करावा लागेल, याची गरजही अधोरेखित झाली आहे.

काय आहे ही कहाणी? एआयनं अशी कोणती चूक केली होती, ज्यामुळे केवळ दोन देशच नव्हे, तर संपूर्ण जगच पुन्हा एकदा जागतिक महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन उभं राहिलं असतं?..

सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातून विस्तवही जात नाही, हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. इराणमधील युद्धाच्या काळात अमेरिकी लष्कराला एक गुप्तचर अहवाल मिळाला. या अहवालात मध्यपूर्वेत असलेल्या चीनच्या एका जहाजातून अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित उपकरणं नेली जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

या माहितीवर विश्वास ठेवून अमेरिकी लष्करानं त्या चिनी जहाजाला रोखण्याची आणि त्यावर ताबा मिळवण्याची तयारी सुरू केली. यासंदर्भात अतिशय गुप्तता पाळण्यात आली होती. सर्व तयारी झाली होती. कोणत्याही क्षणी सशस्त्र सैनिक जहाजावर चढण्यासाठी सज्ज होते. त्याचवेळी अमेरिकी लष्कराची विमानंही आकाशात पाठवण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होण्याच्या काही क्षण

आधी या गुप्तचर अहवालातील गंभीर चूक लक्षात आली. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, कारवाई करण्यापूर्वी अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी या गुप्तचर अहवालाची पुन्हा तपासणी केली. त्यावेळी अहवाल तयार करताना एआय चॅटबॉटची मदत घेण्यात आल्याचं समोर आलं. या चॅटबॉटनं जहाजातील सामानाची चुकीची ओळख पटवून त्यावर आधारित निष्कर्ष दिला होता.

अमेरिकी लष्कराच्या स्पेशल ऑपरेशन्स कमांडमधील एका अधिकाऱ्यानं चिनी जहाजावरील सामानाची माहिती एआय चॅटबॉटमध्ये टाकली होती. चॅटबॉटनं वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मिळालेल्या माहितीची सांगड घालत चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि जहाजात अण्वस्त्रं तयार करण्याशी संबंधित उपकरणं असल्याचं त्यानं सांगितलं. एआयकडून मिळालेली ही माहिती नंतर एका गुप्तचर अहवालात समाविष्ट करण्यात आली. हा अहवाल अमेरिकी लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला. त्याच माहितीच्या आधारे चिनी जहाजाविरुद्ध लष्करी कारवाईची तयारी सुरू करण्यात आली.

या प्रकरणाशी संबंधित एका अमेरिकी अधिकाऱ्यानं सांगितलं, हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा होता. एआयनं दिलेल्या या चुकीच्या माहितीमुळे युद्ध जवळपास सुरू होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. दुसऱ्या एका अमेरिकी अधिकाऱ्यानं सांगितलं, युद्धासारख्या अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीत एआयनं दिलेल्या माहितीची मानवी पातळीवर तपासणी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. एआयमुळे निर्णय घेण्याचा वेग तर वाढू शकतो, पण एआयनं दिलेली चुकीची माहिती वेळेत ओळखली गेली नाही, दुरुस्त केली गेली नाही, तर महायुद्धासारखे गंभीर परिणामही त्यामुळे उद्भवू शकतात...

जनमन

कामे कागदावर नाही, प्रत्यक्षात गरजेचे

दर्जेदार रस्ते हे देशाच्या विकासाला गती तर देतातच, शिवाय जनतेचा प्रवास सुरक्षित करतात, कारण सलग आणि सुस्थितीतील रस्त्यामुळे चालकाला कोणतीही तांत्रिक कसरत करावी लागत नाही. परिणामी अपघातांना पायबंद बसतो आणि मृतांची संख्या घटते. पण खड्डे, खाचखळगे असलेल्या रस्त्यावर प्रवास करताना खड्डे चुकविताना अथवा खड्ड्याच्या दणक्याने वाहन खाली आपटून वाहनधारकांचे मृत्यू होतात. अलीकडे खराब रस्त्यांमुळे अपघातांत वाढ होऊन बरेच पादचारी, वाहनचालक आणि प्रवासी यांचे मृत्यू झाले आहेत, हे दुर्दैवी आहे. जनतेने नियमित कर भरावा आणि त्या बदल्यात शासनाने नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, तसेच त्यांची दुरुस्तीही पाहावी, असे संकेत आहेत. पण प्रशासनाच्या गलथान कारभार व निष्काळजीपणामुळे बऱ्याच वेळेला नवीन रस्ते बनविणे तर दूरच, पण खराब रस्त्यांचे डागडुजीकरणही केले जात नाही. परिणामी अशा दुर्दैवी घटना घडतात आणि एखाद्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. रस्त्यांची नियमित पाहणी, वेळेवर डागडुजी आणि निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट होते आणि लहान-मोठे खड्डे पाण्याखाली गेल्याने वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. रात्रीच्या वेळी अपुरा प्रकाश असल्यास हा धोका अधिकच वाढतो. त्यामुळे रस्त्यांची कामे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष दर्जेदार आणि टिकाऊ होणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या जीविताची किंमत कोणत्याही विकासकामापेक्षा मोठी आहे.

- **किरण तांबे**, तळंदगे, कोल्हापूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सेतू

भूक लागलीय?- रस्त्यावरचं फ्रीज उघडा, हवा तो पदार्थ फुकट खा!

पोलंडमधल्या अनेक शहरांमध्ये रस्त्यांवर कम्युनिटी फ्रीज ठेवलेले असतात. ज्यांना गरज आहे ते लोक या फ्रीजमधून हे पदार्थ विनामूल्य घेऊन जातात.

अवनी दाते
१२ वर्षांपासून पोलंडमध्ये वास्तव्य

काल माझ्या मुलाने सांगितलेल्या एका गोष्टीचं मला खूप कौतुक वाटलं. तो म्हणाला, "आई, सुट्टी सुरू होण्याआधी आम्ही आमच्या 'नैतिकता' विषयाच्या सरांबरोबर स्थानिक बाजारात फील्ड ट्रिपला जाणार आहोत.."

मी उत्सुकतेने विचारलं, "का बरं? काही खरेदी करायची आहे का?"

त्यावर मुलगा म्हणाला, "नाही गं! बाजारात ज्या फळं, भाज्या आणि ब्रेडची एक्सपायरी डेट जवळ आलेली असते ते आम्ही गोळा करून आणणार. त्याची सँडविचेस करून शाळेजवळच्या कम्युनिटी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणार. म्हणजे कुणालाही जेवण मिळणार नसेल तर त्यांना त्या रेफ्रिजरेटरमधून घेऊन ते सँडविचेस खाता येतील!"

मंडळी, पडलात ना बुचकळ्यात? रस्त्यावर फ्रीज? आणि त्यातलं अन्न कोणीही मोफत घेऊन जाऊ शकतं? होय, अगदी बरोबर! पोलंडमधल्या अनेक शहरांमध्ये असे कम्युनिटी फ्रिज आहेत. ज्यांच्याकडे गरजेपेक्षा जास्त खाद्यपदार्थ असतील त्यांनी ते या फ्रीजमध्ये आणून ठेवायचे. मग ज्यांना गरज आहे ते लोक त्या फ्रीजमधून हे पदार्थ विनामूल्य घेऊन जातात. मुख्य उद्देश एकच, चांगले खाद्यपदार्थ डस्टबिनमध्ये न जाता गरजू माणसांना खायला मिळावेत.

या संकल्पनेला विशेष चालना मिळाली ती कोरोना काळात. आर्थिक अडचणीत असलेली कुटुंबं आणि घराबाहेर पडणं कठीण झालेल्या वृद्धांसाठी हे

फ्रीज अक्षरशः देवदूत ठरले. अर्थात, या फ्रिजमध्ये खाद्यपदार्थ ठेवण्याचे काही नियम आहेत. आपण स्वतः जे खाऊ शकतो तेच या फ्रीजमध्ये ठेवायचं. घरचं अन्न व्यवस्थित पॅक करून त्यावर पदार्थाचं नाव, घटक आणि तो पदार्थ केला ती तारीख लिहायची. उघडलेले किंवा अर्धवट खाल्लेले पदार्थ ठेवता येत नाहीत. मी राहते त्या शहरात असे आठ फ्रीज आहेत. सामान्य लोक, केटरर, किराणा दुकानं आणि सामाजिक संस्था त्यात नियमितपणे खाद्यपदार्थ ठेवतात. एक महिला तर गेली चार वर्ष रोज न चुकता पाव ठेवते! विशेष म्हणजे सकाळी गच्च भरलेला फ्रीज दुपारपर्यंत रिकामाही होतो.

हे पाहून आनंद होतो, पण अन्नाची गरज समाजात खरंच किती मोठी आहे या विचाराने वाईटही वाटतं. पोलंडमध्ये अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी अशा अनेक कल्पना आहेत. कम्युनिटी स्टोअर्समध्ये मोठ्या दुकानांतून एक्सपायरीच्या जवळ आलेले पदार्थ गोळा करून गरजू लोकांना मोफत दिले जातात. 'झुपा ना मोनसियाकू'सारख्या संस्था उरलेल्या भाज्या आणि इतर खाद्यपदार्थांपासून सूप केलं जातं. ते बेघरांना वाटतात. हिवाळ्यात 'एसओएस' बसमधून वाया जाण्यापासून वाचवलेल्या घटक पदार्थांपासून केलेले गरम खाद्यपदार्थ, वैद्यकीय मदतही गरजूंपर्यंत पोहोचवली जाते.

'फ्रीगॅनिझम' आणि 'फूड-शेअरिंग ग्रुप्स'ही लोकप्रिय होत आहेत. घरात पार्टीचं अन्न उरलं की सोसायटीच्या ग्रुपवर पोस्ट केलं जातं. देणाऱ्याचं अन्न वाचतं, घेणाऱ्याला चविष्ट जेवण मिळतं आणि स्वयंपाकालाही सुट्टी मिळते! सगळ्यांसाठीच अगदी विन-विन सिच्युएशन. पोलंडमध्ये अजूनही अन्न वाया जातं; पण ते कमी करण्यासाठी इथे छोटी-छोटी पावलं प्रामाणिकपणे उचलली जातात. कारण मोठा बदल घडवायचा असेल, तर सुरुवात नेहमीच छोट्या पावलांनी करावी लागते.. हो की नाही?

neenaadate@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन

दोहरा रवैया अपनाना बंद करे अमेरिका

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका हमेशा से ही प्रभावशाली रही है, लेकिन मौजूदा समय में उसकी ईरान नीति कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की मेज पर बैठ रहा है, मध्यस्थता के जरिए संवाद हो रहा है और समझौते की संभावनाएं तलाशने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। आखिर अमेरिका चाहता क्या है, बातचीत या टकराव? दुनिया के सामने यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा दोहरा रवैया किसी भी कूटनीतिक प्रयास की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच करीब तीन घंटे बातचीत होना इस बात का संकेत है कि संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यदि बातचीत संभव है तो उसे गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धमकी और बातचीत एक साथ चलेंगी तो अविश्वास बढ़ेगा। अमेरिका के पास दुनिया की बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है, लेकिन किसी देश को सैन्य कार्रवाई से तबाह करने की चेतावनी देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ईरान का रवैया भी कम कठोर नहीं है। उसने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, विदेशों में जमा अपनी संपत्तियां जारी करने और क्षेत्रीय मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने जैसी शर्तें रखी हैं। इन मांगों पर दोनों देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इनका समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद रखना केवल अमेरिका या ईरान का मामला नहीं है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। होर्मुज से तेल और गैस की बड़ी मात्रा का परिवहन होता है। यहां तनाव बढ़ने का मतलब है ऊर्जा की कीमतों पर दबाव, परिवहन लागत में वृद्धि और महंगाई का बढ़ना। अंततः इसका भुगतान आम आदमी अपनी जेब से करता है। अमेरिका की विदेश नीति में दोहरे मापदंड का सवाल रूस के संदर्भ में भी उठता है। अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध और 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देता है, जबकि खुद रूस से यूरेनियम जैसे सामरिक उत्पाद खरीदता है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, आर्थिक हितों और रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे में किसी भी बड़ी शक्ति द्वारा एकतरफा दबाव वैश्विक व्यापार के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। दुनिया पहले ही युद्धों, आपूर्ति संकट और महंगाई की चुनौतियों से जूझ रही है। अमेरिका को यह समझना होगा कि ताकत का इस्तेमाल और प्रदर्शन दो अलग चीजें हैं। जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व का अर्थ यह नहीं कि हर विवाद में सैन्य विकल्प को सामने रखा जाए। असली नेतृत्व तो तब दिखाई देता है, जब ताकतवर देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल युद्ध रोकने और बातचीत को सफल बनाने में करे। साथ ही ईरान को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। होर्मुज को लंबे समय तक दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। ईरान को भी बातचीत के जरिए व्यावहारिक समाधान की दिशा में बढ़ना होगा। आज दुनिया को एक स्थिर ऊर्जा बाजार, सुरक्षित व्यापार मार्ग और शांतिपूर्ण समाधान चाहिए। अमेरिका को दोहरा रवैया छोड़कर स्पष्ट नीति अपनानी होगी और ईरान को भी कठोर शर्तों से आगे बढ़कर व्यावहारिक रास्ता तलाशना होगा। धमकी से दुनिया डर सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं बन सकती।

सचेत

विवेक मिश्रा

जी-2 के ग्रह चक्रों में फंसने से बचे भारत

भारत की आतिथ्य पूर्ण अगुवाई में ब्रिक्स देशों का 18वां शिखर सम्मेलन, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। प्रत्यास्थता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता जैसे उद्देश्यों के प्रति संकल्पित, यह विश्व के दक्षिणी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का समागम बना था। जहां सर्वसम्मति से 140 बिंदुओं पर आधारित 'नई दिल्ली घोषणा पत्र' को आत्मसात किए जाने की उद्घोषणा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग व सुरक्षा, एकतरफा टैरिफ और प्रतिबंधों का विरोध, सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसे विषय प्रमुखता के साथ रेखांकित हुए थे। ब्रिक्स के साझा हितों पर धुर विरोधी राष्ट्र भी भारतीय नेतृत्व में एकमत दिखे। विषमताओं में विश्व विस्मित करती, यह विलक्षण भारतीय विदेश नीति विश्वव्यापी विश्वास की आधारशिला बन सकती है। यह सत्य है कि यथार्थ के धरातल पर अभी इस सहमति का परिणीति तक पहुंचना बाकी है। मौजूदा चुनौतियों में तात्कालिक आवश्यकताओं को दर्शाता और उनसे निपटने के समाधानों को सुझाता यह घोषणा पत्र, सभी सदस्य देशों की साझा जरूरतों को पूरा करता है। अतः इसके लागू होने में बाधाएं कम ही प्रतीत होती हैं, बशर्ते द्वेष पूर्ण मानवीकृत बाधाओं को न जन्माया जाए। हम कुछ उदाहरणों से इसे समझ सकते हैं, जैसे ब्रिक्स देशों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारदर्शी, समावेशी व जवाबदेही पूर्ण साझा इस्तेमाल का लक्ष्य रखते ही ए.आई. से पैदा होने वाले खतरो के विषय में चर्चाएं तेज हो गई। ए.आई. सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी एंथ्रोपिक के भूतपूर्व पदाधिकारी जेकब कॉक्सोन चिंताएं व्यक्त करते हुए कहतें है कि यह तकनीक 2030 तक इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देगी। तकरीबन यही बात एआई के गॉड फादर माने जाने वाले जॉफ्री हिंटन भी कहते हैं कि आने वाले एक दशक में एआई के कारण इंसानियत के खत्म होने का 10 से 20 फीसदी तक जोखिम है। यहां गौर करने वाली बात है कि जॉफ्री हिंटन कुछ दिन पहले तक इसी जोखिम के लिए दुनिया को अगले 30 साल का समय दे रहे थे। बिल गेट्स, बर्नी सैंडर जैसे नामचीन लोगों को एक साथ चिंताएं नजर आई।

यू.एन. के प्रमुख एंटोनिया गुटेरस ने तो इसे मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। चीन ने ब्रिक्स में मुखरता से ओपन सोर्स ए.आई. की बात रखी थी। ब्रिक्स के विकासशील देशों का तकनीकी सशक्तिकरण चीन के वैश्विक प्रभुत्व को स्थापित करेगा, तब जबकि अमेरिका और यूरोप अपनी ए.आई. विकास यात्रा को संकीर्णता में बांध रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुक्त तकनीक विस्तार नहीं चाहते हैं, जबकि चीन आश्चर्यजनक रूप से खुले दिल को दर्शा रहा है। वहीं बड़ी ए.आई. कंपनियां भी शोध में चीन के विस्तृत कार्यक्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती हैं। ए.आई तकनीक पर अचानक खड़ा किया गया यह शोर दरअसल ब्रिक्स से निकले संयुक्त तकनीकी संकल्पों को बाधित करने का प्रयास मात्र है। ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की खबरें, अमेरिकी औपनिवेश की डॉलर डिक्टेटरशिप (मौद्रिक तानाशाही) को इस प्रकार चुभी कि, अमेरिकी संसद ने पक्ष-विपक्ष का भेद दूर करके, रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों पर 100% टैरिफ बिल पास कर दिया। चीन, टैरिफ वाली ट्रंप नीति के पर पहले ही कतर चुका है, दुर्लभ खनिज अमेरिकी कंपनियों को सुलभता से मिलते रहें, अमेरिकी सरकार यह सबसे पहले सुनिश्चित करेगी। प्रसंस्कृत स्थायी चुम्बकों व यिट्रियम पर चीन का एकाधिकार और इन पर अमेरिकी निर्भरता, चीन पर लगने वाले सभी टैरिफों को स्वतः ही अप्रभावी बना देती है।

टैरिफ का भी सबसे बुरा प्रभाव भारत पर पड़ता है। दूसरी ओर मक्का पैक्ट के साझेदार सऊदी अरब और पाकिस्तान अपने-अपने तरह से भारत के सामने संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान चेतावनियों के बावजूद समुद्री आवागमन के रास्ते पर भारतीय युद्धपोतों से टकराव पैदा कर रहा है, तो सऊदी अरब भारत को तेल आपूर्ति करने में निजी हित तौल रहा है। सऊदी अरब भारत को स्पॉट मार्केट से तेल खरीदने को कहता है, अर्थात ऊंची बोली लगाकर स्वयं की जिम्मेदारी पर, अपने संसाधनों से तेल को भारत लाना। जो परंपरागत एनुअल कॉन्टैक्ट से एकदम उलट है। भारत के लिए सबसे बेहतर व सशक्त विकल्प यही है कि वह आने वाले कुछ वर्षों तक संघर्ष को टाल, उपस्थित परिस्थितियों व संसाधनों में यथासंभव अपनी प्रगति प्रशस्त करता चले। सजगता इतनी रहे कि ब्रिक्स की धुरी पर घूर्णन करते हम अपने इर्द-गिर्द चक्कर लगाते ग्रहों के चक्रों में न फंस जाएं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मुद्दा
प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल

भारतीय पेशेवरों का बदलता रुख

> पिछले एक साल में भारतीय टैलेंट का भूगोल पूरी तरह बदल गया है। अब प्रवृत्ति अमेरिका जाने की नहीं, अमेरिका छोड़ने की है। कोई जर्मनी और नीदरलैंड जा रहा है, कोई दुबई और सिंगापुर, और सबसे महत्वपूर्ण-एक बड़ी संख्या अब गर्व के साथ भारत लौट रही है। यह सिर्फ नौकरी बदलना नहीं है, यह सोच बदलना है। आंकड़े डराते नहीं, जगाते हैं। यह बदलाव हवा-हवाई नहीं है। इसके पीछे ठोस आंकड़े और कठोर अमेरिकी नीतियां हैं। पहला झटका, विश्वविद्यालयों में सन्नाटा छाया। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के आवेदनों में 60 प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी आई है। जो मेधा समंदर पार गई थी, वह अब समंदर पार कर लौट रही है। यह सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं, भारत के विश्वगुरु बनने की प्रस्तावना है।

एक समय था जब भारतीय माता-पिता अपने मेधावी बच्चे को आशीर्वाद देते थे - बेटा, अमेरिका जा।' अमेरिका जाना सफलता का अंतिम प्रमाण-पत्र था। आईआईटी के बाद स्टैनफोर्ड, पीएचडी के बाद सिलिकॉन वैली और फिर ग्रीन कार्ड। इसे ही 'अमेरिकन ड्रीम' कहा जाता था। अब वह ड्रीम डगमगा रहा है और भारतीय पेशेवर जाग रहा है। पिछले एक साल में भारतीय टैलेंट का भूगोल पूरी तरह बदल गया है। अब प्रवृत्ति अमेरिका जाने की नहीं, अमेरिका छोड़ने की है। कोई जर्मनी और नीदरलैंड जा रहा है, कोई दुबई और सिंगापुर, और सबसे महत्वपूर्ण-एक बड़ी संख्या अब गर्व के साथ भारत लौट रही है। यह सिर्फ नौकरी बदलना नहीं है, यह सोच बदलना है।

आंकड़े डराते नहीं, जगाते हैं। यह बदलाव हवा-हवाई नहीं है। इसके पीछे ठोस आंकड़े और कठोर अमेरिकी नीतियां हैं। पहला झटका, विश्वविद्यालयों में सन्नाटा छाया। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के आवेदनों में 60 प्रतिशत की अभूतपूर्व कमी आई है। यह सामान्य गिरावट नहीं है। ऐतिहासिक पलायन है। कभी हार्वर्ड और एमआईटी में दाखिला भारतीय मध्यम वर्ग का सपना था। आज वही वर्ग पूछ रहा है - क्या चार साल बाद वीजा मिलेगा भी या नहीं? दूसरा झटका,एच-1बी की एक लाख डॉलर वाली दीवार खड़ी की गई। अमेरिका ने पिछले वर्ष सितंबर में एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर यानी लगभग 84 लाख रुपये कर दी। यह फीस नहीं, एक तरह की सजा है। इसका असर तत्काल दिखा - महज एक वर्ष में एच-1बी आवेदनों में 10 प्रतिशत की गिरावट। छोटी और मझोली अमेरिकी कंपनियों ने तो भारतीय पेशेवरों को बुलाना ही बंद कर दिया है। अब सिर्फ गूगल-माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज ही यह फीस भर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा झटका, वैज्ञानिकों का पलायन आरंभ हो चुका है। अमेरिका की असली ताकत उसके लैब थे। पर अब लैब खाली हो रहे हैं। भौतिकी में पीएचडी करने वाले विदेशी स्कॉलर्स के अमेरिका छोड़ने की दर 2023-24 में 16 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई।

यह तीन दशक में अमेरिका छोड़ने की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है अर्थात, अमेरिका अब सिर्फ कोडर नहीं, अपने भविष्य के नोबेल विजेताओं को भी खो रहा है। ग्रीन कार्ड के लिए 20 साल का इंतजार, हर चुनाव में आप्रवासियों को विलेन बनाना और कैंपस में बढ़ती असुरक्षा ने इस मोहभंग को पूरा कर दिया है। अब अमेरिका को नुकसान, यूरोप-एशिया को लाभ प्राप्त हो रहा है। जहां अमेरिका ने दरवाजा बंद किया है, वहीं यूरोप और एशिया ने बाहें खोली हैं। जर्मनी ने अपना 'चांस कार्ड' और 'ऑपर्चुनिटी कार्ड' उदार कर दिया है। वह भारतीय इंजीनियरों को बिना जॉब ऑफर के ही 1 साल का वीजा दे रहा है। नीदरलैंड और स्वीडन 30 प्रतिशत टैक्स छूट दे रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब 10 साल का गोल्डन वीजा दे रहे हैं, सिंगापुर ने 'टेक-पास' में भारतीयों का कोटा दोगुना कर दिया है। भारतीय पेशेवर अब समझ गया है कि जीवन स्तर सिर्फ डॉलर से नहीं नापा जाता। यूरोप में काम के बाद जीवन है, एशिया में घर के करीब होने का सुकून है। वहां 5 बजे के बाद ऑफिस बंद होता है और नस्लीय टिप्पणी का डर नहीं सताता। इन सबके पीछे सबसे बड़ी कहानी है-वापसी-कम्प्रोमाइज नहीं,

चॉइस है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे उज्ज्वल अध्याय है - भारत वापसी। पहले अमेरिका से लौटना विफलता माना जाता था। रिश्तेदार पूछते थे- 'नौकरी चली गई क्या?' आज लौटना सबसे बड़ी सफलता है। नैसकॉम के अनुसार रिवर्स ब्रेन ड्रेन में पिछले 18 महीनों में 35-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अब हर सप्ताह ऐसे परिवार उतरते हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को वाला घर बेचकर हैदराबाद में घर ले लिया है। यह वापसी भारत के भविष्य के लिए पांच बड़े वरदान लेकर आई है। पहला, स्वदेशी, स्वरोजगार और स्टार्टअप को नई ऊर्जा। जो युवा अमेजन में प्रोडक्ट मैनेजर था, वह अब इंदौर में एग्री-टेक स्टार्टअप बना रहा है। जो बोस्टन में कैंसर पर रिसर्च कर रहा था, वह अब पुणे में सस्ती दवा बना रहा है। उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है और भारतीय समस्या की समझ। यही आत्मनिर्भर भारत का असली मॉडल है - वैश्विक ज्ञान, भारतीय समाधान। इससे स्वरोजगार बढ़ेगा, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। दूसरा, मातृभूमि से प्रेम की प्रगाढ़ता। यह आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक वापसी है। कोविड ने सिखाया कि अंत में ऑक्सीजन सिलेंडर अमेरिका से नहीं, पड़ोस से आता है। अब युवा पूछ रहा है कि जब बेंगलुरु में ही 2 करोड़ का पैकेज और विश्वस्तरीय जीवन है, तो मैं मां से 14 हजार किलोमीटर दूर क्यों रहूं? यह मातृभूमि के प्रति प्रेम की पुनर्प्रतिष्ठा है। तीसरा, परिवारों के लिए संजीवनी। इसका सबसे मानवीय लाभ हमारे घरों में दिख रहा है।

देश में बैठे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, भाई-बहन के लिए यह किसी आर्थिक पैकेज से बड़ा है। जब बेटा-बहू अमेरिका में होते थे, तो दादा-दादी वीडियो कॉल पर पोते को देखते थे। अब वही दादा-दादी पोते को कहानी सुना रहे हैं। बुजुर्गों का अकेलापन घट रहा है। परिवार में त्योहार फिर से त्योहार लग रहे हैं। यह वह सुख है, जो डॉलर से नहीं खरीदा जा सकता। चौथा, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'कुटुंब प्रबोधन' का जो विचार दिया था कि परिवार ही समाज की प्रथम पाठशाला है, यह वापसी उसी को सशक्त कर रही है। जब परिवार साथ रहता है, तो बच्चे अपनी भाषा, अपने त्योहार, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। यह स्वदेशी जीवन-शैली का पुनर्जागरण है। इससे समाज में वह समरसता आएगी जो वृद्धाश्रमों से नहीं, साथ रहने से आती है। पांचवां, भारत के लिए ग्लोबल अनुभव का मुफ्त उपहार। अमेरिका ने 30 साल तक भारतीयों को ट्रेनिंग दी। अब वह ट्रेंड मैनपावर भारत को मुफ्त में मिल रही है। यह ब्रेन ड्रेन का रिवर्स होना नहीं, ब्रेन गेन का महाविस्फोट है। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए चेतावनी, भारत के लिए अवसर है। अमेरिका ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। 1930 में जब उसने यहूदी वैज्ञानिकों को रोका, तो लाभ अमेरिका को नहीं, जर्मनी को हुआ। आज वही गलती भारतीयों के साथ हो रही है। अमेरिका को समझना होगा कि एक लाख डॉलर की फीस से आप एक भारतीय को रोक सकते हैं, उसके आइडिया को नहीं। वह आइडिया अब बेंगलुरु में स्टार्टअप बनेगा, बर्लिन में बिकेगा और दुनिया पर राज करेगा। भारत के लिए यह अमृतकाल का सबसे बड़ा अवसर है। हमें लौटते हुए भारतीयों के लिए रेड कार्पेट ही नहीं, रेड टेप खत्म करना होगा। उनके बच्चों के लिए स्कूलों में दाखिला, बिजनेस के लिए सिंगल विंडो और रिसर्च के लिए फंडिंग आसान करनी होगी। आज कहने का समय है - 'आओ, देश आकर देश को रोशन करो।' जो मेधा समंदर पार गई थी, वह अब समंदर पार कर लौट रही है। यह सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं, भारत के विश्वगुरु बनने की प्रस्तावना है।

(लेखक कुशभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मानव अपनी दौड़ को सीमित करे

संकलित
दर्शन

सिकन्दर को एक महात्मा ने कहा, तुम भारत को जीत कर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, पहले मैं अफगानिस्तान जीतूंगा। महात्मा ने पूछा फिर? फिर मैं उजबेकिस्तान, रुस आदि देश जीतूंगा। महात्मा ने पूछा फिर? सिकन्दर बोला फिर मैं आराम करूंगा। महात्मा ने कहा अगर तुम इतना सब करके ही आराम करने वाले हो तो आज ही आराम करो तो क्या कठिनाई है? सिकन्दर कोई उत्तर नहीं दे सका। मानव की एक तृष्णा होती है अप्राप्त को प्राप्त करने की। इस तृष्णा के अन्तर्गत जीवन भर वह भाग दौड़ करता ही रहता है, फिर भी जब उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय तक बहुत कुछ अप्राप्त ही रह जाता है। विश्व और विश्व के उपादान इतने विस्तृत है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं कर सकता, यह स्पष्ट होते हुए भी मानव अपनी तृष्णा को निरन्तर बढ़ाता ही रहता है। आराम-सुख-शान्ति-आनन्द ये तत्व तो उसके लिए दुर्लभ ही हो जाते हैं क्यों कि वह तो जीवनभर अर्जन करने में ही जुटा रहता है। और ऐसा करते-करते ही अपना मानव जीवन बिताकर दुनियां से चला जाता है। शास्त्रों का संदेश है। मानव अपनी दौड़ को सीमित करें।

एकाग्रता के बिना मंत्र जप नहीं हो सकता

संकलित
प्रेरणा

एक दिन सरयू नदी के किनारे पर गोस्वामी तुलसीदास प्रवचन दे रहे थे। वे अक्सर यहां प्रवचन देते थे। इस दौरान तुलसीदास जी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते थे। एक दिन तुलसीदास जी आंखें बंद करके जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप आंखें बंद कर किसे याद कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले कि मेरे राम को। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि तो क्या ये जरूरी है कि भगवान के नाम का जप किया जाए? तुलसीदास जी ने कहा कि हां, ये तो बहुत जरूरी है। नाम जप करने से मन काबू में रहता है। जिन लोगों का मन काबू रहता है, वे शांत रहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि जब मैं नाम जप करने बैठता हूं तो मन नहीं लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी बोले कि कई लोगों की ये समस्या है, जप में मन नहीं लगता। इस कारण लोग भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मन लगे या न लगे, हमें जप करते रहना चाहिए। हमारा मन एक भूमि की तरह है। भूमि में बीज बोने पर उससे पौधा जरूर उगता है, बीज उल्टा गिरे या सीधा, पौधा तो उगता ही है। ठीक इसी तरह हमें भी मन में भक्ति का बीज बोते रहना चाहिए। जप के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता। सभी को एकाग्रता की जरूरत है। अशांत मन एकाग्र नहीं हो सकता है। जप करते रहेंगे तो मन शांत रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। जप करने से देर से ही सही, लेकिन इसका सकारात्मक फल जरूर मिलता है।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत की बेमिसाल धरोहर है आयुर्वेद

हमारे देश में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम है स्वास्थ्यवर्धक भविष्य के लिए आयुर्वेद। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। और इसके महत्व दुनिया को बताना भी है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। जब दुनिया भर में वैश्विक महामारी ने कहर मचाया हुआ था, तब भी और अब भी हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों ने हमारे देश की इस धरोहर को अपना कर अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया और अब भी कर रहे हैं। आयुर्वेदिक पद्धति को दुनिया में एक नया आयाम मिला है। *-हरिश बघेल, राजनांदगांव*

ट्रेंड

आयुर्वेद की भूमिका

मोदी सरकार आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़कर इस गौरवशाली विरासत को विश्व में एक नई पहचान दिला रही है। आइए, हम स्वस्थ भारत के निर्माण में आयुर्वेद की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लें।
- **अमित शाह**, केंद्रीय गृहमंत्री

समाज पर असर

राष्ट्रपति की अपील बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अपने पसंदीदा कलाकारों को देखते और सुनते हैं, और उनसे प्रभावित भी होते हैं। इसलिए, कलाकारों का हर संदेश समाज पर असर डालता है। असली स्टार वही है जो सेहत और अच्छे मूल्यों का प्रकाश फैलाता है।
- **शिवराज सिंह चौहान**, केंद्रीय कृषिमंत्री

गहरी संवेदनाएं

पलामू में करम डाली विसर्जन के दौरान नदी में कुछ लोगों के डूबने की खबर बेहद दुखद और मर्माहत करने वाली है। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं मारंग बुरु से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।
- **हेमंत सोरेन**, सीएम, झारखंड

सार्थक जीवन

जरूरी यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि यह है कि क्या आप एक सार्थक जीवन जीते हैं। इसका मतलब पैसा और शोहरत जमा करना नहीं, बल्कि अपने साथी इंसानों की सेवा करना है। - **दलाई लामा**, आध्यात्मिक गुरू

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

प्यूर्तो रिको के दो अखबार बंद करेंगे प्रिंट संस्करण

प्यूर्तो रिको के दो प्रमुख अखबारों ने आने वाले दिनों में अपने प्रिंट संस्करण बंद करके केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध रहने की घोषणा की है। यह कदम दुनियाभर में प्रिंट मीडिया से डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ते रुझान का हिस्सा है। प्यूर्तो रिको की कंपनी जीएफआर मीडिया ने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं की बदलती आदतों को देखते हुए लिया गया है। यह कंपनी 'एल नुएवो डिया' और 'प्रिमेरा होरा' अखबार प्रकाशित करती है। अखबारों के अनुसार, 'प्रिमेरा होरा' का अंतिम प्रिंट संस्करण 24 सितंबर को और 'एल नुएवो डिया' का अंतिम प्रिंट संस्करण 27 सितंबर को प्रकाशित होगा। जीएफआर मीडिया की प्रकाशक मारिया लुइसा फेरे रेंगल ने एक बयान में कहा, 'हम 21वीं सदी के प्यूर्तो रिको के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां आज नौ करोड़ से अधिक प्यूर्तो रिकन लोग द्वीप, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहते हैं। हम हमेशा प्यूर्तो रिको के साथ रहे हैं और आगे भी जहां-जहां प्यूर्तो रिको होगा, वहां मौजूद रहेंगे।' यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि इस फैसले से कितने लोगों की नौकरी जाएगी। जीएफआर मीडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान के अलावा कोई अन्य टिप्पणी नहीं की जाएगी।

ऑफ बीट

बोलीविया के जंगल में मिली नई प्रजाति की नन्ही बिल्ली

बोलीविया के जंगलों में रहने वाली एक नन्ही जंगली बिल्ली इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बिल्ली को 'टिग्रिनो' नाम दिया गया है। शरीर पर तेंदुए जैसे बड़े धब्बों वाली यह छोटी जंगली बिल्ली बहुत जल्द तनाव में आ जाती है। टिग्रिनो 'लेपर्डस टिलकायो' प्रजाति की जंगली बिल्ली है। वैज्ञानिकों ने एक सदी से भी अधिक समय बाद जंगली बिल्लियों की किसी नयी जीवित प्रजाति की पहचान की है। टिग्रिनो की सिर से पूंछ तक लंबाई महज 18 इंच (46 सेंटीमीटर) और वजन करीब तीन पाउंड (1.4 किलोग्राम) है। आकार में वह एक सामान्य बिल्ली से भी छोटी है। शोध पत्रिका ''करंट बायोलॉजी' में इस खोज से संबंधित अध्ययन को प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हुई। टिग्रिनो को देखने की उत्सुकता में बोलीविया के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ दूसरे देशों से भी लोग 'सेंडा वर्दे वन्यजीव अभयारण्य' पहुंच रहे हैं। टिग्रिनो 2017 से इसी अभयारण्य में है। उस साल एक परिवार उसे वहां लेकर आया था। परिवार ने उसे घरेलू बिल्ली की तरह पालने की कोशिश की, लेकिन उसे यह रास नहीं आया। अभयारण्य के सह-संस्थापक मार्सेलो लेवी ने कहा, 'कुछ ही दिनों में टिग्रिनो संरक्षण की दूत बन गई है।'

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here